विक्रम संवत् 2081 ▪ पौष/ माघ मास (11) ▪ 01 जनवरी 2025 ▪ मूल्य : 23 रु.

चैवेति

गणतंत्र दिवस की
शुभकामनाएं

आर.एन.आई. पंजीयन क्र.017261/69, डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल/297/2024-26, पृष्ठ संख्या-44, प्रकाशन दिनांक प्रत्येक माह की 10 तारीख, पोस्टिंग प्रत्येक माह की 15 एवं 20 तारीख

केन-बेतवा लिंक

बुंदेलखंड में समृद्धि और खुशहाली

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2001 के संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

- भाजपा अध्यक्ष श्री जे.पी. नड्डा जी ने एनडीए नेताओं की बैठक में भाग लिया।

- भाजपा अध्यक्ष श्री जे.पी.नड्डा जी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई जी की 100वीं जयंती पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने "द साबरमती रिपोर्ट" फिल्म देखी।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने रोजगार मेला में 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधान मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की।

अनुक्रमणिका

» **संपादकीय** • संजय गोविन्द खोचे 04

▪ संविधान से सुशासन

» **कवर स्टोरी** 05

▪ केन-बेतवा लिंक से होगी बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली की बयार

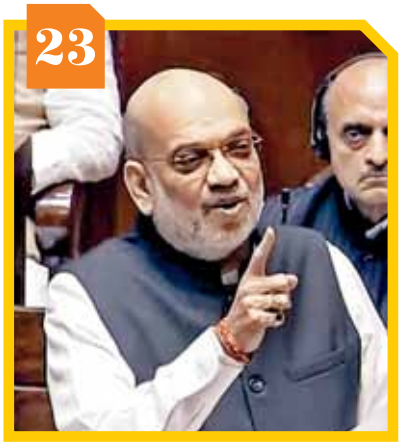

▪ **उपलब्धियों भरा एक वर्ष** 09

» साकार हो रहा अटलजी का स्वप्न- डॉ. मोहन यादव...

▪ **आलेख** 12

» भागीरथ, भोज, छत्रसाल की अटल विरासत के संवाहक मोदी जी...

▪ **संविधान दिवस विशेष** 14

» भारत की एकता का आधार हमारा संविधान...

» मोदी सरकार संघवाद का सम्मान करती है : जगत प्रकाश नड्डा...

» मोदी सरकार ने मातृशक्ति को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान...

▪ **सुशासन का अटल दिवस** 25

» राष्ट्र निर्माण के 'अटल' आदर्श की शताब्दी- नरेन्द्र मोदी...

» लोक कल्याण के लिए किया जाने वाला शासन है सुशासन

▪ **संगठन पर्व** 29

» बूथ समितियों का गठन और बूथों का डिजिटलाइजेशन...

▪ **आलेख** 30

» गीता जयंती: सद्कर्म, स्व-धर्म और सच्चे कर्तव्य पथ की प्रेरणा ...

▪ **गीता जयंती** 32

» विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशन गीता प्रेस

▪ **मन की बात** 34

» महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश...

▪ **त्यौहार** 38

» सूर्य नारायण का पर्व है मकर संक्रान्ति...

▪ **पुण्यतिथि** 39

» भारत को विश्वगुरु बनना है...

▪ **विचार प्रवाह** 40

» भारत के राष्ट्रवाद की अवधारणा...

• मुख्य व्रत-त्यौहार

1. चन्द्रदर्शन 3. विनायकी चतुर्थी व्रत 10. पुत्रदा एकादशी व्रत 11. प्रदोष व्रत, रोहिणी व्रत 12. पाक्षिक प्रतिक्रमण 13. स्नानदान व्रत, पौषी पूर्णिमा, षोडषकारण व्रत प्रारम्भ 14. मकर संक्रांति पुण्यकाल 16. कुमुहूर्त्ता उत्तर्या 17. संकटा गणेश तिल चौथ व्रत 25. षट्तिला एकादशी व्रत 26. तिल द्वादशी 27. प्रदोष व्रत, शिव चतुर्दशी व्रत, मेरूत्तेरस, आदिनाथ मोक्ष क. 28. ऋषभदेव निर्वाणोत्सव 29. स्ना. दा. श्रा.,मौनी अमावस 30. गुप्त नवरात्रारम्भ 31. चन्द्रदर्शन

• मुख्य जयंती-दिवस

6. गुरू गोकुलदास जयंती 7. राजिम भक्तिन माता जयंती 10. विश्व हिन्दी दिवस 12. महर्षि महेश योगी जयंती 13. तिलका मांझी बलिदान दिवस, मोती माता मेला,छेरछेरा 15. थल सेना दिवस 20. अ.भा. मारवाड़ी युवा मंच स्थापना दि. 21. वीर हेमूकालाणी शहीद दिवस 28. लाला लाजपतराय जयंती 30. महात्मा गांधी पुण्यतिथि, शहीद स्मृति दिवस 31. अवतार मेहेरबाबा की अमरतिथि

वर्ष-56, अंक : 11, भोपाल, जनवरी 2025

हमारे प्रेरणास्रोत

पं. दीनदयाल उपाध्याय

ध्येय बोध

समृद्धि का आधार धर्म है। इस संबंध में हम पाते हैं कि हमारा आधार धर्म, अभावात्मक नहीं है। हमारे यहां अभाव का नहीं संयम का विचार किया गया है। सादा जीवन का विचार किया गया है, धन पैदा किया तो उसका उपयोग धर्मानुसार करना चाहिए।

- पं. दीनदयाल उपाध्याय

सचिव, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
संजय गोविंद खोचे*

सहायक सम्पादक
पं. सलिल मालवीय

व्यवस्थापक
योगेन्द्रनाथ बरतरिया
मोबा. नं. 09425303801

पं. दीनदयाल विचार प्रकाशन म.प्र. के लिये मुद्रक एवं प्रकाशक संजय गोविंद खोचे द्वारा पं. दीनदयाल परिसर, ई-2, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016 से प्रकाशित

एवं एम. पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेस-II, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा - 201 305 से मुद्रित.

संपादकीय पता
पं. दीनदयाल परिसर,
ई-2, अरेरा कालोनी, भोपाल- 462016
e-mail:charevetibpl@gmail.com
web site:www.charaiveti.org

मूल्य- तेईस रुपये

*समाचार चयन के लिए पी.आर.बी.एक्ट के तहत जिम्मेदार

संविधान से सुशासन

लोकतंत्र, संविधान व सुशासन यह तीन शब्द नहीं, इन्हीं तीन खम्बों पर भारत खड़ा है। भारत का इतिहास, भारत की व्यवस्था, भारत का लोकतंत्र समृद्ध रहा है। जब इन तथ्यों पर चर्चा होती है तो भारत का गौरवशाली इतिहास सामने आ जाता है। भारत में लोकतंत्र, भारत की पुरानी परंपरा है, भारत में कई गणतंत्र हुआ करते थे, महत्वपूर्ण विषयों पर देश के विद्वान चर्चा किया करते थे। लोकतंत्र व संविधान की भावना के अनुरूप देश व जनता के हित में निर्णय हुआ करते थे। यही तो सुशासन है, जब जनता द्वारा जनता के लिए निर्णय होता है तो देश और मजबूत होकर सामने आता है। भारत का जन्म 1947 में नहीं, भारत तो हजारों साल से अपनी संस्कृति, इतिहास, सनातन परंपरा के प्रति सजग रहा है।

1947 में तो भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 299 सदस्यों की संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन के गहन विचार विमर्श, चर्चा के उपरांत इसे अंतिम रूप दिया। संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप भारत संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संप्रभुता संपन्न- का तात्पर्य जनता द्वारा चुनी गई सरकार द्वारा शासित देश, जो बिना दबाव के जनता के हित में निर्णय लेने हेतु है, पर संविधान की यह भावना भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने चकनाचूर करने में देर नहीं की। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री थे। जनता के हित में निर्णय लेने की जगह स्वयं के हित में, स्वयं के राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए संविधान की भावना को चकनाचूर करने में उन्होंने देर नहीं लगाई और पंडित जवाहरलाल की परंपरा को श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी व जिनने संविधान की शपथ भी नहीं ली वह केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा पारित निर्णय को सार्वजनिक रूप से फाड़ते दिखाई दिए और तत्कालीन प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद के निर्णय को वापस लेने के लिए बाध्य कर दिए गए। संविधान नागरिकों की सामाजिक व आर्थिक समानता को सुनिश्चित करता है। जाति, रंग, नस्ल, लिंग,धर्म या भाषा के कारण कोई भेदभाव नहीं होता है। सभी को समान अवसर, धन संग्रहण कुछ हाथों में न होकर सभी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो यही सरकार का कार्य है। इस भावना की हत्या करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। धर्म विशेष को वोट बैंक बनाओ, सभी को समान स्तर तो छोड़ो, बस परिवार की राजनीति चलाओ, आर्थिक समानता की बात ही नहीं, जो शोषित वर्ग है उसे उसके हाल पर छोड़ दो। और गरीबी हटाओ का नारा जितनी जोर से लगा सकते हो, लगाओ। पर करो कुछ मत यही काँग्रेस की नीति थी।

यह तो नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसमें 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। और फिर वापस न पीछे चले जाएं इस बात की चिंता सरकार कर रही है। यही है संविधान की भावना के अनुरूप सरकार का निर्णय, यही है सुशासन।

पंथनिरपेक्ष-सभी पंथों के लिए समानता सुनिश्चित करता है। पर इस भावना पर भी कड़ा प्रहार करने में काँग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वोट बैंक के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का कितनी बार प्रयास किया गया। कोर्ट से उल्टे पैर वापस भी आना पड़ा, पर वोट बैंक की राजनीति संविधान की भावना पर भारी पड़ती दिखाई दी। नरेंद्र मोदी की सरकार ही है जिसने संविधान की भावना के अनुरूप सभी वर्गों के गरीब बच्चों को, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया। वो भी बिना जाति, धर्म के भेदभाव के। यह है संविधान की भावना के अनुरूप कार्य। यही है सुशासन।

संसद-विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की। बिना जाति, धर्म के भेदभाव के, 80 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री द्वारा फ्री अनाज की व्यवस्था की गई। हर घर जल योजना के अन्तर्गत 15,13,18,817 घरों को बिना भेदभाव के नल से जल पहुँचाया गया। एक देश-एक कर, जीएसटी लागू कर करों के भेदभाव व करों के मकड़ जाल से मुक्ति दिलाई गई और एक समान कर व्यवस्था के अंतर्गत अब तक 99,67,551 करोड़ रुपए का कर संग्रह, स्वामित्व योजना के अंतर्गत 163,00,000 प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण हो चुका है। वो भी बिना जाति, धर्म के भेदभाव के। 5,53,148 गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं बिना भेदभाव के। 11,64,88,439 घरों में टॉयलेट बनाए जा चुके हैं। बिना भेदभाव के। 59,59,12,156 किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकरण किया जा चुका है, बिना भेदभाव के। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 2,98,41,154 घरों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, बिना भेदभाव के। 7,19,42,295 मुफ्त उपचार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, बिना भेदभाव के। एक लंबी सूची बनाई जा सकती है।

मोदी सरकार जनता की समान रूप से चिंता, सहयोग व अंतिम लाभार्थी तक लाभ सुनिश्चित करती है, यही है संविधान निर्माताओं के प्रति सम्मान की भावना,जनता की हित के लिए सरकार इसे ही कहते हैं।

बुंदेलखंड को केन-बेतवा लिंक परियोजना की सौगात मिली, अब बुंदेलखंड सूखा क्षेत्र नहीं हरा भरा क्षेत्र होगा। पीने का पानी, सिंचाई का पानी, उद्योग धंधों के लिए पानी, निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी, वह भी बिना भेदभाव के। डबल इंजन की सरकार संविधान और सुशासन के लिए कृत संकल्पित है। इस सरकार के कारण मध्य प्रदेश को नदियों को जोड़ने की दो परियोजनाओं का लाभ मिलेगा। राजस्थान के साथ पार्वती-काली सिंध-चंबल तथा मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश के साथ केन-बेतवा लिंक परियोजना के द्वारा कई नदियों का जोड़ बनेगा। इन दोनों ही परियोजनाओं का बड़ा लाभ मध्यप्रदेश को होने जा रहा है।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई जी का सपना था, नदियों को जोड़कर भविष्य की जल आपूर्ति की चिंता से जनता को मुक्ति दिलाना, यही तो सुशासन है। जिसमें आज की चुनौतियों के साथ-साथ आने वाले कल की चुनौतियों को समझ कर उससे निपटने की तैयारी करना व जनता को सरकार के सामने मांग न करनी पड़े हर लाभार्थी तक लाभ को सुनिश्चित करना।

यही एक महत्वपूर्ण कारक है जो भाजपा व दूसरे दलों में अंतर खड़ा कर रहा है। 60 वर्षों के शासन व भाजपा के 11 वर्षों के शासन को जनता अनुभव कर रही है। 60 वर्षों के शासन में संविधान में संशोधन होते थे स्वयं की कुर्सी को बचाने के लिए, वोट बैंक को खुश करने के लिए, अपनों को लाभ पहुंचाने के लिए। भाजपा सरकार में संशोधन होते हैं-धारा 370 को दफन करने के लिए, तीन तलाक से मुक्ति के लिए, गरीब वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा के लिए, महिलाओं को विधानसभा-संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए।

दोनों के कार्यकालों के विश्लेषण से स्पष्ट है भाजपा ही संविधान की भावना का सम्मान करती है। संविधान निर्माताओं के प्रति अगाध श्रद्धा, विश्वास व्यक्त करती है। देश को सुशासन प्रदान करने में केवल भाजपा ही सक्षम है। ▪

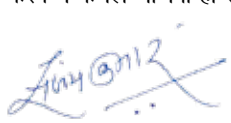

(संजय गोविन्द खोचे)
सम्पादक

केन-बेतवा लिंक से होगी बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली की बयार

- **प्रधानमंत्री ने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया।**
- **प्रधानमंत्री ने 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की नींव रखी।**
- **प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर उनकी याद में एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया।**
- **केन-बेतवा जोड़ो परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली के नए द्वार खोलेगी।**
- **भारत के इतिहास में बीते दशक को जल सुरक्षा और जल संरक्षण के अभूतपूर्व दशक के रूप में याद किया जाएगा।**

एमपी में विकास को एक नई गति मिली है। हजारों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का दौधन बांध का शिलान्यास भी हुआ है।

ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, उसका भी लोकार्पण हुआ है और ये मध्यप्रदेश का पहला floating plant है।

- **केंद्र देश-विदेश से आने वाले सभी पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने का भी निरंतर प्रयास कर रहा है।**

मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार का एक साल पूरा हुआ है। इस एक वर्ष में एमपी में विकास को एक नई गति मिली है। हजारों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं की शुरूआत हुई है। ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का दौधन बांध का शिलान्यास भी हुआ है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, उसका भी लोकार्पण हुआ है और ये मध्यप्रदेश का पहला floating plant है।

भारत रत्न अटल जी के जन्म के 100 साल हो रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये

मध्य प्रदेश, टूरिज्म के मामले में हमेशा से अव्वल रहा है। पर्यटन एक ऐसा सेक्टर है, जो युवाओं को रोजगार भी देता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी ताकत देता है।

अब जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, तो दुनिया में भारत को लेकर जिज्ञासा बढ़ी है। आज दुनिया भारत को जानना चाहती है, समझना चाहती है। इसका बहुत अधिक फायदा मध्य प्रदेश को होने वाला है।

पर्व सुशासन की सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। अटल जी ने वर्षों वर्षों तक अनेक कार्यकर्ताओं को सिखाया है, संस्कारित किया है। देश के विकास में अटल जी का योगदान हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अमिट रहेगा। मध्यप्रदेश में 1100 से अधिक अटल ग्राम सेवा सदन के निर्माण का काम शुरू हो रहा है, इसके लिए पहली किस्त भी जारी की गई है। अटल ग्राम सेवा सदन गांवों के विकास को नई गति देंगे।

हमारे लिए सुशासन दिवस सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम भर नहीं है। गुड गर्वनेंस, सुशासन, भाजपा सरकारों की पहचान है। देश की जनता ने लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में भी, लगातार भाजपा को चुन रहे हैं, इसके पीछे सुशासन का भरोसा ही सबसे प्रबल है। जब आजादी के 75 साल हो चुके हैं तो एक बार evaluation किया जाए। 100-200 विकास के, जनहित के, गुड गर्वनेंस के पेरामीटर निकाले जाएं और फिर जरा हिसाब लगाएं कि कांग्रेस सरकारें जहां होती हैं वहां क्या काम होता है, क्या परिणाम होता है। जहां left वालों ने सरकार चलाई, कम्युनिस्टों ने सरकार चलाई, वहां क्या हुआ। जहां परिवारवादी पार्टियों ने सरकार चलाई, वहां क्या हुआ। जहां मिली जुली सरकारें चलीं वहां क्या हुआ और जहां जहां भाजपा को सरकार चलाने का मौका मिला, वहां क्या हुआ।

देश में जब जब भाजपा को जहां जहां भी सेवा करने का अवसर मिला है, हमनें पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ कर जनहित के, जनकल्याण के और विकास के कामों में सफलता पाई है। निश्चित मानदंडों पर मूल्यांकन हो जाए, देश देखेगा कि हम जनसामान्य के प्रति कितने समर्पित हैं। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए हम दिन रात पसीना बहाते हैं। जिन्होंने देश के लिए खून बहाया, उनका रक्त बेकार न जाए हम अपने पसीने से उनके सपनों को सींच रहे हैं। और सुशासन के लिए अच्छी योजनाओं के साथ ही उन्हें अच्छी तरह लागू करना भी जरूरी है। सरकार की योजनाओं का लाभ कितना पहुंचा, ये सुशासन का पैमाना होता है। अतीत में कांग्रेस सरकारें घोषणाएं करने में माहिर हुआ करती थी। घोषणाएं करना, फीता काटना, दीया जलाना, अखबार मे तस्वीर छपवा देना, उनका काम वहीं पूरा हो जाता था। और उसका फायदा कभी भी लोगों को नहीं मिल पाता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं प्रगति के कार्यक्रम के एनालिसिस में पुराने प्रोजेक्ट देखता हूं। मैं तो हैरान हूं 35-35, 40-40 साल पहले जिसके शिलान्यास हुए, बाद में वहां एक इंच भी काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारों की ना तो नीयत थी और ना ही उनमें योजनाओं को लागू करने की गंभीरता थी।

आज हम पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना का लाभ देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को किसान सम्मान निधि के 12 हजार रुपए मिल रहे हैं। ये भी तभी संभव हुआ, जब जनधन बैंक खाते खुले। यहां एमपी में ही लाड़ली बहना योजना है। अगर हम बहनों के बैंक खाते ना खुलवाते, उनको आधार और मोबाइल से ना जोड़ते, तो क्या ये योजना लागू हो पाती? सस्ते राशन की योजना तो पहले से भी चलती थी, लेकिन गरीब को राशन के लिए भटकना पड़ता था। अब आज देखिए, गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है, पूरी पारदर्शिता

से मिल रहा है। ये तभी हुआ, जब टेक्नॉलॉजी लाने के कारण, फर्जीवाड़ा बंद हुआ। जब एक देश, एक राशन कार्ड जैसी देशव्यापी सुविधाएं लोगों को मिलीं।

सुशासन का मतलब ही यही है, कि अपने ही हक के लिए नागरिक को सरकार के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़ें। और यही तो सैचुरेशन की, शत-प्रतिशत लाभार्थी को, शत-प्रतिशत लाभ से जोड़ने की हमारी नीति है। सुशासन का यही मंत्र, भाजपा सरकारों को दूसरों से अलग करता है। आज पूरा देश इसे देख रहा है, इसलिए बार-बार भाजपा को चुन रहा है।

जहां सुशासन होता है, वहां वर्तमान चुनौतियों के साथ ही, भविष्य की चुनौतियों पर भी काम किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से, देश में लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकारें रहीं। कांग्रेस, गवर्नमेंट पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है लेकिन गवर्नेंस का उससे छत्तीस का नाता रहा है। जहां कांग्रेस, वहां गवर्नेंस हो नहीं सकती। इसका बहुत बड़ा खामियाजा दशकों तक बुंदेलखंड के लोगों ने भी भुगता है। पीढ़ी दर पीढ़ी, किसानों, माताओं-बहनों ने बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष किया है। ये हालात क्यों बने? क्योंकि कांग्रेस ने कभी जल संकट के स्थाई समाधान के बारे में सोचा ही नहीं।

भारत के लिए नदी जल का महत्व क्या है, हिन्दुस्तान में किसी को पूछ लीजिए, देश आजाद होने के बाद सबसे पहले जल शक्ति, पानी का सामर्थ्य, पानी के लिए दूरदर्शी आयोजन, इसके विषय में किसने सोचा था? किसने काम किया था? पत्रकार बंधू भी जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों, जो सच्चाई है उसको दबा कर रखा गया, उसे छिपा कर के रखा गया और एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। देश आजाद होने के बाद भारत की जलशक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सबकी दूरदृष्टि किसी एक महापुरूष को क्रेडिट जाती है, तो उस महापुरूष का नाम है बाबा साहेब आंबेडकर। भारत में जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनीं, इन परियोजनाओं के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का ही विजन था। जो केंद्रीय जल आयोग है, इसके पीछे भी डॉक्टर आंबेडकर के ही प्रयास थे। लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए बाबा साहेब को श्रेय नहीं दिया, किसी को पता तक चलने नहीं दिया। कांग्रेस इसके प्रति कभी भी गंभीर नहीं रही। सात दशक बाद भी देश के अनेक राज्यों के बीच पानी को लेकर कुछ ना कुछ विवाद है। जब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, कांग्रेस का ही शासन था, तब ये विवाद आसानी से सुलझ सकते थे। लेकिन कांग्रेस की नीयत खराब थी इसलिए उसने कभी भी ठोस प्रयास नहीं किए।

जब देश में अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने पानी से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए गंभीरता से काम शुरू किया था। लेकिन 2004 के बाद, उनके प्रयासों को भी जैसे ही अटल जी की सरकार गई, वो सारी योजनाएं, सारे सपने, ये कांग्रेस वालों ने आते ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब हमारी सरकार देशभर में नदियों को जोड़ने के अभियान को गति दे रही है। केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का सपना भी अब साकार होने वाला है। केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली के नए द्वार खुलेंगे। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह और सागर सहित मध्यप्रदेश के 10 जिलों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।

उत्तरप्रदेश में जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, उसके बांदा, महोबा, ललितपुर और झांसी जिलों को फायदा होने वाला है।

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना है, जहां नदियों को जोड़ने के महाअभियान के तहत दो परियोजनाएं शुरू हो गई है। राजस्थान में पार्वती-कालीसिंध-चम्बल और केन-बेतवा लिंक परियोजनाओं के माध्यम से कई नदियों का जुड़ना तय हुआ है। इस समझौते का बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को भी होने जा रहा है।

21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है- जल सुरक्षा। 21वीं सदी में वही देश आगे बढ़ पाएगा, वही क्षेत्र आगे बढ़ पाएगा, जिसके पास पर्याप्त जल होगा और उचित जल प्रबंधन होगा। पानी होगा तभी खेत-खलिहान खुशहाल होंगे, पानी होगा तभी उद्योग-धंधे फलेंगे फूलेंगे, और गुजरात, जहां के ज्यादातर हिस्सों में साल में ज्यादातर समय सूखा ही पड़ता था। लेकिन मध्य प्रदेश से निकली मां नर्मदा के आशीर्वाद ने, गुजरात का भाग्य बदल दिया। एमपी के भी सूखा प्रभावित इलाकों को पानी के संकट से मुक्त करना, मैं अपना दायित्व समझता हूं। इसलिए मैंने बुंदेलखंड की बहनों से, यहां के किसानों से वादा किया था कि आपकी मुश्किलें कम करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करुंगा। इसी सोच के तहत, बुंदेलखंड में पानी से जुड़ी करीब 45 हजार करोड़ रुपए की योजना हमने बनाई थी। हमने मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की भाजपा सरकारों को निरंतर प्रोत्साहित किया। और अब केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत दौधन बांध का भी शिलान्यास हो गया है। इस बांध से सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहर निकलेगी। बांध का पानी करीब 11 लाख हेक्टेयर भूमि तक पहुंचेगा।

बीता दशक, भारत के इतिहास में जल-सुरक्षा और जल संरक्षण के अभूतपूर्व दशक के रूप में याद किया जाएगा। पहले की सरकारों के दौरान पानी से जुड़ी जिम्मेदारियां, अलग-अलग विभागों के बीच बंटी हुई थीं। हमने इसके लिए जलशक्ति मंत्रालय बनाया। पहली बार, हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरु किया गया। आजादी के बाद के 7 दशक

में, सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास ही नल से जल नल कनेक्शन था। बीते 5 वर्षों में 12 करोड़ नए परिवारों तक हमने नल से जल पहुंचाया है। इस योजना पर अभी तक साढ़े 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा चुका है। जल जीवन मिशन का एक और पक्ष है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। वो है, पानी की गुणवत्ता की जांच। पीने के पानी को टेस्ट करने के लिए देशभर में 2100 वॉटर क्वालिटी लैब बनाई गई हैं। पानी को टेस्ट करने के लिए गांवों में 25 लाख महिलाओं को ट्रेन किया गया है। इससे देश के हजारों गांव जहरीला पानी पीने की मजबूरी से मुक्त हो चुके हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, बच्चों को, लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए ये कितना बड़ा काम हुआ है।

2014 से पहले देश में ऐसी 100 के करीब बड़ी सिंचाई परियोजनाएं थीं, जो कई दशकों से अधूरी पड़ी हुई थीं। हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इन पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करवा रहे हैं। हम सिंचाई के आधुनिक तौर-तरीकों का भी उपयोग बढ़ा रहे हैं। पिछले 10 साल में करीब-करीब एक करोड़ हेक्टेयर भूमि को माइक्रो इरिगेशन की सुविधा से जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल में करीब 5 लाख हेक्टेयर भूमि माइक्रो इरिगेशन से जुड़ी है। बूंद-बूंद पानी का सदुपयोग हो इसे लेकर लगातार काम हो रहा है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का अभियान भी चलाया गया। इसके तहत देशभर में 60 हजार से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए। हमने देशभर में जल शक्ति अभियान-कैच द रेन भी शुरु किया है। देशभर में 3 लाख से अधिक री-चार्ज वेल बन रहे हैं। और इन अभियानों का नेतृत्व जनता जनार्दन खुद कर रही है, शहर हो या गांव, हर क्षेत्र के लोग इनमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश सहित देश के जिन राज्यों में भूजल स्तर सबसे कम था, वहां अटल भूजल योजना चलाई जा रही है।

मध्य प्रदेश, टूरिज्म के मामले में हमेशा से अव्वल रहा है। पर्यटन एक ऐसा सेक्टर है, जो युवाओं को रोजगार भी देता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी ताकत देता है। अब जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, तो दुनिया में भारत को लेकर जिज्ञासा बढ़ी है।

आज दुनिया भारत को जानना चाहती है, समझना चाहती है। इसका बहुत अधिक फायदा मध्य प्रदेश को होने वाला है। एक अमेरिकी अखबार में एक रिपोर्ट छपी है कि मध्य प्रदेश को दुनिया के दस सबसे आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बताया गया है। दुनिया के टॉप 10 में एक मध्य प्रदेश।

केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि देश और विदेश के सभी पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ें, यहां आना-जाना आसान हो। विदेशी पर्यटकों के लिए ई-वीजा जैसी योजनाएं बनाई हैं। भारत में जो हैरिटेज और वाइल्डलाइफ टूरिज्म है, उसको विस्तार दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में तो इसके लिए अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। खजुराहो के इस क्षेत्र में ही देखिए, यहां इतिहास की, आस्था की, अमूल्य धरोहरें हैं। कंदरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, चौसठ योगिनी मंदिर अनेक आस्था स्थल हैं। भारत के पर्यटन का प्रचार करने के लिए हमने देशभर में जी-20 की बैठकें रखी थीं।

केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत, मध्य प्रदेश को सैकड़ों करोड़ रुपए दिए गए हैं। ताकि यहां इको टूरिज्म सुविधाओं का, पर्यटकों के लिए नई सुविधाओं का निर्माण हो सके।

साँची और अन्य बौद्ध स्थलों को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जा रहा है। गांधीसागर, ओंकारेश्वर डेम, इंदिरा सागर डेम, भेड़ा घाट, बाणसागर डेम, ये इको सर्किट का हिस्सा हैं। खजुराहो, ग्वालियर, ओरछा, चंदेरी, मांडू, ऐसे स्थलों को हेरिटेज सर्किट के रूप में कनेक्ट किया जा रहा है। पन्ना नेशनल पार्क को भी वाइल्डलाइफ सर्किट से जोड़ा गया है। बीते वर्ष तो पन्ना टाइगर रिजर्व में ही करीब ढाई लाख पर्यटक आए हैं। यहां जो लिंक नहर बनाई जाएगी, उसमें पन्ना टाइगर रिजर्व के जीवों का भी ध्यान रखा गया है।

पर्यटन बढ़ाने के ये सारे प्रयास, स्थानीय अर्थव्यस्था को बड़ी ताकत देते हैं। जो पर्यटक आते हैं, वे भी यहां का सामान खरीदते हैं। यहां ऑटो, टैक्सी से लेकर होटल, ढाबे, होम स्टे, गेस्ट हाउस, सभी को फायदा पहुंचता हैं। इससे किसान को भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि दूध-दही से लेकर फल-सब्जी तक हर चीज के उन्हें अच्छे दाम मिलते हैं।

बीते दो दशकों में मध्य प्रदेश ने अनेक पैमानों में शानदार काम किया है। आने वाले दशकों में मध्य प्रदेश, देश की टॉप इकॉनॉमीज में से एक होगा। इसमें बुंदेलखंड की बहुत बड़ी भूमिका होगी। विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बनाने में बुंदेलखंड का रोल अहम होगा। डबल इंजन की सरकार इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करती रहेगी। ▪

साकार हो रहा अटलजी का स्वप्न- डॉ. मोहन यादव

- **संसाधनों के बेहतर उपयोग से हर वर्ग का विकास कर रही मध्यप्रदेश सरकार।**
- **साइबर तहसीलों से पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बना मध्यप्रदेश।**
- **मध्यप्रदेश में सबसे तेज गति से खुल रहे नए मेडिकल कॉलेज।**

पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वप्न था कि यदि देश की नदियों को जोड़ दिया जाए, तो देश के अनेक हिस्सों से जल संकट को समाप्त किया जा सकता है। अटलजी के सपने को साकार करने के लिए मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश सरकारों ने केन-बेतवा नदियों को जोड़ने का निर्णय लिया। सरकार ने इस परियोजना में आ रही जटिलताओं को दूर किया। इस परियोजना से मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के 11 जिलों को लाभ होगा। सिंचाई के अलावा पेयजल का संकट भी खत्म होगा। कभी सूखे कहे जाने वाले बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। इसी तरह सरकार राजस्थान सरकार के साथ चंबल-काली सिंध-पार्वती नदियों को जोड़ने के लिए भी प्रयास कर रही हैं, जो अब अंतिम चरण में हैं। इन नदियों को जोड़े जाने से पश्चिमी मध्यप्रदेश के जिलों को न सिर्फ सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, बल्कि इस क्षेत्र में उद्योगों का भी विकास होगा।

सिंहस्थ पर्व के दौरान उज्जैन आने वाले श्रद्धालु क्षिप्रा के पवित्र जल से स्नान कर सकें, इसके लिए क्षिप्रा में मिलने वाली कान्ह नदी के पानी को उज्जैन से 20 कि.मी. पहले ही रोक दिया है और क्षिप्रा को रीचार्ज करने की व्यवस्था की जा रही है। जल संसाधन के बेहतर उपयोग के लिए आने वाले समय में प्रदेश की अन्य नदियों को भी जोड़ने के कदम बढ़ाएंगे।

सरकार ने किसानों की समृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दे रहे हैं, तथा समर्थन मूल्य 4892 रुपये प्रति क्विंटल पर सोयाबीन की खरीदी की जा रही है। किसानों की भूमि संबंधी समस्याओं को समाप्त करने के लिए हमने ई-पंजीयन, नामांतरण, बंटवारे आदि की व्यवस्था की है। कृषि उत्पादन में मध्यप्रदेश लगभग अधिकतम सीमा के निकट पहुंच रहा है। इसलिए भविष्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से समझौता किया है। सरकार सिंचित भूमि के रकबे को लगातार बढ़ा रही है। इसके साथ ही बिजली के मामले में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार शुरुआत में 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने जा रही है। आगे चलकर 40 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने की योजना है। वहीं, श्रीअन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति क्विंटल 1000 रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि एवं 3900 रुपये प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि दी जा रही है। कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य 4290 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

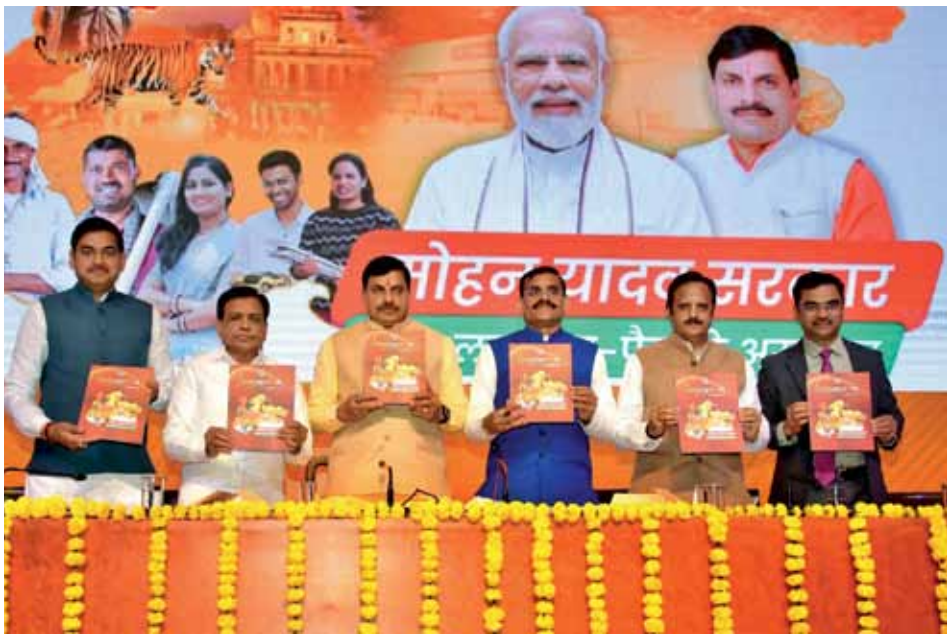

अटलजी के सपने को साकार करने के लिए मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश सरकारों ने केन-बेतवा नदियों को जोड़ने का निर्णय लिया। सरकार ने इस परियोजना में आ रही जटिलताओं को दूर किया।

इस परियोजना से मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के 11 जिलों को लाभ होगा। सिंचाई के अलावा पेयजल का संकट भी खत्म होगा। कभी सूखे कहे जाने वाले बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होगा।

अन्तर्द्वन्द्व

अटल बिहारी वाजपेयी

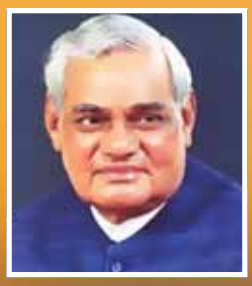

क्या सच है, क्या शिव, क्या सुंदर?
शव का अर्चन,
शिव का वर्जन,
कहूँ विसंगति या रूपांतर?

वैभव दूना,
अंतर सूना,
कहूँ प्रगति या प्रतिस्थलांतर?

मात्र संक्रमण?
या नव सर्जन?
स्वस्ति कहूँ या रहूँ निरूत्तर?

महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है। इसी राह पर चलते हुए सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है, जो देश में सबसे ज्यादा है। सरकार ने लाड़ली बहना योजना में 1.29 करोड़ बहनों के खातों में 19212 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डाली है। इस योजना के बारे में विरोधी कह रहे थे कि यह योजना चल नहीं पाएगी, लेकिन यह योजना लगातार चल रही है। महिला कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाएं निर्बाध रूप से चलती रहे, इसके लिए सरकार आय बढ़ाने के प्रयास कर रही है। इसके साथ ही सरकार 26 लाख लाड़ली बहनों को 450 रुपए गैस रिफिलिंग का दे रही है। महिला उद्यमियों को 850 एमएसएमई इकाईयों में 275 करोड़ की राशि का सीधा अंतरण किया है। इसके साथ ही सेनिटेशन एवं हाईजीन योजना में 19 लाख से अधिक बालिकाओं को 57 करोड़ 18 लाख रुपये की राशि अंतरित की गई है।

सरकार का प्रयास युवाओं को शिक्षित और सक्षम बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ना है। शिक्षा के क्षेत्र में एक विसंगति को दूर करते हुए सरकार ने 'कुलपति' का पदनाम बदलकर 'कुलगुरू' कर दिया है। युवाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रदेश के सभी 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज शुरू कर दिए हैं। इन कॉलेजों में शिक्षण की आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ छात्र-छात्राओं को कॉलेज तक लाने के लिए बसों की व्यवस्था भी की गई है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हमारी सरकार ऋण दे रही है। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंडस्ट्री कॉरिडोर स्थापित कर रहे हैं तथा हर संभाग में इंडस्ट्री कॉनक्लेव का आयोजन किया जा रहा है। सरकार प्रदेश के ढाई लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया पर तो काम कर रही है, इसके अलावा विभिन्न संभागों में स्थापित होने जा रहे उद्योगों में भी करीब तीन लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मध्यप्रदेश में कृषि की प्रधानता को देखते हुए बीएससी एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम सभी विश्वविद्यालयों तथा चुनिंदा पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों में शुरू करने का निर्णय लिया है। इसी तरह के प्रयास डेयरी उद्योग से जुड़े पाठ्यक्रमों के लिए भी कर रहे हैं। युवाओं को अपने दस्तावेज कहीं भी लाने-ले जाने में असुविधा न हो, इसके लिए डिजीलॉकर की व्यवस्था लागू की है।

गरीब कल्याण के रास्ते पर कदम बढ़ाते हुए सरकार ने इंदौर के हुकुमचंद मिल के 4 हजार 800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया, जो वर्षों से लंबित था। ग्वालियर की जेसी मिल, रतलाम की सज्जन मिल और उज्जैन की श्री सिंथेटिक्स के मामले में भी सरकार ऐसे ही प्रयास कर रही है। मध्यप्रदेश में गरीब कल्याण की दृष्टि से सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, स्वनिधि योजना, संबल योजना, स्वामित्व योजना आदि चलाई जा रही हैं, जिनसे गरीबों के जीवन में बदलाव आ रहा है। प्रदेश में संबल योजना में 1.73 करोड़ पंजीयन हुए हैं, जिनमें से 40000 से अधिक लोगों को 895 करोड़ की राशि का वितरण एक साल में किया है। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान मिल रहे हैं, वहीं स्वामित्व योजना के अंतर्गत सरकार ने 24 लाख लोगों को भू अधिकार पत्र दिये हैं।

सरकार संस्कृति को समृद्ध करने का काम कर रही है। एक तरफ सरकार भगवान श्रीराम के वन गमन पथ के विकास का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ भगवान श्रीकृष्ण के पाथेय पर भी काम कर रही है। धार्मिक पर्यटन से युवाओं को रोजगार मिले और निवेश आए, इसके लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों का भी विकास हो रहा है। भगवान श्रीकृष्ण के संबंध में जो महत्व मथुरा का है, वही उज्जैन का, इंदौर की जानापाव पहाड़ी का और धार जिले के अमझेरा का भी है, जहां भगवान कृष्ण ने रुक्मी के साथ युद्ध किया था। इन स्थलों के विकास पर भी काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में गीता जयंती भी मनाई। इससे पहले गोवर्धन उत्सव भी मनाया था।

सुशासन उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने अनेक पहल की हैं। साइबर तहसीलों के माध्यम से दस्तावेजों का पंजीकरण करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। भोपाल में बीआरटीएस के कारण दिक्कतें आ रही थीं, तो उसे हटा दिया और अब ऐसा ही प्रयास इंदौर में भी कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश के थानों का नए सिरे से परिसीमन किया और जिलों के परिसीमन के लिए भी आयोग का गठन किया है। अनियमित और अनियंत्रित लाउडस्पीकर के शोर तथा खुले में मांस-मछली की बिक्री को रोकने के लिए भी कदम उठाए हैं।

चिकित्सा क्षेत्र में भी लगातार काम किया। शपथ लेते ही स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय का एकीकरण किया, जिससे संसाधनों की बचत हो रही है। एक समय प्रदेश में सिर्फ पांच मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज प्रदेश में 17 सरकारी और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। पीपीपी मोड पर 14 और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह मध्यप्रदेश सबसे तेज

गति से मेडिकल कॉलेज खोलने वाला राज्य बन जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना भी कर रही है। मेडिसिटी की अवधारणा पर भी काम कर रहे हैं, जिनमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक उपचार एक साथ उपलब्ध होगा। प्रदेश में पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा का लाभ गंभीर मरीजों को मिल रहा है। मध्यप्रदेश 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला देश का नंबर वन राज्य बन गया है। इसके अलावा 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 46491 नए पद स्वीकृत किए हैं।

प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार का प्रयास है कि पहले से काम कर रहे उद्योगपति अपने काम को बढ़ाएं, नये क्षेत्रों में आगे आएं, देश के अन्य उद्योगपति प्रदेश में उद्योग लगाएं तथा विदेशी उद्योग भी मध्यप्रदेश में निवेश करें। इसके लिए उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा तथा नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव का आयोजन किया है। इसके बाद शहडोल संभाग में कॉनक्लेव और फिर भोपाल में 24 फरवरी को ग्लोबल इंडिस्ट्रियल कॉनक्लेव, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल होंगे। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए देश के अनेक शहरों में रोड शो और अलग-अलग महानगरों में जाकर अधिकारी वहां के उद्योगपतियों को सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इन प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। सरकार ने 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें जिला स्तर पर कॉनक्लेव का आयोजन होगा। ▪

जीवन में खुशहाली व कल्याण के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित- विष्णुदत्त शर्मा

- **मध्यप्रदेश के समग्र विकास की परिकल्पना को साकार कर रही भाजपा सरकार।**
- **गुड गवर्नेंस व त्वरित एक्शन के साथ प्रधानमंत्री जी की चार जातियों पर सरकार का फोकस।**

13 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पद संभाला था। डॉ. मोहन यादव का एक वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र व मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की डबल इंजन सरकार हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने व हर समाज वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। सरकार ने गुड गवर्नेंस पर कार्य करते हुए विभिन्न मुद्दों पर त्वरित एक्शन लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की बताई चार जातियों- किसान, गरीब, युवा व महिलाओं के हितों व विकास को ध्यान में रखकर प्रदेश में योजनाएं बनाई गई हैं और उन्हें बहुत संवेदनशीलता के साथ पूरा किया जा रहा है। किसानों के लिए साइबर तहसील योजना लागू करने के साथ रजिस्ट्री के साथ तुरंत नामांतरण की व्यवस्था की है। युवाओं के लिए एक लाख सरकारी पदों पर भर्तियां करने का निर्णय किया है। महिलाओं के लिए लाड़ली लक्ष्मी, लाड़ली बहना योजना के साथ सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ नगरीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। गरीबों के लिए पीएम एयर एंबुलेंस जैसी सेवा शुरू की गई, ताकि हर गरीब को समय पर सुगम इलाज मुहैया कराया जा सके। पीएम एयर एंबुलेंस योजना से प्रदेश के कई गरीबों को तुरंत एयरलिफ्ट कर बड़े अस्पतालों में भर्ती कराकर उनका निःशुल्क इलाज कराकर सरकार ने जिंदगी बचाने का कार्य किया है। इस तरह की योजनाएं भाजपा की मध्यप्रदेश सरकार की जनता के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के समग्र विकास की परिकल्पना को साकार कर रही है। प्रदेश सरकार सुशासन के साथ त्वरित एक्शन लेते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की चार जातियों पर फोकस कर रही है। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ धर्म, आध्यात्म व संस्कृति का संवर्धन कर रही है।

मध्यप्रदेश के विकास व स्वर्णिम और आत्मनिर्भर बनाने में एक वर्ष मील का पत्थर साबित होगा। सुशासन, संकल्प एवं सिद्धि के साथ एक साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार ने सशक्त मध्यप्रदेश के निर्माण में अभूतपूर्व कार्य किया है। एक साल में सरकार को करीब चार लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें करीब साढ़े चार लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक साल के उपलब्धियों भरे कार्यकाल में कई नवाचार किए हैं। मध्यप्रदेश में उद्योगों का जाल बिछाने के लिए वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है। संभागीय स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर मध्यप्रदेश के हर जिले के समग्र विकास की परिकल्पना पर कार्य कर रहे हैं। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार छोटे शहरों के समुचित विकास के लिए कार्य कर रही है। सरकार धर्म, आध्यात्म, संस्कृति को बढ़ावा देने व संवर्धन का कार्य कर रही है। गीता जयंती का आयोजन हो या गोवर्धन पूजा सरकार जनता की सहभागिता के साथ पर्व और त्योहारों को उल्लास के साथ मना रही है। मध्यप्रदेश सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियां सरकार जन कल्याण पर्व और जनकल्याण अभियान के साथ जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अभी पार्टी के संगठन पर्व चल रहे हैं। प्रदेश में रिकॉर्ड सदस्यता के साथ 65014 बूथों पर बूथ समितियों का गठन हो चुका है। सभी भाजपा कार्यकर्ता मैदान में उतरकर घर-घर संपर्क कर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जनता को बताएंगे। ▪

भागीरथ, भोज, छत्रसाल की अटल विरासत के संवाहक मोदी जी

प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में गंगा की धरा पर उपस्थिती का श्रेय राजा भागीरथ को दिया जाता है।

राजा भागीरथ के तप और साधना से गंगा धरती पर अवतरित हुईं, जिसकी उपस्थिती से भारत का भू-भाग समृद्ध हुआ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आधुनिक भागीरथ हैं। मोदीजी ने भी जल संकट से जूझते भारत के लिए एक नई जल क्रांति की शुरुआत की है।

विष्णुदत्त शर्मा

मध्यप्रदेश की पुण्यभूमि, जो अपनी सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक गौरव के लिए प्रसिद्ध है, अब एक और ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनी है। 25 दिसंबर 2024 को मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के खजुराहो में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर-कमलों से हुआ। यह क्षण न केवल मध्यप्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए विकास, जल संरक्षण एवं जल समृद्धि की दिशा में एक नया अध्याय लिखने वाला है, साथ ही यह भारत की जल क्रांति की नई गाथा लिखने का भी प्रतीक बनेगा। शुभ योग यह है कि परियोजना का भूमिपूजन आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के दिन हुआ है, जिन्होंने भारत के विकास के लिए अनेक सपने देखे थे, उनमें नदियों को जोड़ना विशेष रूप से शामिल था। उन्होंने इस दिशा में प्रारंभिक कदम भी उठाए थे। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वप्न दृष्टा वाजपेयी जी के सपने साकार करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। यह परियोजना प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व, दूरदर्शिता, मध्यप्रदेश के प्रति उनके विशेष स्नेह और अटलजी के विचारों के प्रति समर्पण का एक और प्रमाण है, जो मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी सिद्ध होगी।

प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में गंगा की धरा पर उपस्थिती का श्रेय राजा भागीरथ को दिया जाता है। राजा भागीरथ के तप और साधना से गंगा धरती पर अवतरित हुईं, जिसकी उपस्थिती से भारत का भू-भाग समृद्ध हुआ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आधुनिक भागीरथ हैं। मोदीजी ने भी जल संकट से जूझते भारत के लिए एक नई जल क्रांति की शुरुआत की है। जल संसाधनों को भारत की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा बनाया है। उनके नेतृत्व में जल केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य और विकास का आधार बन गया है। गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तब उनकी जल नीतियों ने सूखे और जल संकट से जूझते गुजरात को जलसमृद्धि का अनूठा उदाहरण बनाया। गुजरात, जो कभी सूखे और जल संकट का प्रतीक था, आज नर्मदा नदी के जल से आच्छादित है। उनकी दूरदृष्टि और अदम्य साहस ने नर्मदा नदी के जल को सही दिशा

में मोड़ते हुए गुजरात की प्यास बुझाई, कृषि क्षेत्र को समृद्ध किया और नर्मदा के जल से साबरमती नदी को भी नया जीवन दिया। यह उनकी नीतियों और इच्छाशक्ति का ही परिणाम है कि गुजरात में जल के अभाव का स्थान जल के सदुपयोग और समृद्धि ने ले लिया। गुजरात में उनका काम जल संकट से जूझ रहे राज्यों के लिए आदर्श बन चुका है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जल संरक्षण को केवल एक सरकारी नीति तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बनाया। उनके अनुसार, जल का प्रबंधन एक पुण्य कर्म है, जिसमें वर्तमान की जरूरतें और भविष्य की पीढ़ियों का उत्तरदायित्व दोनों निहित हैं। उनका यह कथन इस सोच को सार्थक रूप देता है कि जल का सवाल केवल संसाधनों का नहीं, बल्कि मानवता के अस्तित्व का है। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आधुनिक राजाभोज कहना न्याय संगत है। राजा भोज ने जल संरक्षण के लिए ऐसी संरचनाएं बनाईं, जो सदियों बाद भी जल प्रबंधन की उत्कृष्ट मिसाल बनी हुई हैं। भोपाल का ऐतिहासिक बड़ा तालाब राजा भोज की जल संरक्षण क्षमता का अद्भुत उदाहरण है,जो सदियों बीत जाने के बाद भी लाखों लोगों की प्यास बुझा रहा है। दो नदियों के संगम से बनाए गए इस तालाब ने यह सिद्ध कर दिया है कि जल संरक्षण केवल उस समय की आवश्यकता ही नहीं, बल्कि उसे पीढ़ियों के लिए उपहार के रूप में संरक्षित किया जाता है।

प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का दृष्टिकोण भी ऐसा ही है। मोदी जी भी जल संरचनाओं के जनक राजाभोज की परंपरा को आधुनिकता के साथ मानवता के अस्तित्व के लिए आगे बढ़ा रहे हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का मानना है कि जल का संरक्षण केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है-**'जल संचय केवल एक प्रयास नहीं, यह एक पुण्य है। इसमें उदारता और उत्तरदायित्व दोनों निहित हैं। आने वाली पीढ़ियां जब हमारा आकलन करेंगी, तो यह केवल हमारी आर्थिक उपलब्धियों या भौतिक विकास पर आधारित नहीं होगा। उनका पहला प्रश्न यही होगा कि हमने जल के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया। जल का संरक्षण, प्रबंधन और इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता ही भविष्य में हमारी पहचान बनेगी।'** यह विचार न केवल जल संरक्षण के महत्व को दर्शाता है इसीलिये उनकी जलनीतियां दीर्घकालिक हैं, जो न केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान करती हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी टिकाऊ मार्ग प्रस्तुत करती हैं। माननीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुए 'जल शक्ति अभियान' और 'हर घर जल' और 'कैच द रैन' जैसे अभियानों ने करोड़ों भारतीयों के जीवन को परिवर्तित कर दिया है। उनकी योजनाएं यह सिद्ध करती हैं कि जल प्रबंधन में उनका दृष्टिकोण कितना प्रभावशाली और स्थायी है।

मध्यप्रदेश के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का विशेष लगाव समय-समय पर उनकी योजनाओं और निर्णयों से स्पष्ट होता है। उन्होंने हमेशा मध्यप्रदेश को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। उनके प्रयासों से राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अब केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना मध्यप्रदेश के विकास में नई ईबारत लिखने जा रही है। केन-बेतवा लिंक परियोजना, जिस भूमि पर बन रही है, वह शौर्य, सम्मान और जनकल्याण के प्रतीक बुंदेलखंड की भूमि है, बुंदेलखंड की पवित्र भूमि ने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है, जिन्होंने लोकहित को सर्वोपरि रखा। राजा छत्रसाल ने अपनी नीतियों और नेतृत्व से बुंदेलखंड के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए, उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का नेतृत्व भी राजा छत्रसाल के दृष्टिकोण का आधुनिक संस्करण है। उनकी योजनाएं और प्रयास बुंदेलखंड को जल संकट से उबारने और यहां की सूखी धरती को फिर से हराभरा बनाने के लिए समर्पित हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के संकल्प का फल है कि 44,605 हजार करोड़ रूपये की केन-बेतवा लिंक जैसी बहुप्रतीक्षित परियोजना आज जमीन पर उतर रही है और इसने खजुराहो लोकसभा ही नहीं बल्कि सारे बुंदेलखंड की विभीषिका को समाप्त करने के मार्ग प्रशस्त कर दिये हैं। मध्यप्रदेश की 44 लाख एवं उत्तर प्रदेश की 21 लाख जनता को इससे पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी एवं दोनों राज्यों की 65 लाख जनता को सीधे तौर पर इसका फायदा होगा । केन-बेतवा लिंक परियोजना का लाभ मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर और दतिया के साथ-साथ शिवपुरी, विदिशा और रायसेन सहित उत्तर प्रदेश के महोबा, झांसी, बांदा और ललितपुर को भी मिलेगा। इस कार्य के पूरा हो जाने से जहां 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी वहीं 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। बुंदेलखंड में आने वाले उत्तर प्रदेश के 2 लाख 52 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और पेय जल की सुविधा भी इससे मिल सकेगी। यही नहीं 103 मेगा वाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा की जा सकेगी। परियोजना में ऐतिहासिक चंदेल कालीन तालाबों को सहेजने का कार्य भी होगा। इन तालाबों से भूजल स्तर बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्र को फायदा तो होगा। कुल मिलाकर यह परियोजना भारत के जल संकट में मील का पत्थर सिद्ध होगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक दृष्टा हैं। वे राजा भागीरथ, राजाभोज और छत्रसाल जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी जल नीति केवल भारत की जल समस्याओं का समाधान ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बनते हुए उन्हें जलपुरुष के रूप में स्थापित करती है। उनका प्रयास हमें यह विश्वास दिलाता है कि भारत न केवल अपने जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन करेगा, बल्कि जल समृद्धि के क्षेत्र में विश्व का पथ प्रदर्शक भी बनेगा। मध्यप्रदेश की पवित्र भूमि से जल संरक्षण और जल समृद्धि का यह संदेश जब पूरे देश में गूंजेगा, तो यह केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि जल और जीवन की नई गाथा का आरंभ होगा।

25 दिसंबर के दिन इस योजना का भूमिपूजन न केवल श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, बल्कि जल संकट से जूझते देश के लिए एक नई उम्मीद भी है।

बुंदेलखंड के निवासियों से देश के मुखिया का यह आह्वान है कि वे इस परियोजना को एक महायज्ञ के रूप में देखें और इसके लाभों को आत्मसात करें। यह परियोजना केवल जल संकट का समाधान नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के विकास, समृद्धि और खुशहाली का द्वार खोलने वाली है। यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे जल संरक्षण के महत्व को समझें और इस परियोजना के उद्देश्यों को साकार करने में अपना योगदान दें।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वास्तव में एक नई जल क्रांति की ओर बढ़ रहा है। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने मेरे संसदीय क्षेत्र में इस परियोजना का भूमिपूजन किया, पूरे संसदीय क्षेत्र और मप्र की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। ▪

लेखक- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद हैं।

संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा

भारत की एकता का आधार हमारा संविधान - नरेन्द्र मोदी

संविधान निर्माताओं की जो भावनाएं थीं उसको जीने में पिछले 75 साल भारत का नागरिक हर कसौटी पर खड़ा उतरा है।

संविधान निर्माता इस बात में बहुत सजग थे। वह यह नहीं मानते थे कि भारत का जन्म 1947 में हुआ है, वह यह नहीं मानते थे कि भारत में लोकतंत्र 1950 से आ रहा है, वे मानते थे यहां के महान परंपरा को, महान संस्कृति को, महान विरासत को, हजारों साल की उस यात्रा को उसके प्रति वह सजग थे।

भारत का लोकतंत्र, गणतांत्रिक अतीत समृद्ध रहा है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है।

राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने कहा था–सदियों के बाद हमारे देश में एक बार फिर ऐसी बैठक बुलाई गई है। यह हमारे मन में अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। जब हम स्वतंत्र हुआ करते थे, जब सभाएं आयोजित की जाती थी, जिसमें विद्वान लोग देश के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए मिला करते थे।

डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा था- इस महान राष्ट्र के लिए गणतांत्रिक व्यवस्था नई नहीं है। हमारे यहां यह इतिहास के शुरुआत से ही है।

बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था - ऐसा नहीं है कि भारत को पता नहीं था कि लोकतंत्र क्या होता है। एक समय था जब भारत में कई गणतंत्र हुआ करते थे। संविधान निर्माण प्रक्रिया में देश की नारी शक्ति ने संविधान को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। संविधान सभा में 15 माननीय महिला सक्रिय सदस्य थीं। मौलिक चिंतन के आधार पर उन्होंने संविधान सभा की डिबेट को समृद्ध किया था और वह सभी बहनें अलग-अलग बैकग्राउंड की थीं, अलग-अलग क्षेत्र की थीं। और संविधान में उन्होंने जो-जो सुझाव दिए, उन सुझावों का संविधान के निर्माण पर बहुत प्रभाव रहा। दुनिया के कई देश आजाद भी हुए, संविधान भी बने, लोकतंत्र भी चला, लेकिन महिलाओं को अधिकार देने में दशकों बीत गए थे। हमारे यहां शुरुआत से ही महिलाओं को वोट का अधिकार संविधान में दिया गया है।

संविधान निर्माण प्रक्रिया में देश की नारी शक्ति ने संविधान को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। संविधान सभा में 15 माननीय महिला सक्रिय सदस्य थीं।

मौलिक चिंतन के आधार पर उन्होंने संविधान सभा की डिबेट को समृद्ध किया था और वह सभी बहनें अलग-अलग बैकग्राउंड की थीं, अलग-अलग क्षेत्र की थीं। और संविधान में उन्होंने जो-जो सुझाव दिए, उन सुझावों का संविधान के निर्माण पर बहुत प्रभाव रहा।

हमने जी-20 की अध्यक्षता के दरमियान विश्व के सामने वीमेन लेड डेवलपमेंट का विचार रखा था। वीमेन डेवलपमेंट से आगे जाने की जरूरत है, हमने वीमेन लेड डेवलपमेंट की चर्चा को अंजाम दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके महिला शक्ति को भारतीय लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए।

आज हर बड़ी योजना के सेंटर में महिलाएं हैं, जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं। यह संयोग है कि भारत के राष्ट्रपति पद पर आदिवासी महिला विराजमान हैं। यह संविधान की भावना की अभिव्यक्ति भी है।

सदन में भी लगातार महिला सांसदों की संख्या बढ़ रही है, योगदान भी बढ़ रहा है। मंत्री परिषद में भी योगदान बढ़ रहा है। सामाजिक

क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेलकूद का क्षेत्र हो, क्रिएटिव वर्ल्ड हो, हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान, प्रतिनिधित्व देश को गौरव दिलाने वाला रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में खास करके स्पेस टेक्नोलॉजी में उनके योगदान की सराहना हर हिंदुस्तानी बड़े गर्व के साथ कर रहा है।

बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था – समस्या यह है कि देश में जो विविधता से भरा भारत का जन मानस है उसे किस तरह एक मत किया जाए। कैसे देश के लोगों को एक दूसरे के साथ होकर निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाए। जिससे कि देश में एकता की भावना स्थापित हो।

आजादी के बाद एक तरफ संविधान निर्माता के दिल दिमाग में एकता थी। लेकिन आजादी के बाद विकृत मानसिकता के कारण या स्वार्थवश सबसे बड़ा प्रहार हुआ तो देश की एकता के मूल भाव पर हुआ। भारत का भला न देख पाने वाले लोगों ने और जिनके लिए हिंदुस्तान 1947 में ही पैदा हुआ, जो धारणा बनी थी, उनके लिए वो विविधता में विरोधाभास ढूंढते रहे। विविधता अमूल्य खजाना है, उसको सेलिब्रेट करने के बजाय उस विविधता में ऐसे जहरीले बीज बोने के प्रयास करते रहे ताकि देश की एकता को चोट पहुंचे।

आर्टिकल 370 देश की एकता में रुकावट थी। धारा 370 को हमने जमीन में गाड़ दिया। क्योंकि देश की एकता हमारी प्राथमिकता है।

इकोनामिक यूनिटी के लिए जीएसटी ने बड़ी भूमिका अदा की है। वन नेशन वन टैक्स उसे आगे बढ़ा रहा है।

एकता के भाव को मजबूत करने के लिए हमने वन नेशन वन राशन कार्ड की बात मजबूत की है।

देश की एकता के मंत्र के लिए वन नेशन वन हेल्थ कार्ड और आयुष्मान भारत घोषणा की है।

वन नेशन वन ग्रिड को परिपूर्ण कर दिया है, आज बिजली के प्रभाव को निर्विरोध रूप से हिंदुस्तान के हर कोने में ले जाया जा सकता है।

नॉर्थ ईस्ट या जम्मू कश्मीर, हिमालय के गोद के इलाके या रेगिस्तान के सटे हुए इलाके, हमने पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को सामर्थ्य देने का प्रयास किया है।

ऑप्टिकल फाइबर हिंदुस्तान की हर पंचायतों तक ले जाने का प्रयास किया है ताकि भारत की एकता को मजबूती देने में ताकत मिले।

न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा को बहुत बल दिया है, देश का गरीब बच्चा भी मातृभाषा में डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है।

क्लासिकल लैंग्वेज की दिशा में कई लैंग्वेज, जिनका हक बनता था, उनको उस स्थान पर रख करके उनका सम्मान किया।

देश भर में एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान देश की एकता को मजबूत और नई पीढ़ी को संस्कारित करने का काम चल रहा है।

काशी तमिल संगमम और तेलुगू काशी संगमम यह आज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुआ है और समाज में निकटता को मजबूती देने का सांस्कृतिक प्रयास भी चलता रहा है।

जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था। उसी समय देश में संविधान को नोच लिया गया था। आपातकाल लाया गया, संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया, देश को जेल खाना बना दिया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए, कांग्रेस के माथे पर यह जो पाप है वह कभी भी धुलने वाले नहीं है। दुनिया में जब-जब लोकतंत्र की चर्चा होगी कांग्रेस के माथे का यह पाप कभी धुलने वाला नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी।

26 नवंबर 2000 को देश भर में संविधान का 50 वर्ष मनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के नाते राष्ट्र को विशेष संदेश दिया था। एकता, जन भागीदारी, साझेदारी के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने संविधान की भावना को जीने का प्रयास किया था, जनता को जगाने का प्रयास किया था।

जब देश संविधान का 50 वर्ष मना रहा था, यह मेरा भी सौभाग्य था कि मुझे भी संविधान की प्रक्रिया से मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल गया और मैं जब मुख्यमंत्री था उसी कार्यकाल में, संविधान के 60 साल हुए और तब मैंने तय किया था, कि हम गुजरात में संविधान के 60 साल मनाएंगे और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब संविधान के ग्रंथ को हाथी पर अंबारी में रखा गया, उसे विशेष व्यवस्था में रखा गया। हाथी पर संविधान गौरव यात्रा निकाली गई और राज्य का मुख्यमंत्री उस संविधान के नीचे हाथी के बगल में पैदल चल रहा था और देश को संविधान का महत्व समझाने का सांकेतिक प्रयास कर रहा था। यह सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ था, क्योंकि हमारे लिए संविधान का महत्व क्या है और आज 75 साल हुए हमें अवसर मिला और मुझे याद है जब मैंने लोकसभा के पुराने सदन के अंदर जब 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की बात कही थी। तब एक वरिष्ठ नेता ने सामने से आवाज उठाई थी कि 26 जनवरी तो है 26 नवंबर की क्या जरूरत है।

इस विशेष सत्र में अच्छा होता संविधान की शक्ति, विविधताओं पर चर्चा होती, नई पीढ़ी के काम आता। अच्छा होता दलगत की भावनाओं से उठकर के देश हित में संविधान की चर्चा हुई होती तो समृद्धि मिलती।

ये संविधान की भावना थी कि मेरे जैसे अनेक लोग जो यहां पर पहुंच नहीं पाते, ये संविधान था जिसके कारण हम पहुंच पाए।

कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या-क्या हुआ है यह जानने का अधिकार है और इस परिवार के कुविचार-कुरीति-कुनीति इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है।

1947 से 1952, इस देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, एक अस्थाई व्यवस्था थी, एक सिलेक्टेड सरकार थी और चुनाव नहीं हुए थे और जब तक चुनाव ना हो तब तक एक इंटरीम व्यवस्था के रूप में कोई खाखा खड़ा करना चाहिए था। 1952 के पहले राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था। राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं थे। जनता का कोई आदेश नहीं था। उसके बावजूद भी और अभी-अभी तो संविधान निर्माताओं ने इतना मंथन करके संविधान बनाया था। 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी। उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया और यह संविधान निर्माता का भी अपमान था, क्योंकि ऐसी बातें कोई संविधान सभा में नहीं आई होगी ऐसा नहीं है। लेकिन वहां उनकी चली नहीं तो बाद में जैसे ही मौका मिला उन्होंने अभिव्यक्ति की इस आजादी पर हथोड़ा मार दिया और यह संविधान निर्माताओं का घोर अपमान है। अपने मन की चीजें जो संविधान सभा के अंदर नहीं करवा पाए, वो उन्होंने पिछले दरवाजे से किया और वह भी चुनी हुई सरकार के वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने पाप किया था।

उसी दौरान, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए।

1951 में यह पाप किया गया। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चेताया यह गलत हो रहा है। उस समय स्पीकर पद पर बैठे हुए स्पीकर महोदय ने भी पंडित जी को कहा गलत कर रहे हो। इतना ही नहीं आचार्य कृपलानी जी, जय प्रकाश नारायण, जैसे महान कांग्रेसी लोगों ने भी पंडित नेहरू से कहा कि यह रोको लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था। और इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावों की सलाह मानी नहीं और उसे दरकिनार कर दिया।

यह संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय-समय पर वह संविधान का शिकार करते रहे। संविधान की स्पिरिट को लहूलूहान करते रहे।

6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था। उस बीज को खाद पानी देने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। जो पाप पहले प्रधानमंत्री करके गए और जो खून लग गया था। 1971 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान बदलकर के पलट दिया गया और 1971 में यह संविधान संशोधन किया गया था। और क्या था, उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे और यहां कहा था कि संसद संविधान के किसी भी आर्टिकल में जो मर्जी प्रयोग कर सकती है और अदालत उसकी तरफ देख भी नहीं सकती है। अदालत के सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। यह पाप 1971 में उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। और इस परिवर्तन ने इंदिरा जी की सरकार को मौलिक अधिकारों को छीनने का और न्याय पालिका पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया, सक्षम बना दिया था।

खून मुंह पर लग गया था कोई रोकने वाला था नहीं और इसलिए जब इंदिरा जी के चुनाव को गैर रीति के कारण और असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया और उनको एमपी पद छोड़ने की नौबत आई, तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए और उसके बाद इमरजेंसी तो लगाई, संविधान का दुरुपयोग तो किया ही किया, भारत के लोकतंत्र का गला तो घोट ही दिया, लेकिन 1975 में 39वां संशोधन किया और उसमें उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, इनके चुनाव के खिलाफ कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता है ऐसा उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव किया।

इमरजेंसी में लोगों के अधिकार छीन लिए गए। देश के हजारों लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया। न्यायपालिका का गला घोट दिया गया। अखबारों की स्वतंत्रता पर ताले लगा दिए गए। इतना ही नहीं कमिटेड ज्यूडिशरी इस विचार को उन्होंने पूरी ताकत दी और जिस जस्टिस एच आर खन्ना ने उनके चुनाव में उनके खिलाफ जो जजमेंट दिया था, वो इतना गुस्सा भरा था, कि जब जस्टिस एच आर खन्ना जो सीनियरिटी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले थे। जिन्होंने संविधान का सम्मान करते हुए उस स्पिरिट से इंदिरा जी को सजा दी थी, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया यह संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया रही।

देश पर जुल्म और तांडव चल रहा था। निर्दोष लोगों को जेलों में ठूंस दिया जाता था। लाठियां बरसाईं जाती थी। कई लोग जेलों में मौत के शरण हो गए थे और एक निर्दयी सरकार संविधान को चूर-चूर करती रही थी।

ये परंपरा यहां नहीं रूकी, जो परंपरा नेहरू जी ने शुरू की थी। जिसको दूसरे प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया क्योंकि खून मुंह पर लग गया था और इसलिए राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनें। उन्होंने संविधान को एक और गंभीर झटका दे दिया। सबको समानता, सबको न्याय, उस भावना को चोट पहुंचाई।

सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो का जजमेंट दिया था। एक भारत की महिला को न्याय देने का काम संविधान की मर्यादा और स्पिरिट के आधार पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक वृद्ध महिला को उसका हक मिला था लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। उन्होंने न्याय के लिए तड़प रही एक वृद्ध महिला को साथ देने के बजाय, कट्टरपंथियों का साथ दिया। संसद में कानून बनाकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को फिर एक बार पलट दिया गया।

बात वहां तक नहीं अटकी है। नेहरू जी ने शुरू किया, इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया और राजीव जी ने भी उसको ताकत दी। खाद-पानी देने का काम किया क्यों? संविधान के साथ खिलवाड़ करने का लहू उनके मुंह लग गया था।

अगली पीढ़ी भी इसी खिलवाड़ में डूबी पड़ी है। एक किताब को quote कर रहा हूं। किताब में लिखा है और उसमें एक प्रधानमंत्री उस समय के, मेरे पहले जो प्रधानमंत्री थे, उनको quote किया है। उन्होंने कहा है, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा है जो इस किताब में लिखा गया है। सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है।

इतिहास में पहली बार संविधान को ऐसी गहरी चोट पहुंचा दी गई। इन्होंने तो प्रधानमंत्री के ऊपर एक गैर संवैधानिक और जिसने कोई शपथ भी नहीं लिया था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पीएमओ के भी ऊपर बैठा दिया। पीएमओ के ऊपर अघोषित दर्जा दे दिया गया।

इतना ही नहीं और एक पीढ़ी आगे चलें और उस पीढ़ी ने क्या किया, भारत के संविधान के तहत देश की जनता जनार्दन सरकार चुनती है और उस सरकार का मुखिया कैबिनेट बनाता है, ये संविधान के तहत है। इस कैबिनेट ने जो निर्णय किया संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। हर मौके पर संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान को ना मानना, ये जिनकी आदत हो गई थी और दुर्भाग्य देखिए, एक अहंकारी व्यक्ति कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे और कैबिनेट अपना फैसला बदल दे, ये कौन सी व्यवस्था है?

संविधान के साथ धोखेबाजी कैसे करते थे, संवैधानिक संस्थाओं को कैसे नहीं मानते थे। इस देश में बहुत कम लोगों को मालूम होगा, 370 की तो पता है सबको, 35A का पता बहुत कम है। 35A जो संसद में लाए बिना उन्होंने देश पर थोप दिया और अगर 35A ना होता तो जम्मू-कश्मीर में जो हालत पैदा हुई वो हालत पैदा ना हुई होती। राष्ट्रपति के आदेश पर ये काम किया गया और देश की संसद को अंधेरे में रखा गया।

जब अटल जी की सरकार थी तब बाबा साहब आंबेडकर जी की स्मृति में एक स्मारक बनवाना तय हुआ। दुर्भाग्य देखिए 10 वर्ष यूपीए की सरकार हुई, उसने इस काम को नहीं किया, ना होने दिया। जब हमारी सरकार आई, बाबा साहब आंबेडकर के प्रति हमारा श्रद्धा होने के कारण हमने अलिपुर रोड पर बाबा साहब मेमोरियल बनवाया और उसका काम किया।

1992 में,चंद्रशेखर जी कुछ समय थे, तब निर्णय किया गया था। आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर यहीं जनपथ के पास, 40 साल तक वो कागज पर ही पड़ा रहा, नहीं किया गया और तब जाकर के 2015 में हमारी सरकार आई और हमने आकर के इस काम को पूरा किया। बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भी जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई तब संभव हुआ। इतना ही नही बाबा साहब आंबेडकर के सवा सौ साल तो हमने पूरी दुनिया में मनाए थे। विश्व के 120 देशों में मनाने का काम किया था लेकिन जब बाबा साहब आंबेडकर की शताब्दी थी, तब अकेली बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में सुंदरलाल जी पटवा हमारे मुख्यमंत्री जी थे और महू में, जहां बाबा साहब आंबेडकर जी का जन्म हुआ था उसको एक स्मारक के रूप में पुनर्निर्माण करने का काम तब मध्य प्रदेश में हुआ था। शताब्दी के समय भी उनके साथ यही किया गया था।

बाबा साहब आंबेडकर दीर्घदृष्टा थे। समाज के दबे-कुचले लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए वो प्रतिबद्ध थे और लंबी सोच के साथ भारत को अगर विकसित होना है तो भारत को कोई अंग दुर्बल नहीं रहना चाहिए, ये चिंता बाबा साहब को सताती थी और तब जाकर के हमारे

देश में आरक्षण की व्यवस्था बनी। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में खपे हुए लोगों ने, डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर तुष्टिकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर कुछ ना कुछ नुस्खे देने का प्रयास किया और इसका सबसे बड़ा नुकसान एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हुआ है।

नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का घोर विरोध किया है। हिस्ट्री कह रही है, आरक्षण के विरोध में लंबी-लंबी चिट्ठियां स्वयं नेहरू जी ने लिखी है, मुख्यमंत्रियों को लिखी हैं। इतना ही नहीं सदन में आरक्षण के खिलाफ लंबे-लंबे भाषण इन लोगों ने किए हैं। बाबा साहब आंबेडकर, समता के लिए और भारत में संतुलित विकास के लिए आरक्षण लेकर के आए, उन्होंने उसके खिलाफ भी झंडा ऊंचा किया हुआ था। दशकों तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को डिब्बे में डाल दिया था। जब कांग्रेस को देश ने हटाया, जब कांग्रेस गई तब जाकर के ओबीसी को आरक्षण मिला, तब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला, ये कांग्रेस का पाप है। अगर उस समय मिला होता तो आज देश के अनेक पदों पर ओबीसी समाज के लोग भी देश की सेवा करते, लेकिन नहीं चलने दिया, नहीं होने दिया, ये पाप इन्होंने किया था।

जब हमारे यहां संविधान का निर्माण चल रहा था, तब संविधान निर्माताओं ने धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस विषय पर घंटों तक, दिनों तक गहन चर्चा की है। विचार विमर्श किया है और सबका मत बना है कि भारत जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए धर्म के, संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। सुविचारित मत था, ऐसा नहीं कि भूल गए थे, रह गया था। सोच विचार कर तय किया गया था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए संप्रदाय और धर्म के आधार पर ये नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। इतना ही नहीं, दे भी दिया कुछ जगह पर और सुप्रीम कोर्ट से झटके लग रहे हैं और इसलिए अब दूसरे बहाने से बहाने बता रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, मन में साफ है धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, इसलिए ये खेल खेले जा रहे हैं। संविधान निर्माताओं की भावनाओं पर गहरी चोट करने का ये निर्लज्ज प्रयास है।

एक ज्वलंत विषय है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड! ये विषय भी संविधान सभा के ध्यान से बाहर नहीं था। संविधान सभा ने इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुनकर के आए, वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था और बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, जो लोग संविधान को समझते नहीं है, देश को समझते नहीं है, सत्ता भूख के सिवा कुछ पढ़ा नहीं है। उनको पता नहीं है बाबा साहब ने क्या कहा था।

पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। उस समय के सदस्य के.एम. मुंशी जी ने समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द होना चाहिए, सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेकुलर सिविल कोड के लिए और आज कांग्रेस के लोग संविधान निर्माताओं की इस भावना का भी, सुप्रीम कोर्ट की भावना का भी अनादर कर रहे हैं। क्योंकि उनकी राजनीति को वो सूट नहीं करता है, उनके लिए संविधान पवित्र ग्रंथ नहीं है, उनके लिए एक हथियार है राजनीति का। खेल खेलने का हथियार बना दिया है। लोगों को डराने के लिए संविधान को हथियार बनाया जाता है।

कांग्रेस पार्टी को तो संविधान शब्द भी उनके मुंह में शोभा नहीं देता है। क्योंकि संविधान को स्वीकार करने के लिए लोकतांत्रिक स्पिरिट लगती है। जो इनकी रगों में नहीं है सत्तावाद और परिवारवाद भरा पड़ा है।12 कांग्रेस प्रदेश कमेटियों ने, सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। नेहरू जी के साथ एक भी कमेटी नहीं थी, नोट ए सिंगल। संविधान के तहत सरदार साहब ही देश के प्रधानमंत्री बनते। लेकिन लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं, खुद के संविधान पर विश्वास नहीं, खुद के ही संविधान को स्वीकारना नहीं और सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके और यह बैठ गए। जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, वो कैसे देश के संविधान को स्वीकार कर सकते हैं।

कांग्रेस पार्टी के एक अध्यक्ष हुआ करते थे और वह अति पिछड़े समाज से आते थे,श्रीमान सीताराम केसरी जी, कैसा अपमान किया गया। कहते हैं बाथरूम में बंद कर दिया गया। उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। अपनी पार्टी के संविधान में ऐसा कभी नहीं लिखा गया, लेकिन अपनी पार्टी के संविधान को ना मानना लोकतंत्र की प्रक्रिया को ना मानना और पूरी कांग्रेस पार्टी पर एक परिवार ने कब्जा कर लिया।

लोकतंत्र को नकार दिया।

1996 में सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई, राष्ट्रपति जी ने संविधान की भावना के तहत सबसे बड़े दल को प्रधानमंत्री की शपथ के लिए बुलाया और 13 दिन सरकार चली। अगर हमें संविधान के स्पिरिट के प्रति हमारी भावना ना होती तो हम भी यह बांटो, वो बांटो, ये दे दो, वो दे दो। इसको डेप्युटी पीएम बना दो, इसको ढिकना बना दो। हम भी सत्ता सुख भोग सकते थे, लेकिन अटल जी ने सौदेबाजी का रास्ता नहीं चुना, संविधान के सम्मान का रास्ता चुना और 13 दिन के बाद इस्तीफा देना स्वीकार कर दिया। यह ऊंचाई है हमारे लोकतंत्र की। इतना ही नहीं 1998 में एनडीए की सरकार थी। सरकार चल रही थी लेकिन कुछ लोगों को हम नहीं तो कोई नहीं यह जो एक परिवार का खेल चला है, अटल जी की सरकार को अस्थिर करने के लिए खेल चले गए, वोट हुआ खरीद फरोख्त तब भी हो सकती थी, बाजार में माल तब भी बिकता था। लेकिन संविधान की भावना के प्रति समर्पित अटल बिहारी वाजपयी जी की सरकार ने एक वोट से हारना पसंद किया, इस्तीफा दिया, लेकिन असंवैधानिक पद स्वीकार नहीं किया।

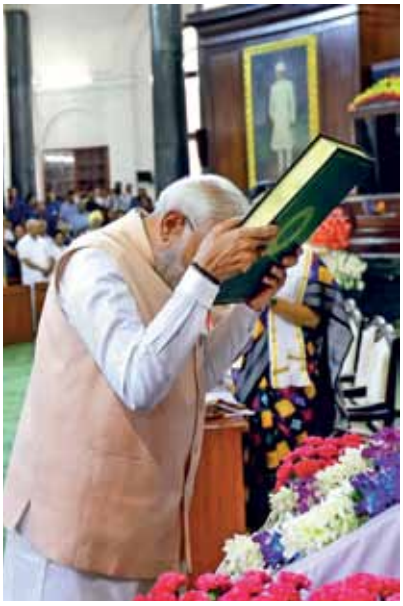

यह हमारा इतिहास है, यह हमारे संस्कार है, यह हमारी परंपरा है और दूसरी तरफ अदालत ने भी जिस पर ठप्पा मार दिया कैश फॉर वोट का कांड एक लघुमति सरकार को बचाने के लिए संसद में नोटों के ढेर रखे गए। असंवैधानिक तरीका सरकार बचाने के लिए भारत के लोकतंत्र की भावना को बाजार बना दिया गया। वोट खरीदे गए।

90 के दशक में कई सांसदों को रिश्वत देने का पाप यह संविधान की भावना थी क्या? 140 करोड़ देशवासियों के मन में जो लोकतंत्र पनपा है उस लोकतंत्र के साथ यह खिलवाड़। कांग्रेस के लिए सत्ता सुख, सत्ता की भूख यही एकमात्र कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस का वर्तमान है।

2014 के बाद एनडीए को सेवा का मौका मिला। संविधान और लोकतंत्र को मजबूती मिली। यह पुरानी जो बीमारियां थी उस बीमारी से मुक्ति का हमने अभियान चलाया। हमने भी संविधान संशोधन किए हैं। देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए और संविधान की भावना के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ किए है। हमने संविधान संशोधन किया, क्यों किया, इस देश का ओबीसी समाज तीन-तीन दशक से ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मांग कर रहा था। ओबीसी के सम्मान के लिए उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमने संविधान संशोधन किया है, हमें गर्व है यह करने का। समाज के दबे कुचले लोगों के साथ खड़े होना यह हम अपना कर्तव्य मानते हैं।

इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग था। वह किसी भी जाति में क्यों ना जन्मा हो लेकिन गरीबी के कारण अवसरों को वो पा नहीं सकता था, आगे बढ़ नहीं सकता था और इसलिए असंतोष की ज्वाला भड़क रही थी और सब की मांग थी, कोई निर्णय नहीं करता था। हमने संविधान संशोधन किया सामान्य जन के गरीब परिवार को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया। यह पहला आरक्षण का संशोधन था देश में कोई विरोध का स्वर नहीं उठा, हर किसी ने प्यार से उसको स्वीकार किया, संसद ने भी सहमति के साथ पारित किया। क्योंकि समाज की एकता की उसमें ताकत पड़ी थी। संविधान की भावनाओं का भाव पड़ा था। सबने सहयोग किया था तब जाकर यह हुआ था।

हमने भी संविधान में संशोधन किए हैं। महिलाओं को शक्ति देने के लिए। संसद और विधानसभा में और संसद का पुराना भवन गवाह है जब देश महिलाओं को आरक्षण देने के लिए आगे बढ़ रहा था और कानून बिल पेश हो रहा था, तब उन्ही का एक साथी दल बेल में आता है, कागज छीन लेता है, फाड़ देता है और सदन स्थगित हो जाता है, और 40 साल तक विषय लटका रहता है और वह आज उनके मार्गदर्शक हैं। जिन्होंने देश की महिलाओं के साथ अन्याय किया वह उनके मार्गदर्शक हैं।

हमने संविधान संशोधन किया, देश की एकता के लिए किया। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान 370 की दीवार के कारण जम्मू कश्मीर की तरफ देख भी नहीं सकता था। हम चाहते थे बाबा साहब अंबेडकर का संविधान हिंदुस्तान के हर हिस्से में लगना चाहिए और इसलिए बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी देनी थी, देश की एकता को मजबूत करना था, हमने संविधान संशोधन किया डंके की चोट पर किया और 370 को हटाया और अब तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी है।

हमने 370 को हटाने का संशोधन किया। हमने ऐसे कानून भी बनाए। जब देश का विभाजन हुआ महात्मा गांधी समेत देश के वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा था, कि पड़ोस के जो हमारे देश हैं वहां जो माइनारटीज हैं वो जब भी संकट में आएगी उनकी चिंता यह देश करेगा गांधी जी का वचन था जो उनके नाम पर सत्ता पर चढ़ जाते थे उन्होंने तो पूरा नहीं किया हमने CAA ला करके उसको पूरा किया। वह कानून हमने लाया, हमने किया है और गर्व के साथ हम आज भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, मुंह नहीं छुपाते हैं। क्योंकि देश के संविधान की भावना के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने का हमने काम किया है।

हमने जो संविधान संशोधन किए हैं वो पुरानी गलतियों को ठीक करने के लिए किए है और एक उज्जवल भविष्य का रास्ता मजबूत करने के लिए किए हैं और समय बताएगा समय की कसौटी पर हम खरे उतरेंगे या नहीं। क्योंकि यह सत्ता स्वार्थ के लिए किया गया पाप नहीं है। देश हित में किया गया पुण्य है।

हमारा संविधान सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर के संवेदनशील रहा है, वो हैं भारत के लोग। वी द पीपल, भारत के नागरिक, संविधान उनके लिए है, उनके हितों के लिए है, उनके कल्याण के लिए है, उनकी गरिमा के लिए हैं और इसलिए संविधान भारत के कल्याणकारी राज्य के लिए हमें दिशा निर्देश देता है और कल्याणकारी राज्य का मतलब है जहां नागरिकों को भी गरिमा प्राप्त हो उनको गरिमामय जीवन की गारंटी मिलनी चाहिए। इस देश को पता है हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वो चार-चार पीढ़ी ने चलाया वह जुमला था गरीबी हटाओ। उनकी राजनीति की रोटी तो हो सकती थी लेकिन गरीब का हाल ठीक नहीं होता था।

जरा कोई भी यह कहे आजादी के इतने सालों के बाद क्या एक डिग्निटी के साथ जीने वाले परिवार को टॉयलेट भी उपलब्ध नहीं होना चाहिए। क्या आपको यह काम करने की फुर्सत नहीं मिली। आज देश में टॉयलेट बनाने के अभियान को जो गरीबों के लिए एक सपना था। उसकी डिग्निटी के लिए हमने इस काम को हाथ में लिया और हम जी जान से जुटे रहे। उसका मजाक उड़ाया गया, उसके बाद भी सामान्य नागरिक के जीवन की गरिमा यह हमारे दिल और दिमाग में होने के कारण हम डिगे नहीं, हम अड़े रहे, हम आगे बढ़ते चले गए और तब जाकर के यह सपना साकार हुआ। माताएं बहनें खुले में शौच जा रही थी या तो सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के बाद और आपको कभी पीड़ा नहीं हुई और उसका कारण यह था कि आपने गरीबों को और गरीबी को टीवी में देखा है और अखबार की सुर्खियों में देखा है। आपको गरीब की जिंदगी का पता नहीं है। वरना आप इनके साथ ऐसा जुल्म नहीं करते।

इस देश की 80 प्रतिशत जनता पीने के शुद्ध पानी के लिए तरसती रही। संविधान उन्हें रोकता था क्या। संविधान तो यह चाहता था कि सामान्य मानवीय के सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए।

यह काम भी हमने बड़े समर्पण भाव से आगे बढ़ाया है।

इस देश की करोड़ों माताएं चूल्हे में खाना पकाना और धुएं से आंखें लाल करना, कहते हैं कि सैकड़ों सिगरेट का धुआं खाना पकाते हैं तब शरीर में जाता है। उन माता बहनों की आंखें लाल होती थी इतना ही नहीं, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता था। उनको धुएं से मुक्ति का काम और 2013 तक क्या चर्चा चलती थी।

9 सिलेंडर देंगे की 6 सिलेंडर देंगे। इस देश ने देखते ही देखते हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया।

अगर हमारा गरीब परिवार दिन रात मेहनत करके गरीबी से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन घर में एक बीमारी आ जाए तो उसका सारा प्लान बेकार हो जाता है, पूरे परिवार की सारी मेहनत पानी में चली जाती है। क्या इन गरीब परिवारों के इलाज के लिए आप कुछ सोच नहीं सकते थे। 50- 60 करोड़ देशवासियों को मुफ्त इलाज मिले, संविधान की इस भावना का आदर करते हुए हमने आयुष्मान योजना को लागू किया और आज देश के 70 साल के ऊपर के किसी भी वर्ग के क्यों ना हो उनके लिए भी हमने व्यवस्था की।

जरूरतमंदों को राशन देने की बात और उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करने में सफल हुए हैं। तो फिर हमसे सवाल पूछा जाता है तो फिर आप गरीब को राशन क्यों देते हो।

जो गरीबी से निकल कर आया है ना उसे पता होता है, कि अस्पताल में भी पेशेंट के स्वस्थ होने के बाद जब छुट्टी देते हैं तो डॉक्टर भी कहता है आप घर जाइए तबीयत ठीक है, ऑपरेशन अच्छा हुआ है। लेकिन महीने भर जरा संभलना, यह मत करना क्योंकि पेशेंट दोबारा तकलीफ में ना आए। गरीब दोबारा गरीब ना बने इसलिए उसका हैंड होल्डिंग जरूरी है और इसलिए हम उसको मुफ्त राशन दे रहे हैं उसका मजाक मत उड़ाओ क्योंकि उसे गरीबी से बाहर निकाला है, उसको दोबारा गरीबी में जाने नहीं देना है और जो अभी भी गरीबी में है उसे हमें गरीबी से बाहर लाना है।

हमारे देश में गरीबों के नाम पर जो जुमले चले, उसी गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन 2014 तक इस देश के 50 करोड़ नागरिक ऐसे थे जिन्होंने बैंक का दरवाजा तक नहीं देखा था।

गरीब को बैंक में प्रवेश तक नहीं था यह पाप आपने किया और आज 50 करोड़ गरीबों के बैंक खाता खोल करके हमने बैंक के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए हैं। इतना ही नहीं एक प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 1 रूपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन उपाय उनको आता नहीं था उपाय हमने दिखाया आज दिल्ली से1 रूपया निकलता है तो 100 के 100 पैसे गरीब के खाते में जमा होते हैं।

देश के अंदर जिन लोगों को बैंक के दरवाजे तक जाने की इजाजत नहीं थी। आज बिना गारंटी वह बैंक से लोन ले सकते है यह ताकत हमने गरीबों को दी है।

गरीबी हटाओ का जुमला इसी के कारण जुमला बन कर के रह गया। गरीब को इस मुश्किल से मुक्ति मिले यह हमारा बहुत बड़ा मिशन और यह हमारा संकल्प है और हम इसके लिए दिन-रात एक कर रहे हैं। जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूजता है।

दिव्यांगजन हर दिन संघर्ष करता है। अब जाकर के हमारे दिव्यांग को फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसकी व्हीलचेयर ट्रेन के डिब्बे तक जाए, यह व्यवस्था हुई।

एक तो भाषा के नाम पर झगड़ा करना तो सिखा दिया आपने, लेकिन मेरे दिव्यांग जनों के साथ कितना अन्याय किया। जो हमारे यहां साइन लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज की जो व्यवस्था है खास करके मूक बधिर के लिए। अब दुर्भाग्य ऐसा देश का कि असम में जो भाषा सिखाई जाए उत्तर प्रदेश में दूसरी सिखाई जाए। उत्तर प्रदेश में सिखाया जाए महाराष्ट्र में तीसरी। दिव्यांग जनों के लिए एक साइन लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी था। आजादी के सात दशक बाद भी उनको उन दिव्यांग जनों की याद नहीं आई। एक कॉमन साइन लैंग्वेज बनाने का काम हमने किया जो आज देश के सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए काम आ रही है।

घुमंतू और अर्ध घुमंतू जन समूह समाज, उनके कल्याण के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने का काम हमने किया, क्योंकि यह संविधान की प्राथमिकता है।

हर कोई रेहड़ी पटरी के लोगों को जानता है, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर फ्लैट में ,हर सोसाइटी में, सुबह होते ही वो रेहड़ी पटरी वाला आकर के मेहनत करके और लोगों का जीवन चलाने में मदद करता है उसको बेचारे को 12-12 घंटे काम करें, रेहड़ी भी किसी से किराए पर ले लें, किसी से ब्याज पर पैसा ले, पैसे से सामान खरीदे, शाम को ब्याज का वह पैसा ले जाए। बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों के लिए ब्रेड का टुकड़ा ले जा सके यह हालत थी। यह हमारी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना बनाकर के बैंक से उनका बिना गारंटी लोन देने का शुरू किया और आज स्वनिधि योजना के कारण वह तीसरे राउंड तक पहुंचा है और अधिकतम loan बैंक से उसको सामने से मिल रहा है उसकी प्रतिष्ठा का और विकास हो रहा है, विस्तार भी हो रहा है।

इस देश में हममे से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको विश्वकर्मा की जरूरत ना पड़ती हो। लेकिन विश्वकर्मा साथियों को कभी पूछा नहीं गया। हमने विश्वकर्मा के कल्याण के लिए योजना बनाई, बैंक से लोन लेने की व्यवस्था की, उनको नई ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की, उनको आधुनिक टूल देने की व्यवस्था की, नई डिजाइन से काम बनाने की चिंता की और उसको हमने मजबूत बनाने का काम किया।

ट्रांसजेंडर जिसको परिवार ने दुतकार दिया, समाज ने दुतकार दिया, जिसकी कोई चिंता करने वाला नहीं था, यह हमारी सरकार है कि इसको भी भारत के संविधान में हक दिए हैं, उस ट्रांसजेंडर के अधिकारों के लिए कानून व्यवस्थाएं बनाने का काम भी किया। उनको गरिमा पूर्ण जीवन मिले उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमने काम किया।

गुजरात का पूर्वी हिस्सा पूरा आदिवासी बेल्ट और एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री आदिवासी रह चुके थे। इतने सालों के बाद भी उस पूरे इलाके में एक भी साइंस स्ट्रीम का स्कूल नहीं था। अगर साइंस स्ट्रीम का स्कूल नहीं है तो कितनी आरक्षण की बातें करो वह बेचारा इंजीनियर और डॉक्टर कैसे बन सकता है ये मैंने उस इलाके में काम किया। और अब वहां साइंस स्ट्रीम के स्कूल हैं, अब तो वहां यूनिवर्सिटीज बन गई हैं।

हमने आदिवासी समाज में भी जो अति पिछड़े लोग हैं और उसमें मैं राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने मेरा काफी मार्गदर्शन किया। अब उसमें से पीएम जन मन योजना बनी, हमारे देश में पिछड़ी-पिछड़े आदिवासी समाज के छोटे-छोटे समूह हैं जिनको आज भी, कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई थी, हमने ढूंढ-ढूंढकर के संख्या बहुत कम है, वोट की राजनीति में उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन मोदी है जो आखिरी को भी ढूंढता है और इसलिए हमने उनके लिए पीएम जन मन योजना के द्वारा उनका विकास किया।

जैसे समाजों में उनके विकास संतुलित होना चाहिए। पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी संविधान अवसर देता है। जिम्मेदारी भी संविधान देता है, उसी प्रकार से कोई भू भाग भी कोई हमारा जियोग्राफिकल इलाका भी वो पीछे नहीं रहना चाहिए और हमारे देश में किया क्या, 60 साल के दर्मियान 100 डिस्ट्रिक्ट आईडेंटिफाई करके कह दिया कि ये तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का ऐसा लेबल लग गया कि किसी की ट्रांसफर होती थी तो वो कहता था पनिशमेंट पोस्टिंग। तो कोई जिम्मेवार अफसर जाता ही नहीं था, हमने पूरी स्थिति को बदल दिया। हमने एसपिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की एक कल्पना रखी और 40 पैरामीटर पर ऑनलाइन रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहे और आज एसपिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उस राज्य के अच्छे जिलों की बराबरी करने लग गए और कुछ तो नेशनल एवरेज की बराबरी करने लगे। भू भाग भी पीछे ना रहे कोई जिला अब इसको आगे ले जाकर के हमने 500 ब्लॉक को एसपिरेशनल ब्लॉक बनाकर के उनके डेवलप पर स्पेशल

फोकस करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

इस देश में आदिवासी समाज 1947 के बाद आया है क्या? क्या राम और कृष्ण थे तब आदिवासी समाज था कि नहीं था? लेकिन आजादी के कई दशकों के बाद भी इतना बड़ा आदिवासी समूह उनके लिए अलग मंत्रालय नहीं बनाया गया। पहली बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई और उन्होंने अलग आदिवासी मंत्रालय बनाया। अलग आदिवासी विकास और विस्तार के लिए बजट दिया।

मछुवारा समाज क्या अभी आया है क्या? इन मछुवारे समाज के कल्याण के लिए पहली बार हमारी सरकार ने आकर के अलग मंत्रालय बनाया है फिशरिज का, उनके कल्याण के लिए अलग से हमने बजट दिया, समाज के इस तबके की भी चिंता की।

छोटा किसान, उसके जीवन में सहकारिता एक मुख्य अंग है। छोटे किसान की जिंदगी को सामर्थ्य देने के लिए सहकारिता क्षेत्र को जिम्मेदार बनाना, सहकारिता क्षेत्र को सामर्थ्यवान बनाना, सहकारिता क्षेत्र को बल देना, इसकी महात्म्य हम समझते हैं क्योंकि छोटा किसान उसकी चिंता हमारे दिल में थी और इसलिए हमने अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया। हमारी सोचने का तरीका क्या है, हमारे देश में नौजवान है, पूरा विश्व आज वर्क फोर्स के लिए तरस रहा है। देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड लेना है तो हमारे इस वर्क फोर्स को स्किल्ड बनाना चाहिए। हमने अलग स्किल मंत्रालय बनाया ताकि दुनिया की आवश्यकता के अनुसार मेरे देश का नौजवान तैयार हो और विश्व के साथ वो आगे बढ़े।

हमारा नॉर्थ-ईस्ट इसलिए कि वहां वोट कम है, सीटें कम हैं इसकी कोई परवाह नहीं है। ये अटल जी की सरकार थी जिसने पहली बार नॉर्थ-ईस्ट के कल्याण के लिए डोर्नियर मंत्रालय की व्यवस्था की और आज उसका परिणाम है कि नॉर्थ-ईस्ट के विकास की नई चीजों को हम प्राप्त कर पाए। इसी के कारण रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये बनने की इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

आज भी दुनिया के देशों में लैंड रिकॉर्ड को लेकर के समृद्ध देशों को भी कई संकट हैं। हमने गांव के हर सामान्य व्यक्ति को अपना लैंड रिकॉर्ड उसके घर के मालिकाना हक के कागज नहीं है, उसके कारण उसको बैंक से लोन चाहिए जो, कहीं बाहर जाए तो कोई कब्जा कर ले, एक स्वामित्व योजना बनाई और देश के, गांव के ऐसे समाज के दबे-कुचले लोगों को वो कागज हम दे रहे हैं जिसके कारण उसका मालिकाना हक बन रहा है, वो स्वामित्व योजना एक बहुत बड़ा दिशा दे रहा है।

इन सारे कामों के कारण पिछले 10 वर्ष में हमने जो प्रयास किया, हमने जिस प्रकार से गरीब को मजबूती देने का काम किया है। हमने जिस प्रकार से गरीब के अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है और एक सही दिशा में चलने का परिणाम है कि इतने कम समय में मेरे देश के 25 करोड़ मेरे गरीब साथी गरीबी को परास्त करने में सफल हुए हैं और हमें इस बात का गर्व है और मैं संविधान निर्माताओं के सामने सर झुकाकर के कहता हूं जो संविधान हमें ये दिशा दे रहा है, उसके तहत मैं ये काम कर रहा हूं ।

जब हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, वो नारा नहीं है। वो हमारे आर्टिकल ऑफ फेथ है और इसलिए हमने सरकार की योजनाएं भी बिना भेदभाव के चलाने की दिशा में काम किया है और संविधान हमें भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। सैचुरेशन, जिसके लिए जो योजना बनी है उसका लाभ उन लाभार्थी को 100 प्रतिशत मिलना चाहिए। ये सैचुरेशन अगर सच्चा, सच्चा सेक्युलरिज्म कोई है ना तो ये सैचुरेशन में है। सच्चा सामाजिक न्याय अगर किसी में है तो ये सैचुरेशन, 100 प्रतिशत, शत प्रतिशत उसको बेनिफिट जिसको जिसका हक है मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए। तो ये भाव को लेकर के हम सच्चे सेक्युलरिज्म को और सच्चे सामाजिक न्याय को लेकर के जी रहे हैं।

संविधान की एक और स्पिरिट भी है, देश को दिशा देने का माध्यम, देश के चालक बल के रूप में राजनीति केंद्र में रहती है। आने वाले दशकों में लोकतंत्र, राजनीति की दिशा क्या होनी चाहिए, हमें मंथन करना चाहिए।

क्या इस देश में योग्य नेतृत्व को अवसर मिलना चाहिए कि नहीं? जिनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, क्या उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे? क्या देश को, लोकतंत्र की स्पिरिट को परिवारवाद ने गहरा नुकसान किया है कि नहीं किया है? क्या परिवारवाद से भारत के लोकतंत्र की मुक्ति का अभियान चलाना, ये संविधान के तहत हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? जो परिवारवादी राजनीति है उनकी धुरी ही परिवार होता है, सब कुछ परिवार के लिए। देश को, देश के नौजवानों को आकर्षित करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और देश के युवाओं को आगे आने के लिए हम सभी राजनीतिक दलों ने प्रयास करना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों ने जिनकी पार्श्व भूमि में राजनीतिक परिवार नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड को लाने के लिए प्रयास करना, देश के लोकतंत्र की और इसलिए मैंने लाल किले से कहा है कि मेरा एक विषय लेकर मैं लगातार बोल रहा हूं, बोलता रहूंगा,1 लाख ऐसे नौजवानों को देश की राजनीति में लाना है, जिनका कोई परिवार का बैकग्राउंड राजनीतिक परिवार का नहीं है और इसलिए देश को एक फ्रेश एयर की जरूरत है, देश को नई ऊर्जा की जरूरत है, देश को नए संकल्प और सपने लेकर के आने वाले युवकों की जरूरत है और भारत संविधान के जब 75 वर्ष मना रहा है तब हम उस दिशा में आगे बढ़े।

हमारे संविधान ने नागरिकों के अधिकार तय किए हैं, लेकिन संविधान को हम से कर्तव्य की भी अपेक्षा है और हमारी सभ्यता का सार है धर्म, ड्यूटी, कर्तव्य, ये हमारी सभ्यता का सार है । और महात्मा जी का Quote है, उन्होंने कहा था मैंने ये अपनी अशिक्षित लेकिन विद्वान मां से सीखा है कि हम अपने कर्तव्यों को जितना अच्छे से निभाते हैं, उसी से अधिकार निकल करके आता है। मैं महात्मा जी की बात को आगे बढ़ाता हूं और मैं कहना चाहूंगा अगर हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो कोई भी हमें विकसित भारत बनाने से नहीं रोक सकता है। संविधान का 75 वां वर्ष कर्तव्य के प्रति हमारे समर्पण भाव को, हमारी प्रतिबद्धता को और ताकत दे, देश कर्तव्य भावना से आगे बढ़े, ये मैं मानता हूं कि यही समय की मांग है।

भारत के भविष्य के लिए संविधान की स्पिरिट से प्रेरित होकर के 11 संकल्प रखना चाहता हूं।

पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें।

दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ सबका विकास हो।

तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता ना हो,

चौथा संकल्प है, देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो।

पांचवा संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो।

छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले।

सातवां संकल्प, संविधान का सम्मान हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार ना बनाया जाए।

आठवां संकल्प, संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है, वो ना छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे।

नौवां संकल्प, विमेन लेड डेवलेपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने।

दसवां संकल्प, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो।

ग्यारहवां संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। ▪

संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा

मोदी सरकार संघवाद का सम्मान करती है : जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 17 दिसंबर, 2024 को भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्यसभा में आयोजित चर्चा में भाग लिया। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि हम सब जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, लेकिन यह प्रजातंत्र की जननी भी है। प्रजातंत्र में समाज में स्वतंत्रता, स्वीकार्यता, समानता और समावेशिता शामिल होती है। उन्होंने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए संसद को धन्यवाद दिया। हम यहां उनके भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं:

कुछ ही दिन बाद हम अपने गणतंत्र के 75 साल पूरे होते हुए देखेंगे। यह उत्सव एक तरीके से हमारी संविधान के प्रति समर्पण, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करता है। हम सब जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, लेकिन यह प्रजातंत्र की जननी भी है। प्रजातंत्र में समाज में स्वतंत्रता, स्वीकार्यता, समानता और समावेशिता शामिल होती है। इससे आम नागरिक सम्मानजनक जीवन जी पाते हैं। संविधान की मूल प्रति में भी अजंता एलोरा की गुफाओं की छाप दिखती है। हम सबको उसमें कमल की भी छाप दिखती है और कमल इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि हम कीचड़ में से निकलकर नए संविधान के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं।

हमारा संविधान भी उस कमल के माध्यम से हमें यह प्रेरणा देता है कि हम तमाम मुसीबतों के बावजूद प्रजातंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अनुच्छेद 370 के ही विरोध में उस समय के जनसंघ के संस्थापक ने आवाज उठाते हुए कहा कि एक देश में 'दो निशान, दो विधान और दो प्रधान' नहीं चलेंगे। उन्होंने इसके लिए बलिदान दिया। राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 में धारा 35A लाई गई और संसद में कोई बहस किए बिना इस धारा को राष्ट्रपति की स्वीकृति दी गई। भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए अनेक कानून जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होते थे।

हमारा संविधान भी उस कमल के माध्यम से हमें यह प्रेरणा देता है कि हम तमाम मुसीबतों के बावजूद प्रजातंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

अनुच्छेद 370 के ही विरोध में उस समय के जनसंघ के संस्थापक ने आवाज उठाते हुए कहा कि एक देश में 'दो निशान, दो विधान और दो प्रधान' नहीं चलेंगे। उन्होंने इसके लिए बलिदान दिया।

आज जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है

जम्मू-कश्मीर में पंजाब से सफाई कर्मचारियों को लाया गया और उनको बसाया गया । उनको जम्मू-कश्मीर की नागरिकता तो दी गई, लेकिन उनकी सिर्फ सफाई कर्मचारी की ही नौकरी का अधिकार था। वे कुछ और नहीं कर सकते थे। इस तरह से आजाद भारत में कानून का उल्लंघन हो रहा था । मैं इस संसद को धन्यवाद देता हूं कि उसने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और आज जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न गया है।

अगले साल 25 जून को आपातकाल लगाए जाने के 50 साल हो जाएंगे, हम 'लोकतंत्र विरोधी दिवस' मनाएंगे। हम आह्वान करते हैं कि कांग्रेस भी उसमें शामिल हो। आपातकाल इसलिए नहीं लगा कि देश को कोई खतरा था, बल्कि इसलिए लगा कि सत्ताधारी दल की सत्ता को खतरा था और इस कारण 25 जून, 1975 को राष्ट्रपति की सम्मति के

द्वारा भारतीय संविधान के अंतर्गत आंतरिक अशांति कारण बताते हुए मूल अधिकारों, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को निलंबित कर दिया गया। आपातकाल के दौरान लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मीसा और डीआईआर में 22-22 महीने के लिए बंदी हुए ।

अल्पसंख्यक तुष्टीकरण

अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की भी बात करना चाहता हूँ । राजीव गाँधी जी को प्रगतिशील बताया गया, लेकिन वह अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त करने के लिए संसद में संशोधन ले आए। उच्चतम न्यायालय ने कई बार कहा था कि तीन तलाक समाप्त होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया, जबकि कई इस्लामी देशों में भी तीन तलाक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की दूर दृष्टि और पक्के इरादे से तीन तलाक को समाप्त किया गया और मुस्लिम बहनों को मुख्यधारा में लाने का काम किया।

पं. नेहरू ने सीमा के बुनियादी ढांचे सहित रक्षा तैयारियों की उपेक्षा की

कांग्रेस पार्टी ने न तो भू-क्षेत्रों को सौंपने के संदर्भ में भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की है और न ही हमारे पड़ोस में भारत के प्रभाव को कम करने के प्रयासों का मुकाबला किया है। 1949 में हमारी बहादुर सेना ने युद्ध के मैदान में सफलता हासिल की थी, लेकिन पंडित नेहरू ने युद्ध विराम स्वीकार किया था । यही कारण है कि आज भी 'पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर' मौजूद है। सभा यह भी जानती है कि चीन ने 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और पाकिस्तान ने उसे 5,180 वर्ग किलोमीटर का अवैध हस्तांतरण किया था।

चीन ऐसा इसलिए कर सका क्योंकि श्री जवाहरलाल नेहरू ने सीमा के बुनियादी ढांचे सहित रक्षा तैयारियों की उपेक्षा की और उन्हें कूटनीति की समझ नहीं थी । जहां तक म्यांमार का सवाल है, 1950 के दशक में कोको द्वीप समूह पर हमारे नियंत्रण के हस्तांतरण की परिस्थितियां आज भी अस्पष्ट हैं। हमने 2008 से 2010 के बीच हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालने वाले घटनाक्रमों के बारे में लापरवाही का रिकॉर्ड भी देखा है। जब चीन ने श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह बनाया, तब हम चुपचाप देखते रहे।

मालदीव में 2012 में एक भारत विरोधी आंदोलन के कारण प्रमुख क्षेत्रों में भारतीय निवेश बाहर हो गया। इसका भी कांग्रेस ने हमेशा विरोध नहीं किया। एक द्वीप है कच्चातीवू जो 1974 में श्रीलंका को सौंपे जाने से पहले तमिलनाडु के अधिकार क्षेत्र में था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने इसे एकतरफा तौर पर श्रीलंका को दे दिया और यह हस्तांतरण भारत के संविधान में संशोधन किए बिना निष्पादित किया गया, जिससे महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी प्रश्न उठे ।

इसी तरह, दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 16 मई, 1974 को भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसे अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। 1974 से 2015 तक कोई अनुसमर्थन नहीं हुआ था। 2015 में सरकार ने समझौते को अंतिम रूप दिया और क्षेत्रीय परिवर्तनों के अंतरराष्ट्रीय समझौते पर सहमति बनी और संसद द्वारा इसका अनुसमर्थन किया गया। मोदी सरकार संघवाद का सम्मान करती है, इसीलिए केंद्र सरकार ने त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल के साथ विचार-विमर्श किया और उनमें से प्रत्येक की सहमति लेने के बाद भूमि सीमा समझौता किया गया और बांग्लादेश में लगभग 111 भारतीय इन्क्लेव और भारत में 51 बांग्लादेशी इन्क्लेव को पुनर्स्थापित किया गया और 50,000 की आबादी को समझौते के तहत लाया गया ।

आप लोगों को जानना चाहिए कि संविधान सभा में जो लोग थे, जिन लोगों ने बाद में आकर देश को चलाया, उनके मन में आरक्षण के प्रति क्या भावना थी। संविधान में अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से अंतर किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह अंतर क्यों किया? उनके दिमाग में कुछ था। आज हम उस अंतर को क्यों खो चुके हैं? मैं आपसे सहमत हूं, वास्तविकता यह है कि इस देश में जाति का बहुत महत्व है। मैं इससे असहमत नहीं हूं। यदि हमारा लक्ष्य जातिविहीन समाज है, तो आपका हर बड़ा कदम ऐसा होना चाहिए जिससे आप जातिविहीन समाज की ओर बढ़े। जिन्होंने 55 साल राज किया, मैंने उनका मत आपके सामने रखा है। काका कालेलकर रिपोर्ट पर आप 22 साल तक बैठे रहे, लेकिन आपने आरक्षण के बारे में कुछ नहीं सोचा। मंडल आयोग कौन लेकर आया? जनता पार्टी की सरकार इसे लेकर आई। राजीव गांधी जी ने तथ्यात्मक त्रुटियों का हवाला देते हुए और रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए मंडल आयोग की रिपोर्ट के क्रियान्वयन का विरोध किया था। आपने पिछड़े वर्ग के साथ कितना अन्याय किया।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा

अब अगर मैं सामाजिक न्याय की बात करूं, तो अनुच्छेद 338ख के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नरेन्द्र मोदी जी की सरकार द्वारा दिया गया। उसी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करके सामाजिक न्याय देने का काम किया गया। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय को आरक्षण भी नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने दिया। अगर में राजनीतिक न्याय की बात करूं, तो अनुच्छेद 370 को समाप्त करके जम्मू-कश्मीर को राजनीतिक न्याय देने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया।

जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को अधिकार देकर राजनीतिक न्याय देने का काम भी अनुच्छेद 370 को समाप्त करके हमारी सरकार द्वारा किया गया।

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को पारित करके महिलाओं को आरक्षण देने का काम भी हमारी सरकार द्वारा ही किया गया । हमने ट्रिपल तलाक का उन्मूलन करके मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का प्रयास भी किया। अगर मैं आर्थिक न्याय की बात करूं, तो मुद्रा योजना, जन-धन खाते, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आदि के जरिए आर्थिक न्याय दिया गया।

प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत के अंतर्गत 61 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष स्वास्थ्य सुरक्षा देना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ▪

संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा

मोदी सरकार ने मातृशक्ति को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया: अमित शाह

हमारे संविधान में भगवान राम, बुद्ध और महावीर, दसवें गुरु गोविंद सिंह के भी चित्र मिलेंगे। इसके साथ-साथ गुरुकुल के माध्यम से हमारी शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, इसका संदेश भी मिलता है।

इसी प्रकार, भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण को एक प्रकार से हमारे अधिकारों का चित्रण करते हुए दिखाया गया है। भगवत गीता के संदेश के चित्र, शिवाजी महाराज और लक्ष्मीबाई को भी संविधान में स्थान देकर देशभक्ति का पाठ हमें सिखाया गया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 17 दिसंबर, 2024 को संविधान की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राज्यसभा में आयोजित चर्चा में भाग लिया। इस दौरान श्री शाह ने सामाजिक न्याय को मजबूत करने ओर हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार के विभिन्न संवैधानिक संशोधनों को रेखांकित किया। हम यहां भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं:

चर्चा का जवाब देते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि ये चर्चा एक ओर जनता को ये अहसास कराएगी कि संविधान के कारण हमारा देश कितना आगे बढ़ा और दूसरी ओर संविधान की मूल भावना के कारण ही 75 साल में लोकतंत्र की जड़ें गहरी होने का अहसास भी कराएगी। इसके साथ ही ये भी अहसास होता है कि जब संविधान की भावनाओं के साथ कोई छेड़छाड़ का प्रयास करता है तो किस प्रकार की घटनाएं होती हैं। संविधान पर दोनों सदनों में हुई चर्चा हमारे किशोरों और युवा पीढ़ी के साथ-साथ संसद में बैठकर देश के भविष्य का निर्णय करने वालों के लिए शिक्षाप्रद साबित होगी।

हमारा संविधान, संविधान सभा और संविधान की रचना की प्रक्रिया दुनिया के सभी संविधानों में अनूठी है। हमारे यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा विस्तृत और लिखित संविधान, चर्चा के हमारे पारंपरिक लक्षणों के साथ बनाया गया है।

हमारे संविधान में भगवान राम, बुद्ध और महावीर, दसवें गुरु गोविंद सिंह के भी चित्र मिलेंगे। इसके साथ-साथ गुरुकुल के माध्यम से हमारी शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, इसका संदेश भी मिलता है। इसी प्रकार, भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण को एक प्रकार से हमारे अधिकारों का चित्रण करते हुए दिखाया गया है। भगवत गीता के संदेश के चित्र, शिवाजी महाराज और लक्ष्मीबाई को भी संविधान में स्थान देकर देशभक्ति का पाठ हमें सिखाया गया है।

विपक्षी पार्टी ने 55 साल के अपने शासन में 77 संविधान परिवर्तन किए

हमारे संविधान को कभी भी अपरिवर्तनशील नहीं माना गया है और समय के साथ देश, कानून और समाज को बदलना चाहिए। संविधान के अंदर ही अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए प्रावधान किया गया है। हमारी पार्टी ने 16 साल राज किया, 6 साल अटल जी ने, 10 साल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया और 5 साल और प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। हमारी सरकार ने 22 बार संविधान में परिवर्तन किए। विपक्षी पार्टी ने 55 साल के अपने शासन में 77 संविधान परिवर्तन किए।

पहला संशोधन 18 जून, 1951 को हुआ

जिसे संविधान सभा ने ही किया । इस संशोधन में 19ए को जोड़ा गया, इसका उद्देश्य क्या था और इसे किस लिए जोड़ा गया? अभिव्यक्ति की आजादी को curtail करने लिए किया गया। ये संशोधन किसने किया, उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे। पहला संविधान संशोधन अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने के लिए लाया गया था और इसे जवाहरलाल नेहरू के लिए लाया गया था।

24वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी की पार्टी 5 नवंबर, 1971 को लाई थी। 24वें संशोधन के माध्यम से संसद को नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का अधिकार दे दिया गया। 39वें संविधान संशोधन ने सभी सीमाओं को पार कर दिया। 10 अगस्त, 1975 का वह दिन हमारे संविधान के इतिहास में हमेशा काले अक्षरों में दर्ज रहेगा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अमान्य करार दिया था। इंदिरा जी ने संविधान संशोधन से प्रधानमंत्री पद की न्यायिक जांच पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये संविधान संशोधन retrospective effect से किया गया था, यानी पुराना मुकदमा भी है तो वह खारिज हो जाएगा।

श्रीमती इंदिरा गांधी ही 42वां संविधान संशोधन लेकर आईं थी जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़कर 6 साल कर दिया गया था। ऐसा इसी भय से किया था कि उस वक्त चुनाव होते तो वे हार जाते, इसीलिए लोकसभा के कार्यकाल को ही लंबा कर दिया जाए। इतनी निर्लज्जता के साथ विश्व में कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ।

देश के अर्थतंत्र को लय में लाने के लिए जीएसटी को लागू किया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ये सरकार अपना पहला और 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई, 2017 को लाई जब देश के अर्थतंत्र को लय में लाने के लिए जीएसटी को लागू किया गया।

कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक फैले इस विशाल देश को जीएसटी के तहत लोगों की परेशानी को खत्म कर एक कानून लाने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने लोगों की भलाई के लिए किया ।

हम दूसरा संशोधन लाए, 102वां संशोधन नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। मोदी सरकार तीसरा संशोधन 12 जनवरी, 2019 को लाई जिसके तहत किसी भी प्रकार का आरक्षण का फायदा न पाने वाली गरीब जाति के बच्चों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया।

पहले ओबीसी की पहचान करने के लिए केन्द्र के पास अधिकार थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 10 अगस्त, 2021 को लाए गए 105वें संशोधन के बाद पिछड़ेपन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया। मोदी सरकार का चौथा और कुल 106वां संविधान संशोधन 28 दिसंबर, 2023 को लाया गया था।

मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर मातृशक्ति को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया। दोनों सदनों में 33 प्रतिशत नारी शक्ति की उपस्थिति होने से संविधान निर्माताओं का सपना पूरा हो सकेगा।

जब मोदी सरकार सत्ता में आई तब महू में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। हमने 14 अप्रैल को 'राष्ट्रीय समरसता दिवस' घोषित किया। धारा 370 के एक टेंपरेरी प्रोविजन को अपनी गोद में 70 साल तक विपक्षी पार्टी ने खिलाने का काम किया। धारा 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए और जब श्री नरेन्द्र मोदी जी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने एक ही बार में 370 और 35A को समाप्त कर दिया है। संविधान के मूल्य हमारे लिए सर्वोपरि हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक जीवंत दस्तावेज दिया है जो युगानुकूल परिवर्तन की जरूरत के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है।

बाबा साहब अम्बेडकर सहित अन्य संविधान निर्माताओं ने भी यह माना था कि संविधान भविष्य की सभी संभावनाओं को नहीं भांप सकता है। इसलिए उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया था।

वर्तमान सरकार ने पिछले दस वर्षों में जो भी संवैधानिक संशोधन किए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन सभी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक मूल्यों को सशक्त करना था, सामाजिक कल्याण था, लोगों का सशक्तीकरण था । चाहे वह अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जाना हो या महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण के लिए नारी वंदन अधिनियम हो या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण हो या जीएसटी कानून हो, यह कार्य संघवाद के संवैधानिक सिद्धांत को कायम रखते हुए सभी को साथ लेकर चलने के हमारे प्रयास को दर्शाता है।

कांग्रेस ने किया संविधान बदलने का प्रयास

आजाद भारत के इतिहास में कांग्रेस ने सिर्फ संविधान संशोधन ही नहीं किया है, बल्कि धीरे-धीरे संविधान को बदलने का प्रयास भी किया है। कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए अधिकांश संवैधानिक संशोधन या तो विरोधियों और आलोचकों को चुप कराने के लिए किए गए या गलत नीतियों को लागू करने के लिए किए गए थे। क्या यह सब एक तानाशाह द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए संविधान को विकृत करने का भरसक प्रयास नहीं था?

जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है और संविधान में लोक सभा कार्यकाल भी बढ़ाकर छह साल कर दिया गया।

75 वर्षों के बाद आज हमें अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत का संविधान भारतवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम साबित हुआ है ।

हमें बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य के प्रति आभारी होना चाहिए। डॉ. अंबेडकर ने उसमें कहा था कि जिन लोगों पर देश चलाने की जिम्मेदारी है, उनकी भूमिका सकारात्मक हो। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा संविधान सबसे उत्कृष्ट दिमागों की एक कड़ी मेहनत और दृष्टि का परिणाम है। हमारा संविधान हर मामले में एक महान दस्तावेज है।

हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार संविधान की पवित्रता को किसी भी सूरत में भंग नहीं होने देगी। ▪

राष्ट्र निर्माण के 'अटल' आदर्श की शताब्दी- नरेन्द्र मोदी

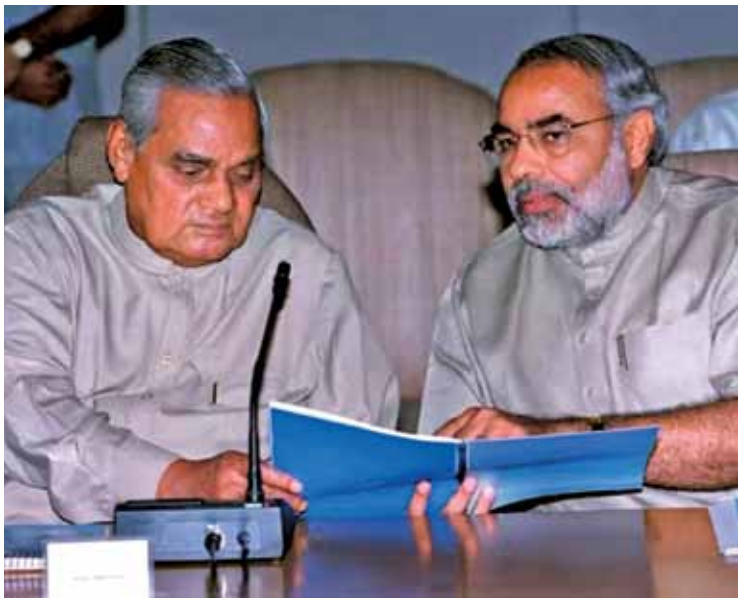

मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं ...
लौटकर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं?

अटल जी के ये शब्द कितने साहसी हैं... कितने गूढ़ हैं। अटल जी, कूच से नहीं डरे... उन जैसे व्यक्तित्व को किसी से डर लगता भी नहीं था। वो ये भी कहते थे...

जीवन बंजारों का डेरा आज यहां,
कल कहां कूच है...
कौन जानता किधर सवेरा...

आज अगर वो हमारे बीच होते, तो वो अपने जन्मदिन पर नया सवेरा देख रहे होते। मैं वो दिन नहीं भूलता जब उन्होंने मुझे पास बुलाकर अंकवार में भर लिया था... और जोर से पीठ में धौल जमा दी थी। वो स्नेह... वो अपनत्व... वो प्रेम... मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है।

25 दिसंबर का दिन भारतीय राजनीति और भारतीय जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का अटल दिवस है। पूरा देश अपने भारत रत्न अटल को, उस आदर्श विभूति के रूप में याद कर रहा है, जिन्होंने अपनी सौम्यता, सहजता और सहृदयता से करोड़ों भारतीयों के मन में जगह बनाई। पूरा देश उनके योगदान के प्रति कृतज्ञ है। उनकी राजनीति के प्रति कृतार्थ है।

25 दिसंबर का दिन भारतीय राजनीति और भारतीय जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का अटल दिवस है।

पूरा देश अपने भारत रत्न अटल को, उस आदर्श विभूति के रूप में याद कर रहा है, जिन्होंने अपनी सौम्यता, सहजता और सहृदयता से करोड़ों भारतीयों के मन में जगह बनाई। पूरा देश उनके योगदान के प्रति कृतज्ञ है। उनकी राजनीति के प्रति कृतार्थ है।

21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए उनकी एनडीए सरकार ने जो कदम उठाए, उसने देश को एक नई दिशा, नई गति दी। 1998 के जिस काल में उन्होंने पीएम पद संभाला, उस दौर में पूरा देश राजनीतिक अस्थिरता से घिरा हुआ था। 9 साल में देश ने चार बार लोकसभा के चुनाव देखे थे। लोगों को शंका थी कि ये सरकार भी उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसे समय में एक सामान्य परिवार से आने वाले अटल जी ने, देश को स्थिरता और सुशासन का मॉडल दिया। भारत को नव विकास की गारंटी दी।

वो ऐसे नेता थे, जिनका प्रभाव भी आज तक अटल है। वो भविष्य के भारत के परिकल्पना पुरुष थे। उनकी सरकार ने देश को आईटी, टेलीकम्यूनिकेशन और दूरसंचार की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ाया। उनके शासन काल में ही, एनडीए ने टेक्नॉलाजी को सामान्य मानवी की पहुंच तक लाने का काम शुरू किया। भारत के दूर-दराज के इलाकों को बड़े शहरों से जोड़ने के सफल प्रयास किये गए। वाजपेयी जी की सरकार में शुरू हुई जिस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने भारत के महानगरों

को एक सूत्र में जोड़ा वो आज भी लोगों की स्मृतियों पर अमिट है। लोकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी एनडीए गठबंधन की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए। उनके शासन काल में दिल्ली मेट्रो शुरू हुई, जिसका विस्तार आज हमारी सरकार एक वर्ल्ड क्लास इंन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में कर रही है। ऐसे ही प्रयासों से उन्होंने ना सिर्फ आर्थिक प्रगति को नई शक्ति दी, बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़कर भारत की एकता को भी सशक्त किया।

जब भी सर्व शिक्षा अभियान की बात होती है, तो अटल जी की सरकार का जिक्र जरूर होता है। शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानने वाले वाजपेयी जी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था, जहां हर व्यक्ति को आधुनिक और गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। वो चाहते थे भारत के वर्ग, यानि ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी और महिला सभी के लिए शिक्षा सहज और सुलभ बने।

उनकी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई बड़े आर्थिक सुधार किए। इन सुधारों के कारण भाई-भतीजावाद में फंसी देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। उस दौर की सरकार के समय में जो नीतियां बनीं, उनका मूल उद्देश्य सामान्य मानवी के जीवन को बदलना ही रहा।

उनकी सरकार के कई ऐसे अद्भुत और साहसी उदाहरण हैं, जिन्हें आज भी हम देशवासी गर्व से याद करते है। देश को अब भी 11 मई 1998 का वो गौरव दिवस याद है, एनडीए सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद पोकरण में सफल परमाणु परीक्षण हुआ। इसे 'ऑपरेशन शक्ति' का नाम दिया गया।

इस परीक्षण के बाद दुनियाभर में भारत के वैज्ञानिकों को लेकर चर्चा होने लगी। इस बीच कई देशों ने खुलकर नाराजगी जताई, लेकिन तब की सरकार ने किसी दबाव की परवाह नहीं की। पीछे हटने की जगह 13 मई को न्यूक्लियर टेस्ट का एक और धमाका कर दिया गया। 11 मई को हुए परीक्षण ने तो दुनिया को भारत के वैज्ञानिकों की शक्ति से परिचय कराया था। लेकिन 13 मई को हुए परीक्षण ने दुनिया को ये दिखाया कि भारत का नेतृत्व एक ऐसे नेता के हाथ में है, जो एक अलग मिट्टी से बना है।

उन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया, ये पुराना भारत नहीं है। पूरी दुनिया जान चुकी थी, कि भारत अब दबाव में आने वाला देश नहीं है। इस परमाणु परीक्षण की वजह से देश पर प्रतिबंध भी लगे, लेकिन देश ने सबका मुकाबला किया।

वाजपेयी सरकार के शासन काल में कई बार सुरक्षा संबंधी चुनौतियां आईं। करगिल युद्ध का दौर आया। संसद पर आतंकियों ने कायराना प्रहार किया। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले से वैश्विक स्थितियां बदलीं, लेकिन हर स्थिति में अटल जी के लिए भारत और भारत का हित सर्वोपरि रहा।

जब भी आप वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में किसी से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेते थे। उनकी बोलने की कला का कोई सानी नहीं था। कविताओं और शब्दों में उनका कोई जवाब नहीं था। विरोधी भी वाजपेयी जी के भाषणों के मुरीद थे। युवा सांसदों के लिए वो चर्चाएं सीखने का माध्यम बनतीं।

कुछ सांसदों की संख्या लेकर भी, वो कांग्रेस की कुनीतियों का प्रखर विरोध करने में सफल होते। भारतीय राजनीति में वाजपेयी जी ने दिखाया, ईमानदारी और नीतिगत स्पष्टता का अर्थ क्या है।

संसद में कहा गया उनका ये वाक्य... सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी मगर ये देश रहना चाहिए... आज भी मंत्र की तरह हम सबके मन में गूंजता रहता है।

वो भारतीय लोकतंत्र को समझते थे। वो ये भी जानते थे कि लोकतंत्र का मजबूत रहना कितना जरुरी है। आपातकाल के समय उन्होंने दमनकारी कांग्रेस सरकार का जमकर विरोध किया, यातनाएं झेली। जेल जाकर भी संविधान के हित का संकल्प दोहराया। NDA की स्थापना के साथ उन्होंने गठबंधन की राजनीति

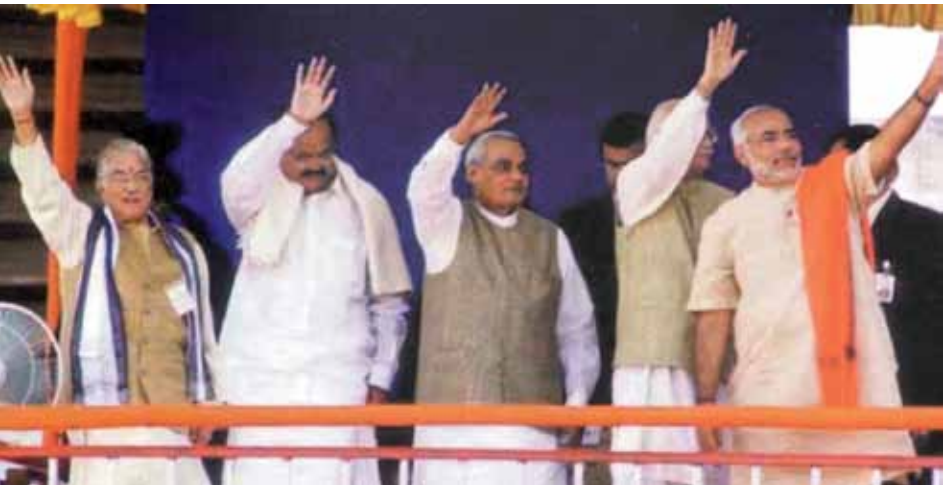

को नए सिरे से परिभाषित किया। वो अनेक दलों को साथ लाए और NDA को विकास, देश की प्रगति और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधि बनाया।

पीएम पद पर रहते हुए उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब हमेशा बेहतरीन तरीके से दिया। वो ज्यादातर समय विपक्षी दल में रहे, लेकिन नीतियों का विरोध तर्कों और शब्दों से किया। एक समय उन्हें कांग्रेस ने गद्दार तक कह दिया था, उसके बाद भी उन्होंने कभी असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया।

उन में सत्ता की लालसा नहीं थी। 1996 में उन्होंने जोड़-तोड़ की राजनीति ना चुनकर, इस्तीफा देने का रास्ता चुन लिया। राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण 1999 में उन्हें सिर्फ एक वोट के अंतर के कारण पद से इस्तीफा देना पड़ा। कई लोगों ने उनसे इस तरह की अनैतिक राजनीति को चुनौती देने के लिए कहा, लेकिन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी शुचिता की राजनीति पर चले। अगले चुनाव में उन्होंने मजबूत जनादेश के साथ वापसी की।

संविधान के मूल्य संरक्षण में भी, उनके जैसा कोई नहीं था। डॉ. श्यामा प्रसाद के निधन का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। वो आपातकाल के खिलाफ लड़ाई का भी बड़ा चेहरा बने। इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनाव से पहले उन्होंने 'जनसंघ' का जनता पार्टी में विलय करने पर भी सहमति जता दी। मैं जानता हूं कि ये निर्णय सहज नहीं रहा होगा, लेकिन वाजपेयी जी के लिए हर राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता की तरह दल से बड़ा देश था, संगठन से बड़ा, संविधान था।

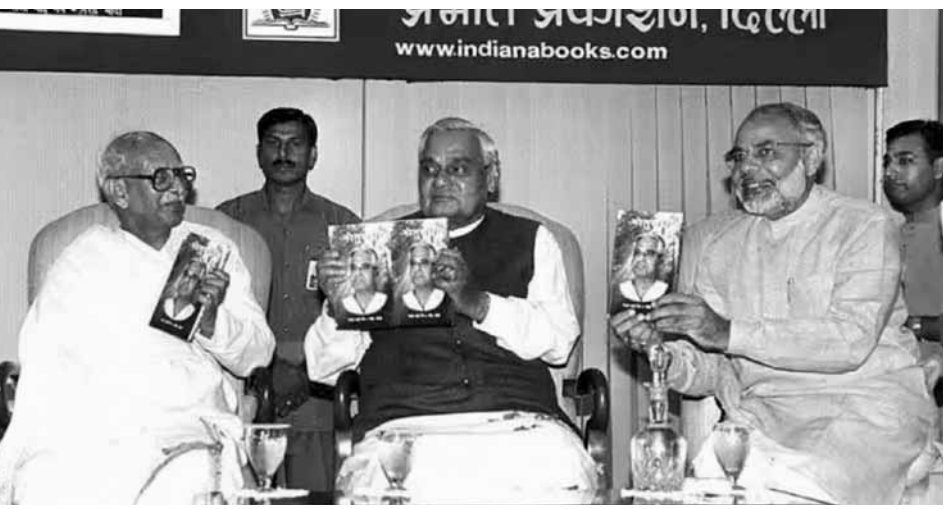

हम सब जानते हैं, अटल जी को भारतीय संस्कृति से भी बहुत लगाव था। भारत के विदेश मंत्री बनने के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने का अवसर आया, तो उन्होंने अपनी हिंदी से पूरे देश को खुद से जोड़ा। पहली बार किसी ने हिंदी में संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात कही। उन्होंने भारत की विरासत को विश्व पटल पर रखा। उन्होंने सामान्य भारतीय की भाषा को संयुक्त राष्ट्र के मंच तक पहुंचाया।

राजनीतिक जीवन में होने के बाद भी, वो साहित्य और अभिव्यक्ति से जुड़े रहे। वो एक ऐसे कवि और लेखक थे, जिनके शब्द हर विपरीत स्थिति में व्यक्ति को आशा और नव सृजन की प्रेरणा देते थे। वो हर उम्र के भारतीय के प्रिय थे। हर वर्ग के अपने थे।

मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को उनसे सीखने का, उनके साथ काम करने का, उनसे संवाद करने का अवसर मिला। अगर आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो इसका श्रेय उस अटल आधार को है, जिस पर ये दृढ़ संगठन खड़ा है।

उन्होंने बीजेपी की नींव तब रखी, जब कांग्रेस जैसी पार्टी का विकल्प बनना आसान नहीं था। उनका नेतृत्व, उनकी राजनीतिक दक्षता, साहस और लोकतंत्र के प्रति उनके अगाध समर्पण ने बीजेपी को भारत की लोकप्रिय पार्टी के रूप में प्रशस्त किया। श्री लालकृष्ण आडवाणी और डॉ. मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों के साथ, उन्होंने पार्टी को अनेक चुनौतियों से निकालकर सफलता के सोपान तक पहुंचाया।

जब भी सत्ता और विचारधारा के बीच एक को चुनने की स्थितियां आईं, उन्होंने इस चुनाव में विचारधारा को खुले मन से चुन लिया। वो देश को ये समझाने में सफल हुए कि कांग्रेस के दृष्टिकोण से अलग एक वैकल्पिक वैश्विक दृष्टिकोण संभव है। ऐसा दृष्टिकोण वास्तव में परिणाम दे सकता है।

आज उनका रोपित बीज, एक वटवृक्ष बनकर राष्ट्र सेवा की नव पीढ़ी को रच रहा है। अटल जी की 100वीं जयंती, भारत में सुशासन के एक राष्ट्र पुरुष की जयंती है। आइए हम सब इस अवसर पर, उनके सपनों को साकार करने के लिए मिलकर काम करें। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें, जो सुशासन, एकता और गति के अटल सिद्धांतों का प्रतीक हो।

मुझे विश्वास है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिखाए सिद्धांत ऐसे ही, हमें भारत को नव प्रगति और समृद्धि के पथ पर प्रशस्त करनें की प्रेरणा देते रहेंगे। ▪

(श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती "सुशासन दिवस" पर विशेष)

लोक कल्याण के लिए किया जाने वाला शासन है सुशासन

हितानंद शर्मा

शासन में 'सुशासन' का भाव भारत की संस्कृति की विशिष्टता है। सुशासन, अर्थात लोक मंगल की कामना से किया जाने वाला शासन। भगवान श्रीराम के रामराज्य के आदर्श शासन से प्रेरणा लेकर हर युग में सुशासन के अनेक उदाहरण रहे हैं, जिनमें शासक लोक कल्याण के लिए कार्य करते रहे। यह भारतीय संस्कृति का सौंदर्य ही है कि शासन में 'सुशासन' सदैव प्राथमिकता में रहा। विदेशी शासकों के आ जाने से कालांतर में विस्मृत हुए इस भाव को पुनः जागृति एवं ऊर्जा तब मिली जब पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार ने लोक कल्याण के लिए सुशासन की दिशा में सतत् कार्य किए। इसीलिए अटलजी के सम्मान में 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाने की घोषणा की गई।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दूरदर्शी नेता, कवि, संपादक, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। भारत माता के महान सपूत और राजनीति के अजातशत्रु अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को शिक्षक पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता कृष्णा देवी के घर ग्वालियर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर और मुरैना में हुई। ग्वालियर से स्नातक और कानपुर से राजनीति विज्ञान से स्नातकोत्तर करने के बाद अटलजी ने स्वयं को राष्ट्रसेवा में समर्पित कर दिया। इस जन्म शताब्दी वर्ष में देश उनके सुशासन और ऐतिहासिक योगदान के लिए अटलजी को विशेष रूप से स्मरण कर रहा है।

चार दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहते हुए अटलजी नौ बार लोकसभा और दो बार राज्यसभा के सदस्य रहे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष रहने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य एवं बाद में अध्यक्ष रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, विपक्ष के नेता और संसद की स्थायी समितियों के अध्यक्ष के रूप में देश की नीतियों को आकार दिया।

चार दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहते हुए अटलजी नौ बार लोकसभा और दो बार राज्यसभा के सदस्य रहे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष रहने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य एवं बाद में अध्यक्ष रहे।

उन्होंने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, विपक्ष के नेता और संसद की स्थायी समितियों के अध्यक्ष के रूप में देश की नीतियों को आकार दिया।

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। जमीन से गहरा जुड़ाव होने से वे आमजन की समस्याओं को भी उतनी ही संवेदनशीलता से समझते थे। इसे उनके एक कार्य से सहजता से समझा जा सकता है। वे उस समय के प्रधानमंत्री थे जब पक्के रास्ते न होने से गांवों में पहुंचना कठिन होता था। बारिश के दिनों में तो कई गावों के रास्ते बंद हो जाते थे। अटलजी ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' प्रारंभ की और पूरे देश के गावों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया। इससे गांवों में आना-जाना सुलभ हुआ तो वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी उनका यह कदम अत्यंत कारगर सिद्ध हुआ।

केवल ग्राम सड़क योजना ही नहीं उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन कर आधुनिक ढंग से निर्माण पर बल दिया। 'स्वर्णिम चतुर्भुज' परियोजना भारत के चार प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला राजमार्ग नेटवर्क तैयार करने की ऐसी ही परियोजना है। अटलजी ने सामाजिक समरसता

के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। समाज के हर वर्ग का ध्यान रखते हुए अपनी नीतियों का निर्धारण किया। देश के जनजाति समाज के कल्याण के लिए उन्होंने अलग से जनजाति कार्य मंत्रालय बनाया। पेयजल एवं सिंचाई के लिए उन्होंने नदियों को जोड़ने की परियोजना का भी प्रस्ताव रखा। अटलजी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस परियोजना में मध्यप्रदेश की केन-बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी।

अटल जी ने देश की प्रगति के लिए कार्य करते हुए हर दिशा में राष्ट्र को सबल बनाने का संकल्प लिया था। यही कारण है कि किसानों को सेठ-साहूकारों के कर्जों से बचाने के लिए उन्होंने 'किसान क्रेडिट कार्ड' जैसी लाभदायक योजना प्रारंभ की तो वहीं दूरसंचार के क्षेत्र में नई नीतियों को अपनाया जिसका सुफल आज संचार क्रांति के रूप में दिखाई देता है। राष्ट्र रक्षा का कार्य सदैव उनकी प्राथमिकता में रहा। इसीलिए विपरीत वैश्विक परिस्थितियों में भी पूरे साहस के साथ पोखरण में 11 मई 1998 को पांच परमाणु परीक्षणों से उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल कराया। इस अवसर पर उन्होंने 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान' का नारा दिया। भारत की सामरिक शक्ति मजबूत करने के लिए उन्होंने विशेष निर्णय लिए। वहीं धोखे से कारगिल में घुस आई पाकिस्तानी सेना को खदेड़ देने के लिए सेना का मनोबल बढ़ाते हुए सैन्य एवं कूटनीतिक मोर्चे पर दृढ़ता से कार्य किया और भारत के हाथों परास्त होकर पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी।

राष्ट्र, धर्म और संस्कृति से वे गहनता से जुड़े रहे। विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में दिया गया उनका भाषण ऐतिहासिक रहा। 1996 में पहली बार 13 दिनों के लिए भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। पीएम के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल 1998 से 1999 तक 13 महीने का था। उन्होंने तीसरी बार 1999 से 2004 तक पीएम के रूप में पूर्ण कार्यकाल के लिए पदभार संभाला। 2018 में 93 वर्ष की आयु तक वे समाज के मार्गदर्शक की भूमिका में रहे। अटलजी भारतीय राजनीति में आदर्श, शिष्टता और नैतिकता का प्रतीक बने। उनके विचार प्रगतिशील, लोकतांत्रिक और समावेशी थे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता और विज्ञान-प्रौद्योगिकी के विकास को देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माना। वे लोकमंगल का भाव लिए सुशासन करने के लिए सदैव याद किए जाएंगे। ▪

(लेखक भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश के प्रदेश संगठन महामंत्री है)

बूथ समितियों का गठन और बूथों का डिजिटलाइजेशन पूर्ण-विष्णुदत्त शर्मा

देश में 2 सितम्बर और मध्यप्रदेश में 3 सितम्बर से पार्टी के संगठन पर्व की शुरुआत हुई थी। शुरुआत से ही प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने संगठन पर्व के प्रति अभूतपूर्व उत्साह दिखाया।

- **संगठन पर्व में इतिहास रचेंगे पार्टी कार्यकर्ता।**
- **भाजपा अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने कार्यकर्ताओं की सराहना की।**

देश में 2 सितम्बर और मध्यप्रदेश में 3 सितम्बर से पार्टी के संगठन पर्व की शुरुआत हुई थी। शुरुआत से ही प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने संगठन पर्व के प्रति अभूतपूर्व उत्साह दिखाया। चाहे प्राथमिक सदस्यता की बात हो या सक्रिय सदस्यता की, पार्टी कार्यकर्ताओं ने हर बार लक्ष्य से अधिक काम किया है। प्रदेश के कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों ने पूरी गुणवत्ता और संपूर्णता के साथ समय सीमा में 100 प्रतिशत बूथ समितियों के गठन को संभव कर दिखाया। ये समितियां सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी हैं। इनमें सभी जाति, वर्ग और आयु समूह के लोगों को शामिल किया गया है। सबसे प्रमुख बात यह है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प की पूर्ति में योगदान देते हुए बूथ समितियों में भी 33 प्रतिशत महिला कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है।

बूथ समितियों के गठन के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने तमाम परेशानियों के बावजूद 100 प्रतिशत बूथ समितियों के डिजिटलाइजेशन को भी पूरा कर दिखाया, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पार्टी कार्यकर्ताओं के इन प्रयासों और परिश्रम की भाजपा अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी सराहना की है। संगठन पर्व के दौरान विभिन्न नवाचारों के जरिए संगठन के रचनात्मक कार्यों को धरातल पर उतारकर संगठन ने आदर्श स्थापित किए हैं। विभिन्न जिम्मेदारियों को संभाल रहे पार्टी कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों के उत्साह से यह स्पष्ट हो चुका है कि इस बार मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी हर मापदंड पर शानदार प्रदर्शन करते हुए नया इतिहास रचने जा रही है। ▪

गीता जयंती: सद्कर्म, स्व-धर्म और सच्चे कर्तव्य पथ की प्रेरणा

डॉ. मोहन यादव

भगवान श्रीकृष्ण द्वारा जो बातें कही गईं वह आज भी सम-सामयिक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जिस गीता भाष्य की रचना की थी उसे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, राजगुरु आदि क्रांतिवीर अपने पास रखते थे।

गीता भाष्य से प्रेरणा लेकर क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिये संघर्ष किया। गीता हमारे लिये न केवल पवित्र ग्रंथ है बल्कि जीवन की सार्थकता सिद्ध करने का मार्ग भी है।

गीता जयंती का अवसर अद्भुत और अलौकिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। मध्यप्रदेश नें पहली बार ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया।

यह हमारा सौभाग्य है कि इस महोत्सव में हमें गीता के ज्ञान और इसके महत्व को जानने तथा व्यवहार में आत्मसात करने का अवसर मिला है। विरासत से विकास की संकल्पना के मूल विचार में सनातन परम्पराएं, मान्यताएं और उसके कल्याणकारी सामाजिक परिणाम रहे हैं। इसी क्रम में गीता जयंती के अवसर पर मध्यप्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया। इसका उद्देश्य भगवान श्रीकृष्ण के जीवन के विविध पक्षों और श्रीमद्भगवद गीता के सार्थक संदेशों से नागरिकों को अवगत करवाना है। सौभाग्य की बात है कि मध्यप्रदेश गीता के सस्वर पाठ का विश्व रिकार्ड स्थापित कर रहा है। इसी श्रृंखला में विद्यालयों में गीता पर केन्द्रित क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लाखों विद्यार्थियों ने सहभागिता की। भगवान श्रीकृष्ण ने जीवन के रहस्य की जो बात श्रीमद्भगवद गीता में समझाई है वह हम सभी के लिये पाथेय के रूप में है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र निर्माण के लिये प्रासंगिक है।

भगवान श्रीकृष्ण ने पांच हजार साल पहले महाभारत की युद्ध भूमि कुरूक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा दी जिससे पवित्र गीता का अवतरण हुआ। भगवान श्रीकृष्ण द्वारा जो बातें कही गईं वह आज भी सम-सामयिक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जिस गीता भाष्य की रचना की थी उसे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, राजगुरु आदि क्रांतिवीर अपने पास रखते थे। गीता भाष्य से प्रेरणा लेकर क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिये संघर्ष किया। गीता हमारे लिये न केवल पवित्र ग्रंथ है बल्कि जीवन की सार्थकता सिद्ध करने का मार्ग भी है।

गीता का मध्यप्रदेश से गहरा संबंध है। भगवान श्रीकृष्ण विद्याध्ययन के लिये मध्यप्रदेश की उज्जैन नगरी आये थे। यहां महर्षि सांदीपनि आश्रम में उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई थी, इसी धरती पर उन्हें सुदर्शन मिला। श्रीमद्भगवद गीता आज भी पूरे संसार के लिये एक अद्भुत ग्रंथ है। संसार के लगभग प्रत्येक देश ने अपनी स्वभाषा में गीता का अनुवाद किया और विश्वविद्यालयों ने शोध किया। व्यक्तित्व विकास की आधुनिक पुस्तकों में ऐसा कोई सूत्र नहीं जिसका वर्णन श्रीमद्भगवद गीता में न हो। श्रीमद्भगवद गीता भारतीय दर्शन और चिंतन का मूल आधार है, जो सत्कर्म के माध्यम से मनुष्य को अपने में ही दिव्यता का अनुभव करा देती है। यह समस्त मानव समाज को स्व-धर्म का आत्मबोध देती है और सच्चे कर्तव्य पथ की ओर प्रशस्त करती है।

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। यह भवन गीता के ज्ञान को साझा करने का महत्वपूर्ण

स्थान होगा। यहां होने वाले विचार-विमर्श से लोगों के जीवन और व्यवहार में बदलाव आयेगा। हमने प्रदेश के सभी विकासखण्डों में एक गांव को चयनित कर वृंदावन गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इन गांवों के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों और सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाया जायेगा। वृंदावन गांव में जहां एक ओर प्राचीन संस्कृति को पुष्पित और पल्लवित किया जायेगा, वहीं दूसरी ओर जैविक खेती और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जायेगा।

रामायण और श्रीमद्भागवत गीता हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं। हमारी युवा पीढ़ी को इन धर्म ग्रंथों के बारे में जानना आवश्यक है। इनके ज्ञान से अपने व्यक्तित्व और भविष्य को परिष्कृत किया जा सकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश करते हुए पाठ्यक्रमों में रामायण और गीता वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल की गई हैं। आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों को गीता का ज्ञान भी दिया जा रहा है, जो धरातल पर भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के एक हाथ में श्रीमद् भागवत गीता है तो दूसरे हाथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की पुस्तकें। यह बदलाव बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण से लेकर भविष्य निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी है।

श्रीमद्भागवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। इनमें 574 श्रीकृष्ण उवाच अर्थात् भगवान श्रीकृष्ण ने कुल 574 श्लोकों में जीवन का संदेश दिया है। व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के साथ संपूर्ण प्रकृति और सृष्टि के जीवन के सभी विषय, हर समस्या का समाधान इन श्लोकों के सूत्रों में है। भगवान श्रीकृष्ण ने जीवन की सफलता के लिये अपने धर्म के पालन और एकाग्रता के साथ कर्मशीलता पर ही बल दिया है।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥
(2/ 47)

अर्थात् तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, कर्म के फल पर नहीं... इसलिए फल की चिंता किये बिना कर्म को ही कर्तव्य मानकर कार्य करो, उसी पर तुम्हारा अधिकार है।

गीता के अध्याय दो के इस श्लोक में किसी व्यक्ति के जीवन की सफलता का ही नहीं, समाज और राष्ट्र के विकास का भी यही सूत्र है। मनुष्य को अपना पूरा ध्यान अपने कर्म और कर्तव्य पर ही लगाना चाहिए। यदि व्यक्ति का समर्पण कर्तव्य के प्रति है तो उससे कोई अनुचित कार्य नहीं होगा और यदि पूरी आयोजना के साथ कर्म आरंभ किया है तो उसकी शत-प्रतिशत सफलता निश्चित है तब क्यों परिणाम के प्रति

रामायण और श्रीमद्भागवत गीता हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं। हमारी युवा पीढ़ी को इन धर्म ग्रंथों के बारे में जानना आवश्यक है। इनके ज्ञान से अपने व्यक्तित्व और भविष्य को परिष्कृत किया जा सकता है।

चिंतित होना चाहिए। श्रीमद्भगवदगीता की प्रेरणा से मध्यप्रदेश ने अपनी विकास यात्रा आरंभ की है। मध्यप्रदेश सरकार का संकल्प है ''विकास के साथ विरासत''। इसीलिए एक ओर जहां विकास के लिये बहुआयामी योजनाओं पर काम हो रहा है वहीं भावी पीढ़ी के निर्माण और उन्हें अपने कर्म-कर्तव्य की प्रेरणा देने के लिये विरासत को भी संजोया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों में योगेश्वर और कर्मेश्वर भगवान श्रीकृष्ण की स्मृतियां बिखरी हुई हैं। उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण, महू के पास जानापाव में भगवान परशुराम से भेंट, धार जिले के अमझेरा में रुक्मणी वरण और शौर्य का प्रदर्शन आदि स्थानों में उनके स्मृति चिन्ह हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने श्रीकृष्ण पाथेय निर्माण करने का संकल्प लिया है।

इस पाथेय में उन सभी स्थानों को जोड़ा जा रहा है जहां भगवान श्रीकृष्ण का आगमन हुआ। यह सब एक तीर्थ के रूप में विकसित होंगे और इन स्थानों पर भगवान श्रीकृष्ण की लीला, शिक्षा एवं श्रीमद्भगवद गीता के संदेश उकेरे जायेंगे ताकि वर्तमान पीढ़ी उनके संदेशों को समझकर अपना जीवन सार्थक कर सके।

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का उत्सव है। सभी नागरिकों से आग्रह है कि वे गीता की अमूल्य शिक्षा तथा मूल्यों से प्रेरणा लें, अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने विकास के साथ विकसित मध्यप्रदेश निर्माण की संकल्पना को आधार प्रदान करें। ▪

(लेखक, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)

सनातन संस्कृति की ध्वजा विश्व में फहरा रही गीता प्रेस

विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशन गीता प्रेस

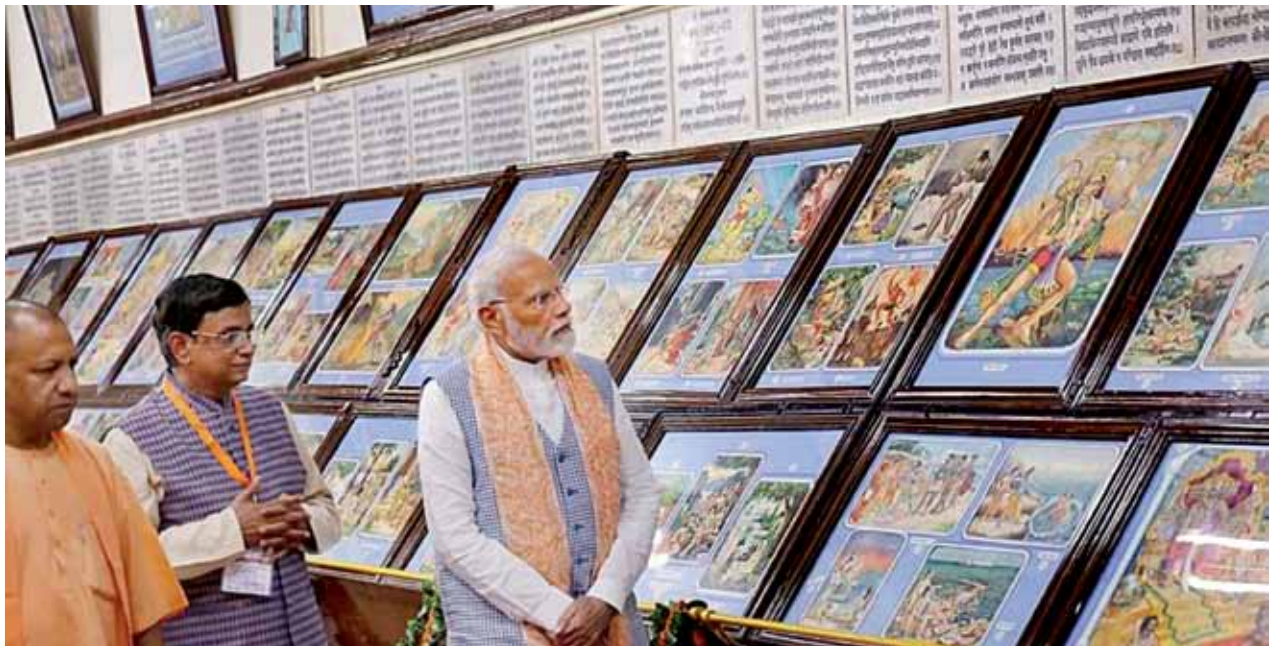

हितानंद शर्मा

गीता के ईश्वरीय संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य "गीता प्रेस गोरखपुर" द्वारा पिछले 102 वर्षों से बिना रुके पूरे श्रद्धाभाव से किया जा रहा है।

भारत के घर-घर में श्रीमद्भागवत गीता और रामायण की प्रति पहुंचाने का श्रेय गीता प्रेस को ही जाता है। गीता प्रेस अब तक श्रीमद्भागवत गीता की 16 करोड़ 21 लाख प्रतियां प्रकाशित कर श्रद्धालु पाठकों तक पहुंचा चुका है।

धर्म स्थापना के लिए मानव इतिहास में हुए सबसे भीषण महायुद्ध के बीच भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया गीता का ज्ञान आज भी अमृत रूप में प्रवाहित हो रहा है। श्रीमद्भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं, सनातन समाज के लिए नहीं, बल्कि विश्व मानवता के शुभ के लिए ईश्वरीय संदेश है। गीता के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को जान सकता है और ईश्वरीय सत्ता का अनुभव भी कर सकता है। गीता जयंती मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह वही दिन है जब श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था।

गीता के ईश्वरीय संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य 'गीता प्रेस गोरखपुर' द्वारा पिछले 102 वर्षों से बिना रुके पूरे श्रद्धाभाव से किया जा रहा है। भारत के घर-घर में श्रीमद् भागवत गीता और रामायण की प्रति पहुंचाने का श्रेय गीता प्रेस को ही जाता है। गीता प्रेस अब तक श्रीमद्भागवत गीता की 16 करोड़ 21 लाख प्रतियां प्रकाशित कर श्रद्धालु पाठकों तक पहुंचा चुका है।

अब तक 41 करोड़ 71 लाख पुस्तकें छापकर विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशन संस्थान होने के बाद भी आश्चर्य की बात यह है कि गीता प्रेस न तो किसी से चंदा लेता है और न ही अपने प्रकाशनों में विज्ञापन ही स्वीकार करता है। जब वर्ष 2021 में गीता प्रेस को उसके उल्लेखनीय कार्यों के लिए भारत सरकार का गरिमामय 'महात्मा गांधी शांति पुरस्कार' प्रदान किया गया तो संस्थान ने पुरस्कार को पूरे सम्मान के साथ ग्रहण किया, पर इसके साथ प्रदान की जाने वाली एक करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि

सरकार को वापस लौटा दी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इस संस्थान के दर्शन के लिए आए थे। लागत मूल्य से 50 से लेकर 90 प्रतिशत तक कम कीमत पर बहुमूल्य पुस्तकें पाठकों तक पहुंचाने वाला गीता प्रेस वास्तव में सामाजिक-धार्मिक जागरण का एक आंदोलन ही है।

भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण की पावन धरा उत्तरप्रदेश का प्रवास तो पूर्व में भी होता ही रहा है किन्तु इसी वर्ष संयोग से संगठन के कार्य से मुझे गोरक्ष प्रांत यानी गोरखपुर सहित आसपास के क्षेत्रों का प्रभार सौंपा गया। ऐसे में गोरखपुर में गोरक्ष पीठ सहित एक महत्वतपूर्ण तीर्थ गीता प्रेस के दर्शन का सौभाग्य भी मिला। प्रकाशन का केंद्रीय कार्यालय गोरखपुर में ही है। हिन्दू धर्म, अध्यात्म, दर्शन सहित मानव कल्याण के अनेक विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित कर चुका गीता प्रेस आधुनिक समय का तीर्थ ही है। राजा भागीरथ के महान तप से पुण्य प्रवाहिनी मां गंगा का धरती पर अवतरण संभव हो सका था। इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को धरती पर लाने का प्रण पूर्ण किया था। इसी प्रकार गीता प्रेस के संस्थापक, ब्रह्मलीन श्री जयदयालजी गोयंदका के ऐसे ही महान तप का सुफल यह प्रकाशन है। वैसे तप तुलना का विषय नहीं है किन्तु धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, भक्ति एवं मानवता के उद्धार के लिए गोयंदका जी द्वारा स्थापित गीता प्रेस आज भी पुण्य प्रवाहमयी ज्ञान सरिता है।

गीता प्रेस के आदि संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार 'भाईजी' के उल्लेख के बिना गीता प्रेस की चर्चा पूर्ण नहीं होगी। भाईजी वीर सावरकर के निकट के क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अपने मौसेरे भाई जयदयालजी के अगाध गीता प्रेम एवं ज्ञान को देखते हुए भाईजी ने श्रीमद्भागवत गीता को लागत मूल्य से भी कम में जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

इस संकल्प की पूर्ति के लिए अपने एक प्रकाशन की आवश्यकता थी जो गोरखपुर में प्रारंभ हुआ। प्रचार-प्रसार से दूर एक अकिंचन सेवक और निष्काम कर्मयोगी की तरह भाईजी ने सनातन संस्कृति की मान्यताओं को घर-घर तक पहुँचाने में जो अतुलनीय योगदान दिया है, इतिहास में इसका उदाहरण मिलना कठिन है।

गीता प्रेस का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म के सिद्धांतों को गीता, रामायण, उपनिषद, पुराणों, प्रख्यात संतों के प्रवचन एवं चरित्र-निर्माण की अन्य पुस्तकें -पत्रिकाएं प्रकाशित कर इन्हें लागत मूल्य से भी कम कीमत में समाज में पहुंचाना है। गीता प्रेस मानव जीवन के उत्थायन और सभी की भलाई के लिए प्रयासरत है। इसका उद्देश्य शांति, आनंद और मानव जाति

गीता प्रेस के मासिक पत्रिका ग्रंथ "कल्याण" के नए संस्करण के साथ 3000 से अधिक ऑनलाइन संग्रह उपलब्ध हैं।

4 मई 1923 को गीता प्रेस की स्थापना की गई थी तब पुस्तकें छापने का काम बोस्टन कंपनी की प्रिंटिंग प्रेस से शुरू किया गया था।

के अंतिम उत्थान के लिए गीता में प्रतिपादित जीवन जीने की कला को बढ़ावा देना है।

संस्थान का संचालन कोलकाता के गोविंद भवन द्वारा किया जाता है। इसका प्रबंधन एक गवर्निंग काउंसिल (ट्रस्ट बोर्ड) करती है। गीता प्रेस में दिन की शुरुआत सुबह की प्रार्थना से होती है। एक व्यक्ति दिन भर घूम-घूम कर प्रत्येक कार्यकर्ता को कई बार भगवान का नाम स्मरण कराता है। गीता प्रेस के अभिलेखागार में श्रीमद् भागवत गीता की 100 से अधिक व्याख्याओं सहित 3,500 से अधिक पांडुलिपियां रखी हैं।

गीता प्रेस के मासिक पत्रिका ग्रंथ 'कल्याण' के नए संस्करण के साथ 3000 से अधिक ऑनलाइन संग्रह उपलब्ध हैं। 4 मई 1923 को गीता प्रेस की स्थापना की गई थी तब पुस्तकें छापने का काम बोस्टन कंपनी की प्रिंटिंग प्रेस से शुरू किया गया था। पैरों से चलाई जाने वाली यह मशीन 500 रुपए में अमेरिका से मंगवाई गई थी। अब संस्थान आधुनिक संसाधनों का सदुपयोग करता है इसीलिए मैनुअल और मशीन दोनों माध्यमो से प्रकाशन का काम होता है। गीता प्रेस इन अर्थों में भी विश्व का अनूठा प्रकाशन है क्योंकि यह अपनी पुस्तकों में मात्रात्मक, व्याकरणिक, शाब्दिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि बताने वाले को पुरस्कृत करता है हालाँकि पुस्तकों में ऐसी त्रुटियां मिलती नहीं हैं।

बीते वर्षों में मीडिया में इस प्रकार के समाचार आए थे कि गीता प्रेस आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बंद होने की कगार पर है किन्तु संस्थान के भ्रमण में यह भी जानने मिला कि स्थिति ऐसी नहीं है। समाज के सहयोग से गीता प्रेस 300 करोड़ रुपए वार्षिक टर्न ओवर वाला समृद्ध संस्थान है और प्रति वर्ष 17 भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है। संस्थान ने अपनी पुस्तकें इंटरनेट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध कराई हैं जहां से कोई भी इन्हें डाउनलोड कर सकता है और यह पूरी तरह निःशुल्क है।

संस्थान का कार्यालय भी दर्शनीय है। इसके भव्य प्रवेश द्वार के स्तंभ एलोरा के प्राचीन गुफा-मंदिर के स्तंभों की शैली में निर्मित हैं। वहीं अर्जुन के रथ के सारथी बन श्रीकृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं। प्रवेश द्वार का शिखर दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर के शिखर का स्मरण कराता है। इस प्रवेश द्वार का उद्घाटन 29 अप्रैल, 1955 को प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने किया था। संस्थान के परिसर में लीला चित्र मंदिर (आर्ट गैलरी) में 684 सुंदर चित्रों में भगवान राम और भगवान कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित किया गया है।

ये अलग-अलग समय के महान कलाकारों की कृतियां हैं। इनके अलावा अन्य पेंटिंग भी प्रदर्शित हैं। श्री कृष्ण लीला को दर्शाने वाली पुरानी मेवाड़ी शैली की 92 पेंटिंग दर्शनीय है। दीवारों पर संगमरमर के ब्लॉकों पर पूरी गीता उकेरी गई है, साथ ही लगभग 700 दोहे और संतों के छंद भी हैं।

गीता प्रेस आधुनिक समय में हिन्दू धर्म, संस्कृति की पताका पूरे विश्व में फहरा रही है। जब भी बात हिन्दू धर्म के महान ग्रंथों की होती है तो सहज ही गीता प्रेस का नाम ध्यान में आ जाता है। आज की घोर व्यावसायिकता के युग में गीता प्रेस लोक कल्याण की भावना से प्रामाणिक पुस्तकें समाज को उपलब्ध करा रहा है। गीता प्रेस की यह पुण्य सलिला निरंतर प्रवाहमान रहने वाली है। ▪

(लेखक भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं)

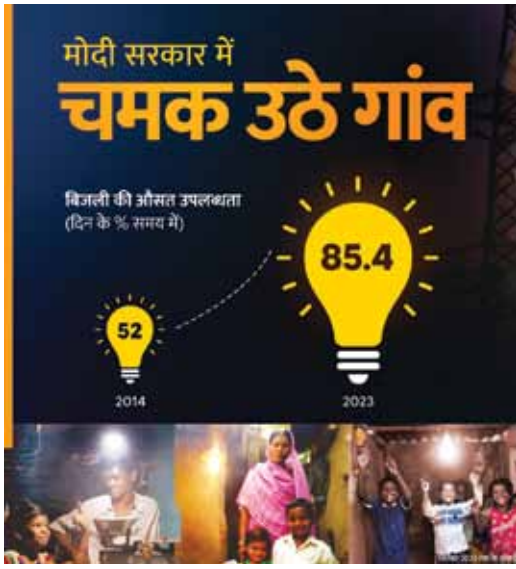

महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश

2025 में 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए guiding light है, हमारा मार्गदर्शक है। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। इस साल 26 नवंबर को संविधान दिवस से एक साल तक चलने वाली कई activities शुरू हुई हैं। देश के नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए constitution.com नाम से एक खास website भी बनाई गई है। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना video upload कर सकते हैं। अलग-अलग भाषाओं में संविधान पढ़ सकते हैं, संविधान के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। 'मन की बात' के श्रोताओं से, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से, कॉलेज में जाने वाले युवाओं से, आग्रह है, इस website पर जरूर जाकर देखें, इसका हिस्सा बनें।

13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियाँ चल रही हैं।

महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है। कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परम्पराएँ, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। जब हम कुंभ में शामिल हों, तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आयें। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूँगा...

महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश।
महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश।
और अगर दूसरे तरीके से कहना है
तो मैं कहूँगा...
गंगा की अविरल धारा,
न बँटे समाज हमारा।।
गंगा की अविरल धारा,
न बँटे समाज हमारा।।

इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु digital महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। Digital Navigation की मदद से आपको अलग-अलग घाट, मंदिर, साधुओं के अखाड़ों तक पहुँचने का रास्ता मिलेगा। यही navigation system आपको parking तक पहुँचने में भी मदद करेगा। पहली बार कुंभ आयोजन में AI chatbot का प्रयोग होगा।AI chatbot के माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस chatbot से कोई भी text type करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकता है। पूरा मेला क्षेत्र को AI-Powered cameras से cover किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को digital lost & found center की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाईल पर government-approved tour packages, ठहरने की जगह और homestay के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। महाकुंभ में जाएँ तो इन सुविधाओं का लाभ उठाएँ और हाँ एकता का महाकुंभ के साथ अपनी selfie जरूर upload करिएगा।

'मन की बात' यानि MKB में अब बात KTB की, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनमें से, बहुत से लोगों को KTB के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन जरा बच्चों से पूछिए KTB उनके बीच

कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परम्पराएँ, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है।

कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है।

बहुत ही superhit है। KTB यानि कृष, तृष और बाल्टीबॉय। आपको शायद पता होगा बच्चों की पसंदीदा animation series और उसका नाम है KTB – भारत हैं हम और अब इसका दूसरा season भी आ गया है। ये तीन animation character हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन नायक-नायिकाओं के बारे में बताते हैं जिनकी ज्यादा चर्चा नहीं होती। हाल ही में इसका season-2 बड़े ही खास अंदाज में Iinternational Film Festival of India, Goa में launch हुआ। सबसे शानदार बात ये है कि ये series न सिर्फ भारत की कई भाषाओं में बल्कि विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित होती है। इसे दूरदर्शन के साथ-साथ अन्य OTT platform पर भी देखा जा सकता है।

हमारी animation फिल्मों की, regular फिल्मों की, टीवी serials की, popularity दिखाती है कि भारत की creative Industry में कितनी क्षमता है। यह Industry न सिर्फ देश की प्रगति में बड़ा योगदान दे रही है, बल्कि, हमारी economy को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। हमारी Film & Entertainment Industry बहुत विशाल है। देश की कितनी ही भाषाओं में फिल्में बनती हैं, creative content बनता है। film और entertainment Industry को इसलिए भी बधाई देता हूँ, क्योंकि उसने 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के भाव को सशक्त किया है।

वर्ष 2024 में हम फिल्म जगत की कई महान हस्तियों की 100वीं जयंती मना रहे हैं। इन विभूतियों ने भारतीय सिनेमा को विश्व-स्तर पर पहचान दिलाई। राज कपूर जी ने फिल्मों के माध्यम से दुनिया को भारत की soft power से परिचित कराया। रफी साहब की आवाज में वो जादू था जो हर दिल को छू लेता था। उनकी आवाज अदभुत थी। भक्ति गीत हों या romantic songs, दर्द भरे गाने हों, हर emotion को उन्होंने अपनी आवाज से जीवंत कर दिया। एक कलाकार के रूप में उनकी महानता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी युवा-पीढ़ी उनके गानों को उतनी ही शिद्दत से सुनती है - यही तो है timeless art की पहचान। अक्किनेनी नागेश्वर राव गारू ने तेलुगु सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनकी फिल्मों ने भारतीय परंपराओं और मूल्यों को बखूबी प्रस्तुत किया। तपन सिन्हा जी की फिल्मों ने समाज को एक नई दृष्टि दी। उनकी फिल्मों में सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय एकता का संदेश रहता था। हमारी पूरी film Industry के लिए इन हस्तियों का जीवन प्रेरणा जैसा है।

भारत की creative talent को दुनिया के सामने रखने का एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। अगले साल हमारे देश में पहली बार World Audio Visual Entertainment Summit यानि WAVES summit का आयोजन होने वाला है। आप सभी ने दावोस के बारे में सुना होगा जहां दुनिया के अर्थजगत के महारथी जुटते हैं। उसी तरह WAVES summit में दुनिया-भर के media और entertainment Industry के दिग्गज, creative world के लोग भारत आएंगे। यह summit भारत को global content creation का hub बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस summit की तैयारी में हमारे देश के young creators भी पूरे जोश से जुड़ रहे हैं। जब हम 5 trillion dollar economy की ओर बढ़ रहे हैं, तब हमारी creator economy एक नई energy ला रही है। मैं भारत की पूरी entertainment और creative Industry से आग्रह करूंगा - चाहे आप young creator हों या established artist, Bollywood से जुड़े हों, या regional cinema से, TV Industry के professional हों, या animation के expert, gaming से जुड़े हों या entertainment technology के Innovator, आप सभी WAVES summit का हिस्सा बनें।

भारतीय संस्कृति का प्रकाश कैसे दुनिया के कोने-कोने में फैल रहा है। मैं आपको तीन महाद्वीपों से ऐसे प्रयासों के बारे में बताऊंगा, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत के वैश्विक विस्तार की गवाह है। ये सभी एक दूसरे से मीलों दूर हैं। लेकिन भारत को जानने और हमारी संस्कृति से सीखने की उनकी ललक एक जैसी है।

Paintings का संसार जितना रंगों से भरा होता है, उतना ही खूबसूरत होता है। जो लोग टीवी के माध्यम से 'मन की बात' से जुड़े हैं, वे अभी कुछ paintings टीवी पर देख भी सकते हैं। इन paintings में हमारे देवी-देवता, नृत्य की कलाएं और महान विभूतियों को देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनमें आपको भारत में पाए जाने वाले जीव-जंतुओं से लेकर और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इनमें ताजमहल की एक शानदार painting भी शामिल है, जिसे 13 साल की एक बच्ची ने बनाया है। आपको ये जानकार हैरानी होगी इस दिव्यांग बच्ची ने अपने मुहँ से इस painting को तैयार किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन painting को बनाने वाले भारत के नहीं, बल्कि Egypt के students हैं, वहाँ के विद्यार्थी हैं। कुछ ही हफ्ते पहले Egypt के करीब 23 हजार students ने एक painting प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। वहाँ उन्हें भारत की संस्कृति और दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को बताने वाली paintings तैयार करनी थी। मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी युवाओं की सराहना करता हूँ। उनकी creativity की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है।

दक्षिण अमेरिका का एक देश है पराग्वे। वहाँ रहने वाले भारतीयों की संख्या एक हजार से ज्यादा नहीं होगी। पराग्वे में एक अद्भुत प्रयास हो रहा है। वहाँ भारतीय दूतावास में एरीका ह्युबर free आयुर्वेद consultation देती हैं। आयुर्वेद की सलाह लेने के लिए उनके पास स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। एरीका ह्युबर ने भले ही engineering की

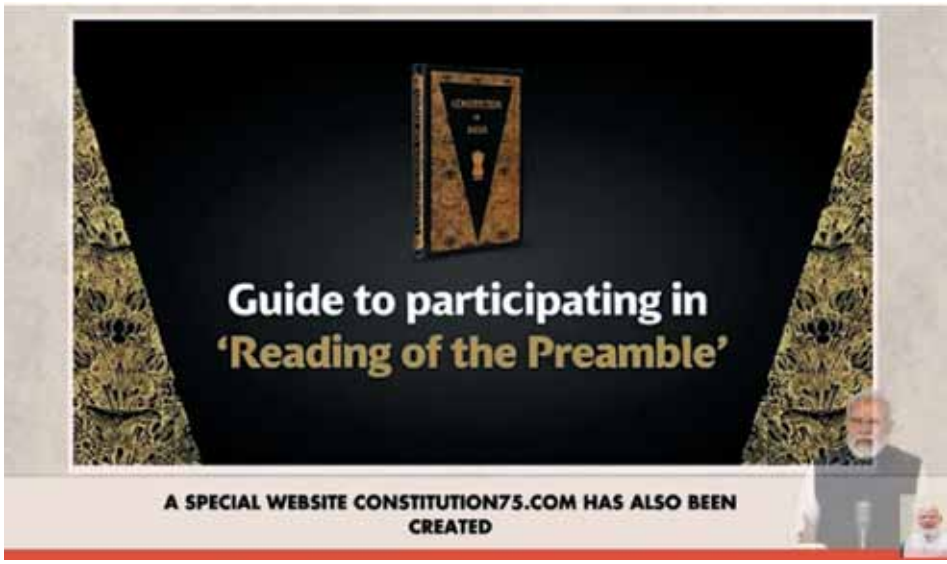

पढ़ाई की हो, लेकिन उनका मन तो आयुर्वेद में ही बसता है। उन्होंने आयुर्वेद से जुड़े Courses किए थे और समय के साथ वे इसमें पारंगत होती चली गई।

ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है और हर हिन्दुस्तानी को इसका गर्व है। दुनियाभर के देशों में इसे सीखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले महीने के आखिर में फिजी में भारत सरकार के सहयोग से Tamil Teaching Programme शुरू हुआ। बीते 80 वर्षों में यह पहला अवसर है, जब फिजी में तमिल के Trained Teachers इस भाषा को सिखा रहे हैं। फिजी के students तमिल भाषा और संस्कृति को सीखने में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं।

ये बातें, ये घटनाएं, सिर्फ सफलता की कहानियाँ नहीं है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की भी गाथाएं हैं। ये उदाहरण हमें गर्व से भर देते हैं। Art से आयुर्वेद तक और Language से लेकर Music तक, भारत में इतना कुछ है, जो दुनिया में छा रहा है।

सर्दी के इस मौसम में देश-भर से खेल और fitness को लेकर कई activities हो रही हैं। मुझे खुशी है कि लोग fitness को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। कश्मीर में Skiing से लेकर गुजरात में पतंगबाजी तक, हर तरफ, खेल का उत्साह देखने को मिल रहा है। #SundayOnCycle और#CyclingTuesday जैसे अभियानों से Cycling को बढ़ावा मिल रहा है।

अब मैं आपको एक ऐसी अनोखी बात बताना चाहता हूँ जो हमारे देश में आ रहे बदलाव और युवा साथियों के जोश और जज्बे का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि हमारे बस्तर में एक अनूठा Olympic शुरू हुआ है! जी हाँ, पहली बार हुए बस्तर Olympic से बस्तर में एक नई क्रांति जन्म ले रही है। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि बस्तर Olympic का सपना साकार हुआ है। आपको भी ये जानकार अच्छा लगेगा कि यह उस क्षेत्र में हो रहा है, जो कभी माओवादी हिंसा का गवाह रहा है। बस्तर Olympic का शुभंकर है - 'वन भैंसा' और 'पहाड़ी मैना'। इसमें बस्तर की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखती है। इस बस्तर खेल महाकुंभ का मूल मंत्र है -

'करसाय ता बस्तर बरसाए ता बस्तर'
यानि 'खेलेगा बस्तर - जीतेगा बस्तर'।

पहली ही बार में बस्तर Olympic में 7 जिलों के एक लाख 65 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है - यह हमारे युवाओं के संकल्प की गौरव-गाथा है। Athletics, तीरंदाजी, Badminton, Football, Hockey, Weightlifting, Karate, कबड्डी, खो-खो और Volleyball - हर खेल में हमारे युवाओं ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। कारी कश्यप जी की कहानी मुझे बहुत प्रेरित करती है। एक छोटे से गांव से आने वाली कारी जी ने तीरंदाजी में रजत पदक जीता है। वे कहती हैं - ''बस्तर खुशी ने हमें सिर्फ खेल का मैदान ही नहीं, जीवन में आगे बढ़ने का अवसर दिया है''। सुकमा की पायल कवासी जी की बात भी कम प्रेरणादायक नहीं है। Javelin Throw में स्वर्ण पदक जीतने वाली पायल जी कहती हैं - ''अनुशासन और कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है''। सुकमा के दोरनापाल के पुनेम सन्ना जी की कहानी तो नए भारत की प्रेरक कथा है। एक समय नक्सली प्रभाव में आए पुनेम जी आज wheelchair पर दौड़कर मेडल जीत रहे हैं। उनका साहस और हौसला हर किसी के लिए प्रेरणा है। कोडागांव के तीरंदाज रंजू सोरी जी को 'बस्तर youth Icon' चुना गया है। उनका मानना है - बस्तर Olympic दूरदराज के युवाओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का अवसर दे रहा है।

बस्तर Olympic केवल एक खेल आयोजन नहीं है। यह एक ऐसा मंच है जहां विकास और खेल का संगम हो रहा है। जहां हमारे युवा अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं और एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ :

अपने क्षेत्र में ऐसे खेल आयोजनों को प्रोत्साहित करें

#खेलेगा भारत - जीतेगा भारत के साथ अपने क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं की कहानियां साझा करें

स्थानीय खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर दें

याद रखिए, खेल से, न केवल शारीरिक विकास होता है, बल्कि ये Sportsman spirit से समाज को जोड़ने का भी एक सशक्त माध्यम है। तो खूब खेलिए-खूब खिलिए।

भारत की दो बड़ी उपलब्धियां आज विश्व का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। इन्हें सुनकर आपको भी गर्व महसूस होगा। ये दोनों सफलताएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिली हैं। पहली उपलब्धि मिली है -मलेरिया से लड़ाई में। मलेरिया की बीमारी चार हजार वर्षों से मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। आजादी के समय भी यह हमारी सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक थी। एक महीने से लेकर पांच साल तक के बच्चों की जान लेने वाली सभी संक्रामक बीमारियों में मलेरिया का तीसरा स्थान है। मैं संतोष से कह सकता हूँ कि देशवासियों ने मिलकर इस चुनौती का दृढ़ता से मुकाबला किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन - WHO की रिपोर्ट कहती है - ''भारत में 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में 80 प्रतिशत की कमी आई है''। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। सबसे सुखद बात यह है, यह सफलता जन-जन की भागीदारी से मिली है। भारत के कोने-कोने से, हर जिले से हर कोई इस अभियान का हिस्सा बना है। असम में जोरहाट के चाय बागानों में मलेरिया चार साल पहले तक लोगों की चिंता की एक बड़ी वजह बना हुआ था। लेकिन जब इसके उन्मूलन के लिए चाय बागान में रहने वाले एकजुट हुए, तो इसमें काफी हद तक सफलता मिलने लगी। अपने इस प्रयास में उन्होनें Technology के साथ-साथ Social

media का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। इसी तरह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले ने मलेरिया पर नियंत्रण के लिए बड़ा अच्छा model पेश किया। यहां मलेरिया की monitoring के लिए जनभागीदारी काफी सफल रही है। नुक्कड़ नाटक और रेडियो के जरिए ऐसे संदेशों पर जोर दिया गया, जिससे मच्छरों की breeding कम करने में काफी मदद मिली है। देश-भर में ऐसे प्रयासों से ही हम मलेरिया के खिलाफ जंग को और तेजी से आगे बढ़ा पाए हैं।

अपनी जागरूकता और संकल्प शक्ति से हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, इसका दूसरा उदाहरण है cancer से लड़ाई। दुनिया के मशहूर Medical Journal Lancet की study वाकई बहुत उम्मीद बढ़ाने वाली है। इस Journal के मुताबिक अब भारत में समय पर cancer का इलाज शुरू होने की संभावना काफी बढ़ गई है। समय पर इलाज का मतलब है - cancer मरीज का treatment 30 दिनों के भीतर ही शुरू हो जाना और इसमें बड़ी भूमिका निभाई है - 'आयुष्मान भारत योजना' ने। इस योजना की वजह से cancer के 90 प्रतिशत मरीज, समय पर अपना इलाज शुरू करा पाए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले पैसे के अभाव में गरीब मरीज cancer की जांच में, उसके इलाज से कतराते थे। अब 'आयुष्मान भारत योजना' उनके लिए बड़ा संबल बनी है। अब वो आगे बढ़कर अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। 'आयुष्मान भारत योजना' ने cancer के इलाज में आने वाली पैसों की परेशानी को काफी हद तक कम किया है। अच्छा ये भी है, कि आज समय पर, cancer के इलाज को लेकर, लोग, पहले से कहीं अधिक जागरूक हुए हैं। यह उपलब्धि जितनी हमारे Healthcare system की है, डॉक्टरों, नर्सों और Technical staff की है, उतनी ही, सभी नागरिक भाई-बहनों की भी है। सबके प्रयास से cancer को हराने का संकल्प और मजबूत हुआ है। इस सफलता का credit उन सभी को जाता है, जिन्होनें जागरूकता फैलाने में अपना अहम योगदान दिया है।

Cancer से मुकाबले के लिए एक ही मंत्र है - Awareness, Action और Assurance. Awareness यानि cancer और इसके लक्षणों के प्रति जागरूकता, Action यानि समय पर जांच और इलाज, Assurance यानि मरीजों के लिए हर मदद उपलब्ध होने का विश्वास। हम सब मिलकर cancer के खिलाफ इस लड़ाई को तेजी से आगे ले जाएं और ज्यादा-से-ज्यादा मरीजों की मदद करें।

आपको ओडिशा के कालाहांडी के एक ऐसे

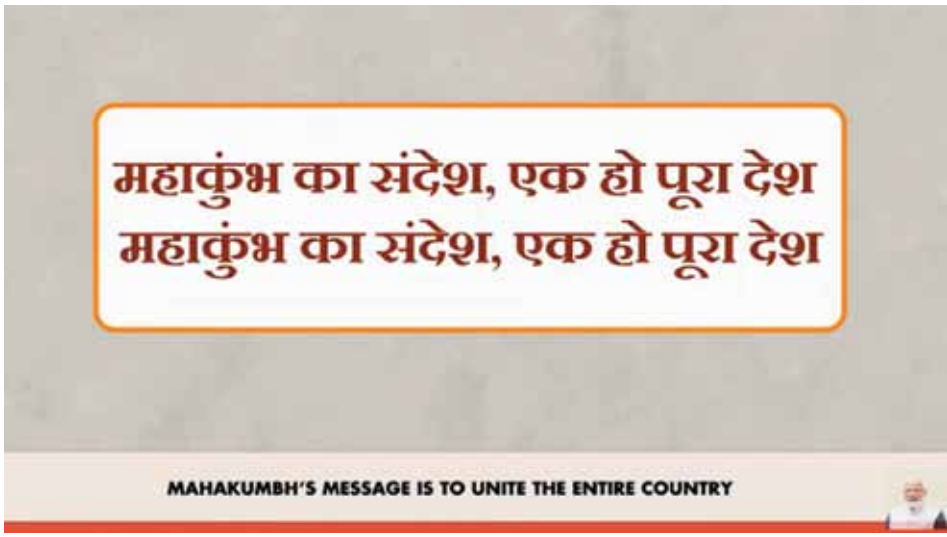

प्रयास की बात बताना चाहता हूँ, जो कम पानी और कम संसाधनों के बावजूद सफलता की नई गाथा लिख रहा है। ये है कालाहांडी की 'सब्जी क्रांति'। जहां, कभी किसान, पलायन करने को मजबूर थे, वहीं आज, कालाहांडी का गोलामुंडा ब्लॉक एक vegetable hub बन गया है। यह परिवर्तन कैसे आया? इसकी शुरुआत सिर्फ 10 किसानों के एक छोटे से समूह से हुई। इस समूह ने मिलकर एक FPO - 'किसान उत्पाद संघ' की स्थापना की, खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया, और आज उनका ये FPO करोड़ों का कारोबार कर रहा है। आज FPO से अधिक किसान इस FPO से जुड़े हैं, जिनमें 45 महिला किसान भी हैं। ये लोग मिलकर 200 एकड़ में टमाटर की खेती कर रहे हैं, 150 एकड़ में करेले का उत्पादन कर रहे हैं। अब इस FPO का सालाना turnover भी बढ़कर डेढ़ करोड़ से ज्यादा हो गया है। आज कालाहांडी की सब्जियां, न केवल ओडिशा के विभिन्न जिलों में, बल्कि, दूसरे राज्यों में भी पहुँच रही हैं, और वहाँ का किसान, अब, आलू और प्याज की खेती की नई तकनीकें सीख रहा है।

कालाहांडी की यह सफलता हमें सिखाती है कि संकल्प शक्ति और सामूहिक प्रयास से क्या नहीं किया जा सकता। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ :-

अपने क्षेत्र में FPO को प्रोत्साहित करें

किसान उत्पादक संगठनों से जुड़ें और उन्हें मजबूत बनाएं।

याद रखिए - छोटी शुरुआत से भी बड़े परिवर्तन संभव हैं। हमें, बस, दृढ़ संकल्प और टीम भावना की जरूरत है।

'मन की बात' में हमने सुना, कि कैसे हमारा भारत, विविधता में एकता के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे वो खेल का मैदान हो या विज्ञान का क्षेत्र, स्वास्थ हो या शिक्षा - हर क्षेत्र में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमने एक परिवार की तरह मिलकर हर चुनौती का सामना किया और नई सफलताएं हासिल की। 2014 से शुरू हुए 'मन की बात' के 116 episodes में मैंने देखा है कि 'मन की बात' देश की सामूहिक शक्ति का एक जीवंत दस्तावेज बन गया है। सभी ने इस कार्यक्रम को अपनाया, अपना बनाया। हर महीने आपने अपने विचारों और प्रयासों को साझा किया। कभी किसी young innovator के Idea ने प्रभावित किया, तो कभी किसी बेटी की achievement ने गौरवान्वित किया।

ये आप सभी की भागीदारी है जो देश के कोने-कोने से positive energy को एक साथ लाती है। 'मन की बात' इसी positive energy के amplification का मंच बन गया है, और अब, 2025 दस्तक दे रहा है। आने वाले साल में 'मन की बात' के माध्यम से हम और भी Inspiring प्रयासों को साझा करेंगें। विश्वास है कि देशवासियों की positive सोच और Innovation की भावना से भारत नई ऊंचाइयों को छूएगा।

आप अपने आस-पास के unique प्रयासों को #Mannkibaat के साथ share करते रहिए। मैं जानता हूँ कि अगले साल की हर 'मन की बात' में हमारे पास एक दूसरे से साझा करने के लिए बहुत कुछ होगा। सभी को 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, Fit India Movement में आप भी जुड़ जाइए, खुद को भी fit रखिए। जीवन में प्रगति करते रहें। ▪

सूर्य नारायण का पर्व है मकर संक्रान्ति

प्रयागराज में हर साल माघ मेला लगता है, जहाँ भक्तगण कल्पवास करते है, यहाँ हर बारह वर्षों के बाद कुंभ मेला लगता है, जबकि छः वर्ष के पश्चात अर्धकुंभ लगता है।

मकर संक्रान्ति का हमारे देश में बहुत ज्यादा सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक महत्व है। इसी कारण रामचरित मानस में उल्लेखित है-

माघ मकरगत रबि जब होई।
तीरथपतिहिं आव सब कोई।।
देव दनुज किंनर नर श्रेनीं।
सादर मज्जहिं सकल त्रिबेनी।।
पूजही माधव पद जल जाता।
परसि अखय बटु हरषहिं गाता।।

ऐसा माना जाता है, कि प्रयाग में संगम पर मकर संक्रान्ति के दिन सारे देव-देवियाँ स्नान करने आते है, इसीलिये प्रयाग में इस दिन स्नान करना अत्याधिक पुण्यकारक माना गया है। प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रान्ति होती है, क्योंकि आज ही के दिन सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होकर धनु से मकर राशि में प्रविष्ट होते है, जो सूर्य के पुत्र शनि की राशि है। मकर संक्रान्ति का बहुत बड़ा मेला गंगासागर में लगता है, इसके पीछे की एक कथा है, कि मकर संक्रान्ति को ही गंगाजी स्वर्ग से उतर कर भागीरथ जी के पीछे-पीछे चलकर कपिल मुनी के आश्रम में जाकर सागर से मिल गई थी। गंगा जी के इसी पावन जल से राजा सगर के साठ हजार पुत्रों का जो शाप से पीड़ित थे उनका उद्धार हुआ, इसी घटना की याद में ये तीर्थ गंगासागर के नाम से विख्यात हुआ और इसीलिये यहाँ पर विशाल मेले का मकर संक्रान्ति के दिन आयोजन होता है।

प्रयागराज में हर साल माघ मेला लगता है, जहाँ भक्तगण कल्पवास करते है, यहाँ हर बारह वर्षों के बाद कुंभ मेला लगता है, जबकि छः वर्ष के पश्चात अर्धकुंभ लगता है। ऐसा माना जाता है, कि मकर संक्रान्ति से सूर्य की गति तिल-तिल करके बढ़ती है, इसीलिये इस दिन तिल और गुड़ के दान का महत्व है। इस दिन को पंजाब व जम्मू-कश्मीर में 'लोहड़ी' के रूप में मनाते है, इसके पीछे एक लोक कथा है, कि मकर संक्रान्ति के ही दिन कंस ने भगवान श्रीकृष्ण को मारने के लिये लोहिता नाम की एक राक्षसी को गोकुल भेजा था, जिसे श्रीकृष्ण ने खेल-खेल में ही मार डाला था, इसी घटना की याद में इसे लोहिड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। सिन्धी समाज भी मकर-संक्रान्ति के एक दिन पूर्व इसे 'लाह-लोही' के रूप में मनाते है। इसी प्रकार तमिलनाडु में मकर संक्रान्ति को 'पोंगल' के रूप में मनाते है, जिसमें तिल, चावल व दाल की खिचड़ी बनाते है, क्योंकि वे नई फसल का चावल, दाल, तिल से पूजा करके कृषि देवता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते है, इसी दिन से तमिल पंचांग का नया वर्ष पोंगल शुरु होता है। माघ मास के स्नान का प्रारम्भ पौष की पूर्णिमा से प्रारम्भ हो जाता है। भारतीय संवत्सर का ग्यारहवाँ चान्द्रमास और दसवाँ सौर मास 'माघ' कहलाता है। क्योंकि इस माह मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इसीलिये इसका नाम माघ पड़ा। धार्मिक दृष्टिकोण से माघ माह का बहुत महत्व है। इस माह में जल के भीतर डुबकी लगाने से प्राणी पापमुक्त हो जाता है। इस माह की ऐसी विशेषता है, कि इसमें जहाँ कही भी जल हो, वह गंगाजल के समान होता है। इसी प्रसंग में पद्मपुराण में एक कथा का वर्णन है कि प्राचीन काल में नर्मदा जी के तट पर सुव्रत नामक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत ज्ञानी थे उन्हें वेद, पुराणों, ज्योतिष, तर्क, मंत्र, सांख्य, योग व चौसठ कलाओं का अच्छा खासा ज्ञान था। वे अनेक देशों की भाषा व लिपियाँ भी जानते थे। इतने ज्ञानी होने के बाद भी वे अपने ज्ञान का प्रयोग धार्मिक कार्यों के लिये न करते हुए धन कमाने के लिये करते थे, जिससे उन्होंने कई स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर ली। धन कमाते-कमाते वे बूढ़े हो गये और बीमारी ने आ घेरा। तब उनके मन में विवेक का उदय हुआ कि मैंने अपना सारा जीवन धनार्जन में लगा दिया, परलोक की तो सोची ही नहीं, मेरा उद्धार कैसे हो? वे इसी सोच में थे कि इसी दौरान उनका संग्रहित धन भी चोरी हो गया, जिससे उन्हें धन की वास्तविक नश्वरता का बोध भी हुआ। अब उन्हें चिन्ता थी, तो सिर्फ परलोक की। व्याकुलता में उन्हें ये श्लोक याद आया-

माघे निमग्नाः सलिले सुशीते
विमुक्तपापास्त्रिदिवं प्रयान्ति।।

सुव्रत को अपने उद्धार का मूल मंत्र मिल गया, उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और नर्मदा जी में लगातार नौ दिन तक स्नान किया। दसवे दिन स्नान के बाद उनके प्राणांत हो गये। यद्यपि उन्होंने जीवन भर कोई सत्कर्म नहीं किया था, धनार्जन ही किया था, परन्तु माघ मास में स्नान के कारण निर्मल मन से पश्चाताप करते हुए उन्हें देवलोक की प्राप्ति हुई।

भारतीय ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रान्ति के दिन सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में हुए परिवर्तन को अन्धकार से प्रकाश की ओर हुआ परिवर्तन माना जाता है। सूर्योपासना का पर्व मकर संक्रान्ति हिन्दुओं द्वारा अंग्रेजी कलैन्डर के अनुसार मनाया जाने वाला एकमात्र पर्व है, जो प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये माना जाता है, कि कुल 12 राशियों में से प्रत्येक राशि में सूर्य का भ्रमण काल एक माह तक होता है, इसीलिये प्रत्येक वर्ष सूर्य 14जनवरी के आस-पास मकर राशि में प्रवेश करता है। यह स्थिति वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित मकर रेखा के उत्तर की ओर सूर्य के प्रवेश की होती है, इसीलिये इसे सूर्य का उत्तरायण में आना भी कहा जाता है, जो धार्मिक आधार पर शुभता का प्रतीक है। ▪

पं. सलिल मालवीय

भारत को विश्वगुरु बनना है

सुबह की शांत वेला है। सदा की तरह मैं अपने भगवान् के साथ हूँ। मन को बेचैन करने वाले विचारों को बुझाने और ईश्वर के आगे दीये जलाने का प्रयास करती हूँ। आँखों के आगे धुँधलका घिर आता है। इस धुँधलके में देश को गलत दिशा में ले जाने वाले नेताओं की श्रृंखला उभरती है। पिछले दिनों उजागर हुए उच्च पदों पर आसीन, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोगों के चेहरे हैं। घोटाले ही घोटाले परदा उठ रहा है।

मन के बैचेन क्षण में ही वह शाश्वत पंक्ति कौंधती है 'कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।' लेकिन परिश्रम वाला फल की आशा न करे, यह बात मन को जँचती नहीं थी। पराभूतों का यह ध्येय वाक्य मेरे आहत मन को शांत नहीं कर पा रहा था। आखिर मैं एक कार्यकर्ता हूँ। हाड़मांस की बनी एक नारी हूँ। आजीवन मैंने फल की आशा रखी तो इसमें मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। यह फल, यह सफलता मैंने केवल अपने लिए कब चाही थी। सौभाग्य से मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं रही, मैं तो किसी और उद्देश्य के लिए लड़ रही थी। अपने सभी साथियों से कदम मिलाए मेरी सारी भागदौड़ और छटपटाहट केवल इसलिए थी कि दिग्भ्रमित शासकों द्वारा राष्ट्र व जनजीवन में तेजी के साथ होता जा रहा अधःपतन रोक सकूँ। अपने करोड़ों देशवासियों के बारे में मेरा सपना एकदम सामान्य है। मेरे देवता भी इसे जानते हैं। मैं तो उनसे दामन पसारे केवल इतना ही माँग रही थी कि इन करोड़ों जीवों को रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए किसी के सामने हाथ पसारने की नौबत न आए और मानव द्वारा मानव के लिए पैदा किए गए दुःखों का यथासंभव परिहार हो सके। इससे अधिक मैं कुछ भी नहीं माँग रही थी। इसी उद्देश्य से इतना सारा परिश्रम, इतनी दौड़धूप और इतना समर्पण करने के बाद थोड़े दिन के लिए ही सही, वह दिन भी देख लिया, जिससे मन को संतोष हुआ कि सपना पूरा हो सकता है। वह समय पुनः आएगा और युगों तक चलेगा। मेरे पास की पूँजी, इतना ही संतोष क्या कम है कि मैंने जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। लोगों को अनाप-शनाप आश्वासनों के सब्जबाग दिखाकर चुनाव नहीं जीते। मैं अपने आपको धन्य मानती हूँ कि मेरे हाथों लोगों का विश्वासघात कभी नहीं हुआ। बड़े शहरों में बसे झोंपड़पट्टी वालों की दुर्दशा का कारण मैं नहीं हूँ। दिल्ली के सिक्खों और पंजाब तथा कश्मीर के हिंदुओं का जीवन बिताने वाले लोगों को मैंने धोखा नहीं दिया है। गरीबी हटाने का जादू अपने पास होने का झूठा दावा कर मैंने किसी को नहीं भरमाया है। बड़े से बड़े घोटालों में मैं कहीं नहीं हूँ। सर्वत्र हिंसा, आतंक, अपहरण, लूट का वातावरण बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं रहा है। मेरी इस आयु में यह संतोष धन क्या कम है।

आँखों के सामने घिर आया कुहासा छँट जाता है। आरती की ज्योति फिर से अपना प्रकाश फैलाने लगती है। मेरे देवताओं की मूर्तियाँ उस प्रकाश में फिर से देदीप्यमान हो उठती हैं। मन में उठे सारे संदेह, शंका व कुंठाएँ समाप्त हो जाती हैं। मैं आत्मचिंतन में विभोर हो जाती हूँ तो मुझे अपने भाग्य से ईर्ष्या होने लगती है। नाना खड्ग शमशेर जंगबहादुर राणा की दृढ़ता, पिता ठाकुर महेन्द्र सिंह की निस्पृहता और पति जिवाजीराव की दिलेरी मुझे विरासत में मिली है। यह त्रिवेणी संगम एक महान संस्कार धन के रूप में मुझे धरोहर के नाते मिला और वही मेरा पाथेय रहा है, बची हुई जिंदगी में भी रहेगा। शेष यात्रा भी उसी के सहारे चलती रहे, बस इससे अधिक मुझे कुछ और नहीं चाहिए; सचमुच में कुछ नहीं चाहिए। पुनः कर्तव्यपथ पर चलते रहने की प्रेरणा मिलती है। बचपन में ही मन मे एक प्रश्न उठा करता था 'मातृभूमि को गुलाम क्यों कहते हैं?' और इस प्रश्न के साथ मन पीड़ा से भर उठता था। ज्यों-ज्यों बड़ी होती गई, भारत माँ को स्वतंत्र कराने वाले आंदोलनकारियों ने प्रेरित किया। उनके संघर्ष ने मन को उद्वेलित किया। मातृभूमि को स्वतंत्र बनाना उनके लिए एक यज्ञ था। उस यज्ञ में समिधा बनने का भाव मन में घर करता गया। हिंदू दर्शन में जीवन ही एक यज्ञ है। छोटे यज्ञ से बड़े यज्ञ के लिए जीना भी यज्ञ ही है। इसलिए समाज हित में अपनी छोटी-सी जिंदगी का एक कदम भी उठे तो चिरंतन चलने वाले महायज्ञ में एक समिधा डालने के बराबर ही है। समाज शाश्वत है। समाज को दिशा देने में, उसकी दशा पर विचार करते रहने में मात्र तत्कालीन सरकार व शासन की भूमिका नहीं रहती रही है। यह संतों की भूमि है। समाज को अक्षुण्ण बनाए रखने में समय समय पर उन्होंने भी अपने जीवन की आहुति दी है। आठ सौ वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव में रहे भारत में समाज जीवन के मूल्यों के बीज तत्व को ऋषि मुनियों, संत महात्माओं और मठ आश्रमों ने ही सँभालकर रखा। पिछले सारे वर्षों से संघ परिवार की भूमिका भी इसी परंपरा को जीवित रखने का प्रयास है। अपने देश में वोट प्राप्ति का लोभ और कुरसी की खातिर राजनीतिज्ञ भी भ्रमित हुए हैं।

समाज की समरसता को जाति और धर्म के नाम पर छिन्नभिन्न करने, भोग के लिए जीने, व्यक्तिशः अपनी जिंदगी जीने के भाव घर करने लगे हैं। हिंदू जीवन पद्धति जीवन को समग्रता को देखने की है। 'ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्' का आदर्श यहाँ नहीं चल सकता। जमाखोरी और भ्रष्टाचार बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। ये स्थितियाँ सनातन हिंदू जीवन मूल्यों के विपरीत हैं। इसलिए समाज में कसमसाहट है। यह कसमसाहट की स्थिति समाप्त होगी। नजर के सामने संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार, गुरुजी गोलवलकर, बालासाहब देवरस की तस्वीर उभरती है। बालासाहब देवरस ने अपने जीते जी अस्वस्थता की स्थिति में अपना उाराधिकारी नियुक्त कर दिया, नई परंपरा डाली। प्रसन्नता है कि संघ परिवार की राष्ट्रवादी विचारधारा को जनमानस स्वीकारने लगा है। इस विचारधारा को आज कोई चुनौती नहीं है। यह एक व्यापक अनुभूति बन रही है कि राष्ट्र अपनी जड़ों को नहीं छोड़ सकता। किसी भी विपरीत परिस्थिति में राष्ट्र एक होकर खड़ा हो जाएगा। महान भारत की रचना, समृद्धिशाली भारत का सपना लेकर संघ परिवार आगे बढ़ रहा है। परिवार बृहत् से बृहत्तर होता जा रहा है। एक दिन भारत को पुनः विश्व गुरु बनना है। व्यक्ति जीवन में शुचिता, प्रशासकीय जीवन में पारदर्शिता, लोक जीवन में स्वावलंबन, समाज जीवन में समरसता के बिना हम लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते। **चरैवेति चरैवेति** संकल्प से राष्ट्र जीवन चिरंतन बना रहेगा। ▪

(पुस्तक राजपथ से लोकपथ से साभार)

भारत के राष्ट्रवाद की अवधारणा

देश आजाद होने के बाद स्वाभाविक रूप से यह सवाल हम सब लोगों के सामने आना चाहिए था कि अब हमारे देश की दिशा क्या होगी?

किन्तु सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि देश की स्वतंत्रता के बाद भी जितने गंभीर रूप से इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए था, उतना गम्भीर रूप से लोगों ने विचार नहीं किया।

पं. दीनदयाल उपाध्याय

अंग्रेजों के शासनकाल में देश में जितने भी आन्दोलन चले और देश की जितनी भी राजनीति थी, उन सबका एक ही लक्ष्य था कि अंग्रेजों को हटाकर हम स्वराज्य प्राप्त करें। स्वराज्य के बाद हमारा रूप क्या होगा? हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे? इसका बहुत कुछ विचार नहीं हुआ था। बहुत कुछ शब्द का मैंने प्रयोग इसलिए किया है कि बिलकुल विचार नहीं हुआ था यह कहना ठीक न होगा। ऐसे लोग थे कि जिन्होंने उस समय भी बहुत-सी बातों पर विचार किया था। स्वयं गांधी जी ने हिन्द स्वराज्य लिखकर उसमें स्वराज्य आने के बाद भारत का चित्र क्या होगा, इस पर अपने विचार रखे थे। उसके पहले लोकमान्य तिलक ने भी गीता रहस्य लिखकर संपूर्ण आंदोलन के पीछे की तात्विक भूमिका क्या होगी, इसका विवेचन किया था। साथ ही उस समय दुनिया में जो भिन्न-भिन्न विचारसरणियां चल रही थी, उनकी भी तुलनात्मक दृष्टि से आलोचना की थी।

इसके अतिरिक्त समय-समय पर कांग्रेस या दूसरे राजनैतिक दलों ने जो प्रस्ताव स्वीकार किये, उनमें भी ये विचार आये थे। किन्तु उन सबका जितना गंभीर अध्ययन होना चाहिए था, उतना उस समय तक नहीं हुआ था। क्योंकि सबके सामने प्रमुख प्रश्न यही था कि पहले अंग्रेजों को निकालें फिर अपने घर का निर्माण कैसे करेंगे, इसका विचार कर लेंगे। इसलिए यदि विचारों के मतभेद भी कहीं थे तो लोगों ने उनको दबा करके रखा था। यहाँ तक कि समाजवाद के आधार पर आगे का भारत बनना चाहिए, इस तरह का विचार करने वाले जो लोग थे, वे कांग्रेस के अन्दर ही एक सोशलिस्ट पार्टी बनाकर काम करते रहे। उसके बाहर निकलकर उन्होंने अलग से कार्य करने का प्रयत्न नहीं किया। क्रान्तिकारी भी अपने-अपने विचारों के अनुसार स्वराज्य के लिए काम करते थे। इसी प्रकार और भी लोग थे। किन्तु प्रमुखता इसी बात की रही कि पहले देश को आजाद कर लिया जाए।

अतः देश आजाद होने के बाद स्वाभाविक रूप से यह सवाल हम सब लोगों के सामने आना चाहिए था कि अब हमारे देश की दिशा क्या होगी? किन्तु सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि देश की स्वतंत्रता के बाद भी जितने गंभीर रूप से इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए था, उतना गंभीर रूप से लोगों ने विचार नहीं किया और आज भी जब इतने वर्ष देश को स्वतन्त्र हुए हो गए हम यह नहीं कह सकते कि कोई दिशा निश्चित हो गयी है।

भारत किधर जाने वाला है?

समय-समय पर कांग्रेस या दूसरे दल के लोगों ने कल्याणकारी राज्य, समाजवाद, उदारमतवाद, आदि का ध्येय अवश्य घोषित किया है। विविध नारे लगाये गये हैं। परन्तु ये जितने नारे लगाने वाले लोग हैं, उनके सामने उन सब विचार धाराओं का नारे से अधिक कोई महत्व नहीं रहता। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका मुझे अनुभव है। एक बार एक सज्जन से बातचीत हो रही थी। वह कह रहे थे कि कांग्रेस के विरूद्ध मिल-जुलकर अपने को एक मोर्चा बनाना चाहिए ताकि अच्छी तरह से लड़ सकें। राजनीतिक दृष्टि से समय-समय पर इस प्रकार की नीतियाँ लेकर दल चलते है और इसलिए उनके इस प्रस्ताव में तो कोई अनुचित बात नहीं थी। परन्तु बात करते-करते मैंने सहज में पूछ लिया कि हम लोग मोर्चा तो शायद बना लेंगे परन्तु कुछ थोड़ा बहुत कार्यक्रम लेकर चलें? कौन सा आर्थिक कार्यक्रम लेकर चलें? कौनसा राजनैतिक कार्यक्रम लेकर चलें? इन

प्रश्नों पर भी विचार करना चाहिए।

इस पर उन्होंने सहज भाव से कह दिया कि इसकी कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो पसन्द हो स्वीकार कर लीजिए। हम तो घोर साम्यवादी कार्यक्रम से लेकर बिल्कुल पूंजीवादी कार्यक्रम तक जो आप चाहें उसमें समर्थन कर देंगे। उनको किसी भी कार्यक्रम में कोई आपत्ति नहीं थी। उद्देश्य केवल इतना ही था कि किसी न किसी तरीके से कांग्रेस को हरा देना चाहिए। आज भी बहुत बार लोग कहते हैं कि कम्युनिस्टों तथा बाकी सब लोगों से मिलकर भी कांग्रेस को हरा दिया जाए।

साँप-नेवला एक साथ

केरल में अभी-अभी चुनाव हुए हैं। उसमें कम्युनिस्ट, मुस्लिम लीग, स्वतंत्र पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, विद्रोही कांग्रेस जो केरल कांग्रेस के नाम से आई, क्रान्तिकारी सोशलिस्ट पार्टी आदि जितनी भी पार्टियां हैं, इनमें आपस में भिन्न-भिन्न प्रकार से गठबंधन हुए। इन गठबन्धनों के कारण यह पता नहीं लग सकता था कि इनके कोई राजनीतिक सिद्धान्त, विचार अथवा आदर्श भी हैं या नहीं। विचारों की दृष्टि से यह स्थिति है। कांग्रेस में भी यही बात दिखाई दे रही है। यद्यपि कांग्रेस ने प्रजातन्त्रीय समाजवाद का सिद्धान्त स्वीकार किया है तथापि कांग्रेस के लोग जो बोलते हैं उनमें यही दिखाई देता है कि वहाँ पर एक निश्चित सिद्धान्त निश्चित कार्यक्रम नहीं। घोर कम्युनिस्ट विचारधारा वाले भी कांग्रेस के अन्दर विद्यमान हैं और उस कम्युनिज्म का डटकर विरोध करते हुए पूँजीवादी विचारधारा वाले भी कांग्रेस के अन्दर मौजूद हैं। अहिनकुल योग के अनुसार नकुल और साँप के सहअस्तित्व का कोई जादू का पिटारा हो सकता है तो वह आज की कांग्रेस है।

हमें आत्माभिमुख होना पड़ेगा

इस स्थिति में हम आगे बढ़ सकेंगे या नहीं, इसका हमें विचार करना चाहिए। देश में आज की अनेक समस्याओं की कारण मीमांसा करें तो पता चलेगा कि अपने गन्तव्य और उसकी दिशा का अज्ञान बहुतांश में आज की अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। यह तो मैं मानता हूं कि हिन्दुस्थान के सभी 45 करोड़ लोग सब प्रश्नों पर अथवा किसी एक प्रश्न पर भी पूर्णतः एक विचार और एक मत नहीं हो सकते। किसी भी देश में यह संभव नहीं है। फिर भी राष्ट्र की एक सामान्य इच्छा नाम की कोई चीज होती है। उसको आधार बनाकर काम किया जाएं तो सर्वमान्य व्यक्ति को लगता है कि मेरे मन के मुताबिक काम हो रहा है। उसमें से विचारों की अधिकतम एकता भी पैदा होती हैं। अक्टूबर-नवम्बर 1962 में कम्युनिस्ट चीन के आक्रमण के समय जनता की अवस्था इस तथ्य का अच्छा उदाहरण है। इस समय देश में एक उत्साह की लहर पैदा हो गई थी। कर्म तथा त्याग दोनों की शक्ति जाग्रत हो गई थी। जनता और सरकार के बीच भिन्न-भिन्न दलों के बीच तथा नेता और जनता के बीच कोई खाई नहीं दिखाई देती थी। यह सब कैसे हुआ? सरकार ने वह नीति अपनाई जो जनता के मन के अनुसार तथा पुरूषार्थ का आह्वान करने वाली थी। फलतः हम एक होकर खड़े हो गए।

समस्याओं का कारण स्व के प्रति दुर्लक्ष्य

आवश्यकता है कि अपने स्व का विचार किया जाए। बिना उसके स्वराज्य का कोई अर्थ नहीं। स्वतंत्रता हमारे विकास और सुख का साधन नहीं बन सकती। जब तक हमें अपनी असलियत का पता नहीं तब तक हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं हो सकता और न उसका विकास ही संभव है। परतन्त्रता में समाज का स्व दब जाता है। इसीलिए राष्ट्र स्वराज्य की कामना करते हैं जिससे वे अपनी प्रकृति और गुणधर्म के अनुसार प्रयत्न करते हुए सुख की अनुभूति कर सकें। प्रकृति बलवती होती है। उसके प्रतिकूल काम करने से अथवा उसकी ओर दुर्लक्ष्य करने से कष्ट होते हैं। प्रकृति का उन्नयन कर उसे संस्कृति बनाया जा सकता है, पर उसकी अवहेलना नहीं कर सकती। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि किसी प्रकार मानव प्रकृति एवं भावों की अवहेलना से व्यक्ति के जीवन में अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रायः उदासीन एवं अनमना रहता है। उसकी कर्म शक्ति क्षीण हो हो जाती है अथवा विकृत होकर विपथ गामिनी बन जाती है। व्यक्ति के समान राष्ट्र भी प्रकृति के प्रतिकूल चलने पर अनेक व्यथाओं का शिकार बनता है। आज भारत की अनेक समस्याओं का यही कारण है।

राजनीति में अवसरवादिता

राष्ट्र का मार्गदर्शन करने वाले तथा राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश व्यक्ति इस प्रश्न की ओर उदासीन है। फलतः भारत की राजनीति, अवसरवादी एवं सिद्धान्तहीन व्यक्तियों का अखाड़ा बन गई है। राजनीतिज्ञों तथा राजनीतिक दलों के न कोई सिद्धान्त एवं आदर्श है और न कोई आचार संहिता। एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाने में व्यक्ति को कोई संकोच नहीं होता। दलों के विघटन अथवा विभिन्न दलों की युक्ति भी होती है तो वह किसी तात्विक मतोद अथवा समानता के आधार पर नहीं अपितु उसके मूल में चुनाव और पद ही प्रमुख रूप से रहते हैं। 1937 में जब हाफिज मुहम्मद इब्राहिम मुस्लिम लीग के टिकट पर चुने जाने के बाद कांग्रेस में सम्मिलित हुए तो उन्होंने स्वस्थ राजनीतिक परंपरा के अनुसार विधानसभा से त्याग पत्र देकर पुनः कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर आए। 1948 में जब कांग्रेस से अलग हटकर सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ तब सभी सोशलिस्टों ने, जो विधानमण्डलों के सदस्य थे, त्यागपत्र देकर अपने-अपने क्षेत्र से पुनः चुनाव लड़े। किन्तु उसके बाद किसी ने इस परंपरा का निर्वाह नहीं किया। अब राजनीतिक क्षेत्र में पूर्ण स्वैच्छाचार है। इसी का परिणाम है कि आज भी सभी के विषय में जनता के मन में समान रूप से अनास्था है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं कि जिसकी आचरणहीनता के विषय में कुछ कहा जाए तो जनता विश्वास न करे। इस स्थिति को बदलना होगा। बिना उसके समाज में व्यवस्था और एकता स्थापित नहीं की जा सकती।

हम किस ओर चलें?

हम किस ओर चले? राष्ट्र के सामने यह प्रश्न है। कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्र के परतन्त्र होने के पूर्व एक हजार वर्ष पहले जहाँ हमने राष्ट्र जीवन का सूत्र छोड़ दिया था वहीं से हम उसे आगे बढ़ाएँ। पर राष्ट्र कोई वस्त्र या पुस्तक के समान निर्जीव वस्तु तो है नहीं जिसे बुनते या पढ़ते समय जहाँ एक बार छोड़ दिया, वहाँ से फिर किसी विशेष अतिथि के बाद उसे आगे बढ़ाया जा सके। फिर यह कहना भी युक्ति संगत नहीं होगा कि परतन्त्रता के साथ एक हजार वर्ष पूर्व हमारे जीवन का सूत्र एकदम टूट गया है तथा तब से अब तक हम पूर्णतया निष्क्रिय अथवा गतिहीन रहे हैं। बदली हुई परिस्थितियों में अपने जीवन को बनाये रखने तथा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने में अपने जीवन को अभिव्यक्त किया। हमारे जीवन का प्रवाह अवरूद्ध नहीं अपितु आगे बढ़ता गया।

गंगा की धारा की लौटाने का प्रयत्न बुद्धिमानी नहीं होगी। बनारस की गंगा हरिद्वार के समान शीतल एवं स्वच्छ चाहे न हो, परन्तु उतनी ही पवित्र एवं मुक्ति-दायिनी है। उसमें मिलने वाले जिन नदी-नालों को उसने आत्मसात कर लिया है उनकी कलुषा तथा गन्दगी की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। वे गंगा में मिलकर गंगा ही बन गये हैं। अब तो गंगा के प्रवाह को आगे ही बढ़ाना होगा।

यदि संपूर्ण स्थिति इतनी ही होती तब तो कोई कठिनाई नहीं थी। विश्व में हम अकेले ही तो नहीं है। दूसरे राष्ट्र भी है। उन्होंने पिछले एक हजार वर्ष में अभूतपूर्व उन्नति की है। हमारा संपूर्ण ध्यान तो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने तथा

अपनी रक्षा के प्रयत्नों में ही लगा रहा है। विश्व की इस प्रगति में हम सहभागी नहीं हो सके। अब जब हम स्वतंत्र हो गये हैं तो क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं हो जाता कि हम अपनी इस कमी को शीघ्राति-शीघ्र पूरा करके विश्व के इन प्रगट देशों के साथ खड़े हो जाएँ? यहाँ तक तो, मैं समझता हूं, मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं है।

स्वदेशी की भावना सर्वव्यापी हो

समस्या तब पैदा होती है, जब हम पश्चिम की प्रगति के कारणों तथा परिणामों अथवा वास्तविकता एवं भासवान के सबन्ध में ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाते। यह कठिनाई तब तक बढ़ जाती है जब हम यह देखते हैं कि इन प्रगत देशों में से ही एक ने हमारे ऊपर डेढ़ सौ वर्षों तक राज्य किया तथा अपने राज्यकाल में उसने ऐसे अनेक उपाय किये जिससे हमारे अन्दर अपने सबन्ध में तिरस्कार तथा उनके विषय में आदर का भाव पैदा हो जाए। पश्चिम के ज्ञानविज्ञान के साथ ही पश्चिमी देशों रहन सहन, बोल चाल, खान-पान आदि के तरीके भी इस देश में आये। भौतिक विज्ञान ही नहीं अपितु, नीतिशास्त्र, राज्यव्यवस्था, अर्थनीति तथा समाज धारणा के क्षेत्र में भी इन देशों के मानदण्ड हमारे मानक बन गए। आज भारत के शिक्षित वर्ग के जीवन मूल्यों पर पश्चिम का यह प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता है। हमें निर्णय करना पड़ेगा कि यह प्रभाव अच्छा है या बुरा। जब तक अंग्रेज थे तब तक तो हम स्वदेशी की भावना से अंग्रेजियत को दूर रखने में ही गौरव समझते थे, किन्तु अब जब अंग्रेज चला गया है तब अंग्रेजियत पश्चिम की प्रगति का द्योतक एवं माध्यम बनकर अनुकरण की वस्तु बन गयी है। यदि सत्य है तो संकुचित के भाव का आड़े लाकर राष्ट्र की प्रगति में बाधा डालना ठीक नहीं होगा। किन्तु इसके विपरीत पाश्चात्य जीवन मूल्यों और विज्ञान की प्रगति को यदि अलग किया जा सकता है तो अंग्रेजियत के मोह का परित्याग करना ही हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। पर कुछ लोग ऐसे भी है जो पाश्चात्य राजनीति एवं अर्थनीति की दिशा को ही प्रगति की दिशा समझते हैं और इसलिए भारत पर वहाँ की स्थिति का प्रक्षेपण करना चाहते हैं। अतः भारत की भावी दिशा का निर्णय करने से पूर्व यह उचित होगा कि हम पश्चिम की राजनीति के वैचारिक अधिष्ठान तथा उनकी वर्तमान पहेली का विचार कर लें।

यूरोप में राष्ट्रों का उदय

जिन विचार धाराओं ने यूरोपीय राजनीति एवं जीवन को विशेषतः प्रभावित किया है उनमें राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र तथा समाजवाद की प्रमुख रूप से गणना की जा सकती है। इसके साथ ही विश्व एकता तथा शांति का स्वप्न देखने वाले भी वहाँ हुए है और उस दिशा में भी कुछ प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन विचारों में राष्ट्रवाद सबसे पुराना तथा बलशाली है। रोम के साम्राज्य के पतन के बाद तथा रोमन कैथोलिक चर्च के प्रति विद्रोह अथवा उसके प्रभाव के कमी के कारण यूरोप में राष्ट्रों का उदय हुआ। यूरोप का पिछला एक हजार वर्ष का इतिहास इन राष्ट्रों के आविर्भाव तथा पारस्परिक संघर्ष का इतिहास है। इन राष्ट्रों के आविर्भाव तथा पारस्परिक संघर्ष इतिहास है। इन राष्ट्रों ने यूरोप महाद्वीप से बाहर जाकर अपने उपनिवेश बनाये तथा दूसरे स्वतंत्र देशों को गुलाम बनाया। राष्ट्रवाद के उदय के कारण राष्ट्र और राज्य की एकता की प्रवृत्ति भी बढ़ी तथा राष्ट्रीय राज्य का यूरोप में उदय हुआ। साथ ही रोमन कैथोलिक चर्च के केन्द्रीय भाव में कमी होकर या तो राष्ट्रीय चर्च का निर्माण हुआ या मजहब का। मजहबी गुरुओं का राजनीति में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। सेक्युलर स्टेट की कल्पना का इस प्रकार जन्म हुआ।

यूरोप में प्रजातंत्र का जन्म

दूसरी क्रांतिकारी कल्पना प्रजातंत्र की है जिसका यूरोप की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ है। प्रारंभ में तो जितने राष्ट्र बने उनमें राजा ही शासनकर्ता रहा, किन्तु राजा की निरंकुशता के विरूद्ध जनता में भी धीरे धीरे जागरण हुआ। औद्योगिक क्रांति के कारण तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणाम स्वरूप सभी देशों में एक वैश्य वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। स्वभावतः इनका पुराने सामन्तों तथा राजाओं से संघर्ष आया। इस संघर्ष ने प्रजातंत्र की तात्विक भूमिका ग्रहण की। यूनान के नगर गणराज्यों से इस विचार का उद्‌गम ढूंढा गया। प्रत्येक नागरिक की समानता, बन्धुता और स्वतंत्रता के आदर्श के सहारे जनसाधारण को इस तत्व के प्रति आकृष्ट किया गया। फ्रांस में बड़ी भारी राज्य क्रांति हुई। इंग्लैण्ड में भी समय-समय पर आन्दोलन हुए। प्रजातंत्र की जनपथ पर पकड़ हुई। राजवंश या तो समाप्त कर दिये गये अथवा उनके अधिकार मर्यादित कर वैधानिक राज्य पद्धति की नींव डाली गई। आज प्रजातंत्र यूरोप की मान्य पद्धति है। जिन्होंने प्रजातंत्र की अवहेलना की वे भी प्रजातंत्र के प्रति निष्ठा व्यक्त करने में कमी नहीं करते। हिटलर, मुसोलिनी तथा स्टालिन जैसे तानशाहों ने भी प्रजातंत्र को अमान्य नहीं किया।

व्यक्ति का शोषण होता रहा

प्रजातंत्र ने यद्यपि प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार दिया, किन्तु जिन लोगों ने प्रजातंत्र के संघर्ष का नेतृत्व किया था। शक्ति उन्हीं के हाथों में रही। औद्योगिक क्रान्ति के परिणाम स्वरूप उत्पादन की नई पद्धति पर विश्वास हो गया था। स्वतंत्र रहकर घर में काम करने वाला मजदूर अब कारखानेदार का नौकर बनकर काम करने लगा था। अपना गाँव छोड़कर वह नगरों में आ बसा था। वहां उसके आवास की व्यवस्था बहुत ही अधूरी थी। कारखाने में जिस ढंग से काम होता था, उसके कोई नियम नहीं थे। मजदूर असंगठित एवं दुर्बल था। वह शोषण, अन्याय और उत्पीड़न का शिकार बन गया था। राज्य की शक्ति जिनके हाथों में थी, वे भी उसी वर्ग में से थे, जो उनका शोषण कर रहे थे। अतः राज्य से कोई भी आशा नहीं थी।

इस अन्यायपूर्ण अवस्था के विरूद्ध विद्रोह तथा स्थिति में सुधार की भावना लेकर कई महापुरूष खड़े हुए। उन्होंने अपने आपको समाजवादी कहा। कार्ल मार्क्स भी इन समाजवादियों में से एक है। उसने विद्यमान अन्याय का विरोध करने के प्रयत्न में अर्थव्यवस्था तथा इतिहास का अध्ययन कर एक विश्लेषण प्रस्तुत किया। कार्ल मार्क्स की विवेचना के बाद समाजवाद एक वैज्ञानिक आधार पर खड़ा हो गया। बाद में समाजवादियों ने मार्क्स को माना हो या ना, किन्तु उनके विचारों पर उसकी छाप अवश्य है। ▪

(पं. दीनदयाल उपाध्याय लिखित एकात्म मानववाद पुस्तक से साभार)

▪ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने भाजपा सरकार के सफलतम एक वर्ष पूर्ण होने पर पितृपुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया।

▪ प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित की।

▪ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

▪ प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव-2024 का शुभारंभ किया।

▪ प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने संगठन पर्व की ग्वालियर-चंबल संभाग की बैठक को संबोधित किया।

▪ प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना की।

▪ प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने भाजपा अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को जन्मदिन की बधाई दी।

▪ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने झाबुआ, मंदसौर और आगर में भाजपा जिला कार्यालय का भूमिपूजन किया।

निवेशकों का बढ़ता विश्वास, क्षेत्रीय उद्योगों का संपूर्ण विकास

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

INVEST MADHYA PRADESH

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट

फरवरी 2025, भोपाल

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव

मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश की गति को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर क्षेत्रीय औद्योगिक विकास के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का श्रृंखलाबद्ध आयोजन किया जा रहा है। नये निवेश से क्षेत्रीय स्तर पर उद्योगों की उन्नति के साथ युवाओं के लिए रोज़गार के अवसरों की नई राहें खुल रही हैं।

उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलूरु, कोलकाता में हुए निवेशकों के साथ इंटरेक्टिव सत्रों में कुल 2 लाख 76 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनसे 3.28 लाख से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित होंगे

निवेशकों को विशेष सुविधाएं और नीतियां-

सरकार ने औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, निवेश प्रोत्साहन योजना और कस्टमाइज़ पैकेज जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं। नए निवेशकों को उद्योग मित्र नीतियों के साथ सरल और सुगम निवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है।

एक्सपोर्ट हब बनता मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रयासों से मध्यप्रदेश न सिर्फ औद्योगिक हब बन रहा है बल्कि हर क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। कनेक्टिविटी, उद्योग-अनुकूल नीतियां और मजबूत अधोसंरचना से मध्यप्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। औद्योगिक विकास के साथ-साथ निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि। पिछले वित्त वर्ष में 13,198 करोड़ रुपए के दाल उत्पादों का निर्यात। निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य : आने वाले तीन वर्षों में निर्यात को दोगुना करने का संकल्प, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी।

Website : invest.mp.gov.in

D1917/24